[श्री बी० पी० मौर्य]

नहीं किये गये, तो हमारे बाजुओं में भी बदला लेने की ताकत है और हम जा कर मौके पर बदला लेंगे, यह मैं कहना चाहता हूं। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक एक महीने के अन्दर अन्दर मुल्ज़मान गिरफ्तार होने ही चाहियें।

MR. SPEAKER: I will pass it on to the Minister concerned. We are completely at one with you. It is very shocking that such things should happen. It is only a few months back that a very beautiful statue of Gandhiji—a lot of money was spent on it—was put up in Amritsar and somebody did mischief and cut off its arm and the head. This tendency to spoil and destroy the statues of eminent people and our great leaders is highly condemnable. I think the Ministry of Home Affairs should take very serious action on it.

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर): अध्यक्ष महोदय, ऐसी घटना 14 तारीख को हुई और आज तक कोई पकड़ा न जाए यह बात समझ में नहीं आती।

MR. SPEAKER: I now pass on to the next item.

13.8 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS—(*contd.*)

MINISTRY OF AGRICULTURE—*contd.*

MR. SPEAKER: The House will now take up further discussion and voting on Demands for Grants under the control of the Ministry of Agriculture.

Shri Chandra Bhal Mani Tiwari was on his legs.

श्री चन्द्रभाल मणि तिवारी (बलरामपुर): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं कल बोल रहा था उसी विषय में फिर आ रहा हूं कि हम ने खेती के डेवलपमेंट पर अगर अपने पूर्ण साधनों से, सारे उपयोगी साधनों से कार्य आरम्भ नहीं किया तो देश की वह दुर्दशा भी अपने सामने देखने को मिलेगी जैसा कि आप को मालूम है कि रशिया में अपने प्रारम्भिक काल में, जब वह डेमोक्रेटिक शासन में आया, तो उसे 18 साल भोगनी पड़ी। उस इतिहास के दोहराने मे भारत का कल्याण नही होना है।

भारत की आबादी आज करीब 55 करोड़ है। यदि भारत की यह पौपुलेशन इस सुधार पर अपनी निगाह डालेगी, हमारे मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान देंगे तो शायद इसकी यह दुर्दशा नही होगी। अब मैं कुछ खास बातों पर आऊंगा। देहात मे और शहर मे कुछ भेद दिखाई पड़ते है। जैसा इन्सान शहर मे है वैसा ही इन्सान देहात में है, लेकिन दोनो के स्टैन्डर्ड आफ़ लिविंग मे अन्तर है। इस का कारण यह है कि हमारे देहात का विकास, देहात की प्रोग्रैस बिल्कुल रुकी हुई है। इसका क्या कारण है? क्या मंत्री महोदय ने कोई कम्पेरेटिव चार्ट तैयार नही किया? अगर तैयार किया है तो मैं चाहूंगा कि अपने उत्तर से उस पर रोशनी डालें। मैं उसके बारे में कुछ बुनियादी ज़रूरतों पर निगाह डालने की कोशिश करूंगा। जो शहरों को सुविधायें [illegible] न की गयी हैं, जैसे सड़कों की बिजली [illegible] वही सुविधायें देहात में भी प्रदान करनी [illegible] हियें ताकि वहां भी आदमी ऐम्लाइमेंट हो जायें और अपने को देखें कि वह भी

शहर के बराबर हो जायें । देहात का हर आदमी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वह आप के संविधान को समझ सके । आखिर इस का कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि आज वहां एजुकेशन नहीं है । एजुकेशन के सम्बन्ध में मैंने देखा है कि गांवों में स्कूल नहीं हैं, और स्कूल भी हैं तो टीचर्स नहीं हैं । मैं मानता हूं कि यह स्टेट की जिम्मेदारी है, लेकिन केन्द्रीय सरकार को भी इस सम्बन्ध में उन को लिखना चाहिये उन की तम्बीह करनी चाहिये ताकि स्कूलों में आज जो दुर्दशा है वह ठीक हो और हमारे बच्चे पढ़ें और पढ कर हमारे देश के अच्छे नागरिक बन सकें तथा अच्छी खेती कर सकें ।

कमजोर वर्ग के लिये ऐग्रीकल्चर लोन देने की व्यवस्था की गई है । हमारे यहां लीड बैंक खोले गये है । लीड बैंकों मे जो पुस्तके अथवा हैंडबुक दी गई है वह अंग्रेजी में है । भला आप बतलाइये कि हिन्दी समझने वाले तो वहां है नही, अंग्रेजी समझने की शक्ति किस मे है ? क्या मैं मंत्री महोदय से उम्मीद करूं कि इस स्थिति पर विचार किया जायेगा और वहां हिन्दी की हैंडबुक्स भेजी जायेंगी ?

स्टेट सरकारों ने जमीन की सीलिंग कर दी है जो 18 एकड से ले कर 27 एकड़ तक और 10 एकड़ से ले कर 18 एकड़ तक है । अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग नियम हैं । अब लोगों के पास जमीनें अधिक थीं तब उन को जोतने के लिये लोग बड़े बड़े ट्रैक्टर खरीद सकते थे । आज ट्रैक्टर्स की कीमतें कहीं भी 25,000 रुपये से कम नजर नहीं आती हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज 10 और 18 एकड़ तक का काश्तकार 25,000 रुपये का ट्रैक्टर खरीद सकता है ? इस के लिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस पर ध्यान दें और देश में 10 से 15 हजार रुपये तक के ट्रैक्टर बनवायें या बाहर से मंगवायें । यदि ऐसा प्रबन्ध नहीं होता है तो सरकार खुद साल दो साल के अन्दर इतना भारी नुकसान उठायेगी कि अभी जो गल्ला उस को इस साल मगाना पड़ रहा है, दैवी प्रकोप के कारण या बिजली की कमी के कारण, हो सकता है वह और भी बढ जाए, और उतना ही मंगाना पड़े जितना हम पहले मंगाया करते थे ।

मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां आज जो अच्छे किस्म का बीज दिया जाता है, जिस की भूमिका श्री सुब्रह्मण्यम ने अपने पीरियड में बड़ी कामयाबी के साथ बनाई थी, शायद उस की गति आज धीमी हो गई है । इस का कारण मैं यह समझता हूं कि हमारे मंत्री महोदय अपनी वृद्धावस्था के कारण शायद इस ओर अधिक ध्यान नहीं दे पा रहे है । लेकिन हमारे और मंत्रीगण हैं, मैं समझता हूं वह इस मे अपना सक्रिय हाथ डालेंगे । मैंने देखा कि पिछले पांच सात सालों से कोई नई वेराइटी की चीज सामने नहीं आ रही है । हमारे यहां कृषि अनुसन्धान के बहुत कम केन्द्र हैं । जैसे उत्तर प्रदेश में केवल दो हैं । एक तो पन्त नगर में

[श्री चन्द्र भाल मनी तिवारी]

है और एक कानपुर में है । पन्त नगर पूरे उत्तर प्रदेश की आवश्यकता को पूरा नही कर सकता । इस के केन्द्र बनाये जाने की बहुत आवश्यकता है । हमारे यहा की पापुलेशन की 70 फीसदी जनसख्या खेती करती है । इस के लिये ज्यादा से ज्यादा सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता है ।

हमारे देश की जो वन सम्पत्ति है उस की रक्षा करने का उत्तरदायित्व हमारे मत्री महोदय पर है लेकिन वह पूरा नही हो पाता है । इस से हमारे देश मे पानी कम मिलने लगा है । पानी कम मिलने से फसलो की क्षति होती है । मैं समझता हू कि मत्री महोदय इस स्थिति को सुधारेगे ।

कृषि ऋणो के सम्बन्ध मे बहुत सी गडबडिया नजर आती हैं । हमारे बैंक लोन देते हैं, लेकिन किसानो को बहुत परेशान करते हैं । जब मेरे जैसे समद् सदस्य को तकलीफ उठानी पडती है तो भला आप सोचे कि जो हमारे छोटे काश्तकार है, जो बिल्कुल ही अन्डेन्ड हैं, अनपढ हैं, उन की क्या क्या दुर्गति नही होती होगी । क्या मत्री महोदय कोई सर्कुलर बैको को भेजेगे कि किसानो को जो असुविधाये हो रही है उन को जल्दी से दूर करे । जो हमारे लीड बैंक खोले गये हैं जब हम उन की प्रगति के बारे मे सोचते हैं तो वह हमको ० प्रतिशत मालूम पडती हैं । हमारे ऐन्थनी साहब, इस को नही मानते हैं ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिदेशित-आग्ल भारतीय) मानते है ।

श्री चन्द्र भाल मनी तिवारी : अगर मानते हैं तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं ।

हमारे यहा कुछ सोसायटियां हैं कोआपरेटिव की जो लड डेवेलपमेंट का काम करती है । उन सब में बडा भ्रष्टाचार है । हो सकता है कि गुजरात में सोसायटिया अच्छी हो, जैसी कि हम तारीफ सुना करते है, हमारे श्री शिन्दे उन की बडी तारीफ करते हैं, लेकिन देश के और क्षेत्रो मे यह सोसायटिया ठीक काम नही करती । हम ने उत्तर प्रदेश की बहुत सी सोसायटियो को देखा है जहा करोडो रुपयो के घोटाले हुए और कमेज भी दर्ज हुए है । मुकदमे भी वहा होने जा रहे है । जब तक इस घाटाले को दूर नही किया जायेगा तब तक मैं नही मानता कि उन के कामा मे सुधार हो सकता है ।

मेरा एक सुझाव है । गावो मे किसानो के बीच मे लीडरशिप की आवश्यकता है । अगर वह लीडरशिप हर सोसायटी मे फार्म होती है तो उन का कन्टेक्ट हो सकता है । स्टेट से, उन का कान्टेक्ट हो सकता है केन्द्र से । अगर यह सुविधा प्रदान की गई तो आज जो भी असुविधाये उनको है उन को दूर किया जा सकता है और उन लीडरो के द्वारा सारे साधन उन तक पहुचाये जा सकते है

हमारे यहा जमीन की सीलिंग कर दी गई है, मैक्सिमम सीलिंग कर दी गई है । इस से मुझे भय हो रहा है कि कोई भी बेहतर

का आदमी किसी असेम्बली या पार्लियामेंट के चुनाव में भाग नहीं ले सकेगा । इस का कारण यह है कि शहरों की स्थिति रोज व रोज ठीक होती जा रही है, उनकी शक्ति बढ़ती जा रही है और हमारे देहातों की शक्ति घटती जा रही है । विकेन्द्रीकरण नही हुआ है । सारी शक्ति केन्द्रित होती जा रही है । आज शहरो का स्तर बढ़ता जा रहा है और उसके मुकाबले में देहातो का स्तर नीचे गिरता जा रहा है । इस तरह से हमारे देहातों का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, जिस की बहुत बडी आवश्यकता है । इसके न होने पर हमारे देहात सफर करेंगे । इसके सुधार के लिये बहुत ही आवश्यक है कि कोई विवेकपूर्ण कदम मन्त्री महोदय उठाये ।

हमारे देश मे बहुत सा जमीन का हिस्सा रेगिस्तानी है या बजर पडा हुआ है । मैंने हरियाणा मे देखा कि वहा की सरकार ने करीब करीब अपने पूरे रेगिस्तानी हिस्से को पम्पो के द्वारा उपजाऊ बनाने की कोशिश की है और निरन्तर प्रयोग कर रही है ।

क्या यह प्रोग्राम देशव्यापी आधार पर नही चल सकता है ? झासी और बुन्देलखड के इलाके में, वाटरलागिंग से नष्ट हो रहे इलाके मे, क्या वह प्रोग्राम नही चल सकता है ? क्या इस प्रोग्राम को देश के कोने कोने मे लागू नहीं किया जा सकता है ? मैं समझता हू कि ऐसा किया जा सकता है ? यदि केवल राजस्थान की सहायता दी जाये, तो वह पूरे देश को सपोर्ट कर सकता है ।

हमें खेती पर क्या क्या प्रयोग करने हैं, इस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए । इसके लिए हमें नई वैरायटी के बीज, खाद और पानी चाहिए । यद्यपि सिंचाई का विषय मौजूदा मन्त्री महोदय के डिपार्टमेंट में नही है, लेकिन वह खेती के लिए बहुत आवश्यक है । मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय मेरे सुझाव को डा० के० एल० राव तक पहुचा दें ।

जब हमारे देश मे सरफेस वाटर बहुत है, तो फिर ग्राउड वाटर की खोज क्यो हो रही है ? अगर हम अपने सरफेस वाटर का पूरी तरह उपयोग करे, तो देश का एक इच भी असिंचित नही रह सकता है । पिछले साल हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, श्री परमार, से मेरी बात हुई । उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश मे बाध बनाया जाये, तो हम उत्तरी भारत को इतना पानी दे सकते है कि एक इच जमीन भी असिंचित न रहे । जमीन के नीचे से पानी प्राप्त करने की कोशिश करने के बजाये जमीन के ऊपर बाध क्यो नही बनाए जाते हैं और पानी का स्टोरेज क्यो नही किया जाता है ? ग्राउड वाटर के सम्बन्ध मे कई प्रकार की परेशानिया होती है । उनके बारे मे सोचने के बजाये मन्त्री महोदय सरफेस वाटर की तरफ क्यो नही ध्यान देते है ?

मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इन बुनियादी जरूरतों की तरफ ध्यान देकर खेती की समस्याओं को हल करेंगे ।

श्री बरकातराम सिंह (होशियारपुर) अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की इक्तसादी जिन्दगी मे जराअत का एक बहुत बडा हिस्सा है। हमारे मुल्क मे ज्यादातर खेती पानी मिलने पर होती है। मैं इस बारे मे कुछ और ज्यादा आगे चल कर कहूगा। इस हाउस मे पानी पर बहुत बहस हो चुकी है। लेकिन अगर हमारे इरिगेशन मिनिस्टर साहब यहा होते, तो मैं बताता कि एग्रीकल्चर और इरिगेशन मे कितने कोआर्डिनेशन की जरूरत है।

आज हमारे यहा नये ढग की खेती शुरू हुई है। बहुत पुराने जमाने से, जब कि फ्यूडल सिस्टम कायम था, बडी जमीनो पर बहुत कम पैदावार होती थी। लेकिन इस साइंटिफिक एज मे नये इम्प्लीमेंट्स और नये इनपुट्स आये है, जिनकी वजह से हमारी पैदावार मे इजाफा हुआ है और वह इजाफा होता चला गया है।

13.24 hrs.

[MR DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

मैं यह समझता हू कि किसी का यह कहना दुरुस्त नही है कि हम अपने लिए सारे अनाज का इम्पोर्ट करते है। मेरे पास इस बारे मे स्टैटिस्टिक्स मौजूद है। 1966 मे 10 34 मिलियन टन अनाज इम्पोर्ट किया गया, जो कि 1972 मे घट कर आधा मिलियन रह गया। यह ठीक है कि इस साल हमने दो मिलियन टन अनाज बाहर से मगाया है, लेकिन उसकी वजह है। दो साल पहले हमारे मुल्क मे बहुत से लोग यह कहते थे कि हमें फौरन जग के लिए तैयार होना चाहिए और बगला देश को फौरन मान्यता देनी चाहिए। हमने बगला देश को मान्यता दी और उसी वक्त जग हुई, जिस की वजह से हमे कई मुश्किलात का सामना करना पडा जो लोग उस वक्त बडे जोश से कहते थे कि हमे जग करनी चाहिए और बगलादेश को मान्यता देनी चाहिए, लेकिन जब हमने वह जग जीत ली और बगला देश बन गया, तो यही लोग कहते है कि अनाज की कमी क्यो हुई है। उन को पता है कि जो इलाका पाकिस्तान से काट कर अलग देश बन गया है और हमारा मुआवन बन रहा है, सिर्फ फौजी नुक्ता-ए-नजर से उसकी मदद करने की नही, बल्कि अनाज देकर उसको कायम रखने की जरूरत थी। जब बगलादेश की जरूरत को पूरा किया गया तो हमारे भडार मे कमी होना लाजिमी था।

लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हू कि सिर्फ हिन्दुस्तान मे ही नही, बल्कि सारे ससार मे ड्राउट, खुश्कसाली, हुई है। ऐसे कुछ देशो के अनाज के भडार भी खाली हुए, जिनके बारे म हम कहते है कि वे हमसे बहुत आगे बढे हुए है। हमने पढा है कि दो साल पहले बारिश भी कम हुई और सोवियत रूस म बर्फ भी कम पडी, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहा पानी कम मिला। पिछले साल से पहले सोवियत रूस की अनाज की पैदावार 190 मिलियन टन थी, लेकिन ड्राउट और कम पानी मिलने की वजह से पिछले सीजन मे उसकी पैदावार 170 मिलियन टन हुई।

इसलिए सोवियत रूस ने अपने भंडार को पूरा करने के लिए बाहर से अनाज मंगाया है।

सी० पी० एम० के मेरे दोस्त ने कल बहुत कुछ कहा। मैं इस बात में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं कि चीन में कल्चरल रेवोल्यूशन भी अनाज की पैदावार पर असर-अंदाज हुआ है और वहां की पोलीटिकल सिचुएशन ने इकनसादी हालत को खराब किया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वहां भी ड्राउट हुआ है और उसकी वजह से वहां की पैदावार में कमी हुई है। पिछले साल चीन की पैदावार 250 मिलियन टन थी, जब कि इस साल तकरीबन 245 मिलियन टन हुई। यह हालत उस देश की है, जो कहता है कि वह सब से आगे है और कम्युनिज्म की आखिरी तस्वीर है, लेकिन हमारे दोस्त इसको सपोर्ट करते हैं और उसकी मिसाल देते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि चीन ने कैनेडा से 3 3 मिलियन टन, यू० एस० ए० से 0 5 मिलियन टन और 0 3 मिलियन टन और आस्ट्रेलिया से 1 मिलियन टन, इस तरह कुल 5 मिलियन टन के करीब, अनाज मंगाया है। जैसा कि मैंने बताया है, उसकी वजह यह है कि वहां पर ड्राउट पड़ा और खुश्कसाली हुई।

हमारे देश में मुख्तलिफ़ सूबों में जो भयानक ड्राउट पड़ा है, उसकी एक मिसाल यह है कि महाराष्ट्र में मवेशियों के लिए मौलेसिज से बना हुआ फ़ीड मुहैया किया गया है और इस बात के लिए कानूनी बन्दोबस्त करना पड़ा है कि पक्की खोलों में न दिया जाये, ताकि वह लोगों को पीने के लिए मिल सके। ऐसी हालत में से हम गुजर रहे हैं! इस सिलसिले में हमारी सरकार ने जो काम किया है, हमें उसकी दाद देनी चाहिए। पाकिस्तान में भी बहुत गन्दुम पैदा होता है, लेकिन उसने भी 1 4 मिलियन टन अनाज बाहर से मंगाया है। सिर्फ़ हम ही बाहर से अनाज मंगाने वाले नहीं है। हमारा अनाज का इम्पार्ट घट कर आधा टन रह गया था। अगर नार्मल हालत रहती और वक्त पर बारिश हो जाती, तो हम उसको भी खत्म कर देते।

हम को गवर्नमेंट को दाद देनी चाहिए कि उसने इन मुश्किलात के बावजूद प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इमर्जेंसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत लांग-टर्म मेजर्ज के लिए 152 करोड़ रुपया दिया है। उसने शार्ट-टर्म प्रोग्राम के लिए पहले 6 0 करोड़ रुपया दिया था, लेकिन इस साल उसको बढ़ा कर 100 करोड़ रुपये कर दिया है, ताकि लोग अपनी खेती को बढ़ाने के लिए जल्दी काम कर सकें। गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रुपये की कमी नहीं होने दी है। उस रुपये का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ स्टेट गवर्नमेंट्स ने कैसे किया है, उसके बारे में मुझे इख्तलाफ़ है। उसका जिक्र करना कोई माकूल बात नहीं है। लेकिन क्योंकि इनकी तरफ से जो चला गया नीचे उसका इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक हुआ है या किस हद तक नहीं हुआ यह तो वह जानें, मैं इनको सिर्फ इतना अर्ज करता हूं कि जरा पुल अप कीजिये उनको। बस और कुछ नहीं कहना चाहता।

[श्री दरबारा सिंह]

ड्राई फार्मिंग का भी काफी अच्छा तजर्बा इन्होंने किया। उसको हाई ईल्डिंग वैराइटी ज्वार की बाजरे की हुई है। ठीक है कि कहीं कीड़े उस को खा जाते हैं। लेकिन उसको भी रोकने की कोशिश है। काफी कुछ यह कोर्स ग्रेन भी पानी न मिलने की वजह से ज्यादा हो नहीं सका है। पल्सेज और दूसरी चीजें जो हैं जिनको हम जरूरियात जिन्दगी समझते हैं उनकी कमी वाकई हुई है और इस सब की एक ही वजह है कि पानी की कमी हुई।

इसके साथ साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इंटेंसिव कल्टीवेशन हो सकती है। लेकिन उसके लिए पानी चाहिए। आज भी इस जमीन में यह ताकत है कि टू टू थ्री टाइम्स ए ईयर वह क्राप दे सकती है, ऐसे जराये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सोयल कंजर्वेशन करने की जरूरत है। मैं एक अर्ज और करना चाहता हूं, उसके मिनिस्टर साहब यहां हैं नहीं, शेलो ट्यूबवेल्स जो हैं, ठीक है बिजली की कमी हुई, बारिश नहीं हुई तो हमारे रिजर्वायर भरे नहीं, आगे पानी नहीं निकला, न खेती को गया, न जनरेशन हुई पावर की और पावर नहीं मिला तो ट्यूब वेल नहीं चले। लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा जेनेरेटर जितने भी मंगवाए जा सकते हैं फौरी तौर पर उनका इन्तजाम करना चाहिए क्योंकि शार्ट टर्म की स्कीम्स में ज्यादा काम करने की जरूरत है बनिस्बत इसके कि 50 साला स्कीम पानी की कहीं दे दी जाय कि गंगा का पानी कावेरी में जायगा। यह पचास साला स्कीम आप मुझे मत दीजिए। हम तो फौरी तौर पर चाहते हैं और उसके लिए जो भी इन्तजाम आपने किए हैं उनको लागू कीजिए।

पंजाब शुरू से 68-69 से पैदावार का 40.5 प्रतिशत सेंटर के भंडार को देता रहा है और इस साल 60 परसेंट से ऊपर आपके भण्डार में आएगा।

श्री राम सहाय पाण्डेय (राजनंदगांव) : पंजाब का ही भरोसा है।

श्री दरबारा सिंह : अब मैं क्या कहूं आपको ? भरोसा रखेंगे तो कुछ हो जायगा।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): पंजाब पर पूरा भरोसा है।

श्री दरबारा सिंह : बात यह है कि हम यह चाहते हैं कि ऐसा हो। लेकिन एक बात याद रखिये, हमेशा के लिये पंजाब ऐग्रीकल्चर सूबा नहीं रहना चाहता। वह भी कामर्शियल क्राप उगाना चाहता है। इसलिये हर एक स्टेट को सेल्फ एफिसिएंसी की ओर ध्यान देना होगा। क्यों न जहां अनाज हो सकता है वहां उसके लिये कोशिश अपने अपने सूबों में करें ? हम पत्थर में नहीं चाहते कि वहां अनाज पैदा होगा लेकिन उनके वहां जो जमीन काबिले काश्त है वहां क्यों न अनाज पैदा किया जाय ? लेकिन वह एक अलाहिदा सवाल है, उसके बारे में मैं कम कहूंगा।

दस हजार ट्यूब वैल और एक हजार डीप ट्यूब वैल्स के लिये जो स्कीम आपको भेजी गई है और आपसे यह कहा

है कि इससे दो लाख टन फालतू व्हीट और एक लाख टन राइस हम देंगे । तो इसको आपको निकालना चाहिये । हुआ क्या कि गैस टर्बाइन के लिये आर्डर दे दिया । आपकी सरकार ने उसको रोका है । तो निकालिये उसको । गैस टर्बाइन अगर हमे मिल जाता है तो हम फौरी तौर पर आपको अश्योर करते है कि पजाब 60 नही 70 परसेंट अनाज देने के लिये तैयार हो जायगा । इसलिये यह थोडी सी बात मैंने पजाब की भी की है क्योकि आपका ज्यादा से ज्यादा अनाज पजाब और हरियाने से आता है । हरियाने से 30 परसेंट आता है, यू० पी० मे 15 परसेंट आता है । यह सारी फिगर्स मौजूद है । इसलिये उसके बारे मे ज्यादा जिक्र नही करता । ... (व्यवधान) यह घंटी कुछ जल्दी बज गयी ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the hon. Member should try to conclude I have been requested by his Whip to give fifteen minutes to the first two....

श्री दरबारा सिंह 15 मिनट अभी हुए नही है ।

MR DEPUTY-SPEAKER: Speakers and ten minutes to the others from the Congress Party.

SHRI DARBARA SINGH: It is not yet 15 minutes.

MR DEPUTY-SPEAKER: It is going to be 15 minutes. I am just giving the warning.

SHRI ANNASAHEB P SHINDE: He is a very senior Member of our party.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If I start making that kind of discrimination, then I would be in for trouble.

श्री दरबारा सिंह मैं इरीगेशन के बारे मे अर्ज करना चाहता हू कि हमारी टोटल इरीगेशन 19.9 प्रतिशत है और सारी इरीगेशन का 1/7 हिस्सा हम इस्तेमाल करते है । 6/7 हिस्सा अभी तक ऐसे ही पडा है । इस के बारे मे मे कृषि मत्री या और दोस्तों से यह अर्ज करूगा कि आप इस बात के ऊपर गौर करे, यह बात गलत है कि इरीगेशन अपना पार्ट अलहिदा लिये जाय और उसका कोआर्डिनेशन ऐग्रीकल्चर के साथ कतई न हो । इन मुहकमा मे कोआर्डिनेशन बहुत जरूरी है । यह नही कि वह पचास साल की स्कीम बनाये और आप पैदावार बढाना चाहते है कल, तो पचास साल की स्कीम से तो कल अनाज ज्यादा पैदा नही होगा । इसलिये छोटी छोटी टर्म की योजनाये शार्टेज मे ज्यादा फायदा दे सकता है, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाय ।

न्यूक्लीयर पावर प्रोजेक्ट के बारे म आप का कहना है कि यह कोल माइन्स से 500 मील दूर होना चाहिये । यह आपके प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन की और दूसरो की रिपोर्ट है । तो दो आपने दिये है एक यू० पी० मे और, एक जगह और । हम यह नही कहते कि हम हिस्सेदार बनना चाहते है । वैसे बनना चाहिये । जो राजस्थान मे है उसका कुछ हिस्सा हमे मिलना चाहिये । लेकिन अगर हरियाने और पजाब के लिये आप इन न्यूक्लीयर प्रोजेक्ट दें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि पजाब 500 मील दूर है उस इलाके से और पाच सौ मील की दूरी आप

[श्री दरबारा सिंह]

चाहते हैं कोल माइन्स से। कोल माइन्स जहा है वहा थर्मल प्लाट लग सकता है। न्यूक्लीयर प्लाट उससे दूर होना चाहिये। इसलिये पजाब जो उतनी दूरी पर है उसके लिये ऐग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को कहना चाहिये कि न्यूक्लीयर प्लाट उसके लिये दिया जाय।

वाटर डिस्प्यूट भी आपके पास है। यह वाटर डिस्प्यूट तो आप खत्म करे। एक जोनल कान्फ्रेंस हुई थी तो उसमे हमने बहुत जोरो से कहा था कि हमारा मिशन है कि थीम डेम का फैसला होना चाहिये। आज उसका फैसला नही हो पाता कि यह जमीन किसकी है किसके हिस्से मे यह आता है पानी किसका होगा किसका कितना शेयर होगा मै कहना चाहता हू कि यह जमीन न मेरी है न आपकी है। जमीन हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान के सूबे है। यह क्या मिल कर उसका तय नही कर सकते कि पानी की जरूरत किसको है, पावर की जरूरत किसको है, यह अपने अपने उसके बाप दादा बने हुए है यह बात आपकी तोडनी चाहिये। तो इसके लिये आप कुछ ध्यान दीजिये।

फ्लड कट्रोल मे 149 करोड का आप को नुकसान हुआ। पावरटी दूर करने की स्कीमे आप बनाते हैं। करोडहा रुपया खर्च होता है। आप एक दफा उस की स्कीमे उन सूबो मे लें जो सूबे अभी तक फ्लड कट्रोल करने मे नाकामयाब रहे हैं। उनकी मदद तो आप कर रहे हैं। आप उन लोगो की मदद कर रहे है। आप सरकार की मदद कीजिए। जो सूबे की सरकारे हैं वह कुछ नही कर पाई है। सिल्टिंग हो जाता है पानी बाहर बह जाता है। (व्यवधान)

लैंड सीलिंग के बारे मे मैं अर्ज करना चाहता हू। आप ने एक हदबन्दी मकर्रर की। हदबन्दी हो गई। 30 एकड से किसी जगह पर 18 एकड हो गई। उस के लिए अगर आप ने छोटा यूनिट बनाया है और आप कहते हैं कि उस घेरे मे वह वायबिल बन सकता है तो उस के लिए स्माल ट्रैक्टर्स की बहुत जरूरत हैं। मैं नही मानता कि 20 हजार का ट्रैक्टर हो। ट्रैक्टर की कीमत दस हजार में कम होनी चाहिए। क्या कि जमीन वाला उस मे से पैदा कर के उस की कीमत दे सकता हैं। बाहर से कही न० 2 का पैसा उस के पास नही आने का हैं। इसलिए स्माल ट्रैक्टर बनाए जाने चाहिए ताकि वह उस के घर मे आ सके। अपने खेत पर वह उस से काम कर सके। यह नही हो कि वह जमीन छोडता जाय और पैदावार कम हो।

दूसरे आप को सर्विस स्टेशन्स बनाने चाहिए। सरकार सर्विस स्टेशन्स बनाए जिस से कि गवर्नमेंट लीज आउट कर लोगो को किराये पर दे। इस के अलावा इनपुट्स वहा अवेलेबल हो ऐसे सर्विस स्टेशन्स बनाए जाने चाहिए। सूबो मे ऐसा चलता है लेकिन वह करते कुछ नही हैं इस के लिए।

बैंक्स का रुपया आप दे रहे हैं। मुझे यह पता नहीं, आप इस बात को वाजह

करेंगे कि आप ने क्रेश प्रोग्राम सन् 73–74 में खत्म कर दिए या चालू रखे ? लेकिन बैंक्स का जो रुपया है, काफी मर्केन्टेबिलिटी है मगर उस में सुधार करना होगा क्यों कि बैंक के अन्दर काम करने वाले जो हैं वह गरीबों का काम निकलने नहीं देते उस का पैटर्न आप को बदलने की जरूरत हैं। उस के ऊपर कमेटी बनाने की जरूरत हैं और विजिलेंस रखने की जरूरत हैं। वरना पैसा तो उन्हीं बड़े बड़े आदमियों को ही जाता हैं। रिक्शेवाले को और छोटे लोगों को नहीं जाता, दस पन्द्रह एकड़ वालों को नहीं जाता। दूसरे लोगों को जाता है। इसलिए इस का कोई इन्तजाम कीजिए।

मैं एक बात अर्ज करने के बाद बैठ जाता हूं। 1961 में जो पोपुलेशन थी और उस के बाद 1971 में जो पोपुलेशन हैं, उस के हिसाब से आप पर कैपिटा इन्कम को बढ़ाते रहे. आबादी बढ़ गई, इस लिये इन्कम भी बढ़ गई। मैं इस की डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो फैक्टर्स आपने रखें हैं, मैं चाहता हूं कि उस का नये ढंग से नया सर्वे करायें ताकि पता चले कि आज जो सरकारें यह कह रही हैं कि हमारे यहां 300 हो गया है, 400 हो गया हैं—वैसे तो कहते हैं कि हमारे लोग गरीब हो गये हैं, लेकिन साथ में अपनी अमीरी की दास्तान भी सुनाते हैं, आप इस का नये सिरे से सर्वे कीजिये।

पंचायती राज के बारे में भी कहना चाहता था—इस में काफी काम करने की जरूरत हैं, स्टेटों में इस सिलसिले में डीसेन्ट्रला-इजेशन के बजाय सैन्ट्रलाइज कर रहे हैं, इस लिये डीसैन्ट्रलाइजेशन की तरफ तवज्जह दी जाय।

श्री मारकण्ड राय (घोसी) : मान्यवर, कृषि मन्त्रालय का अमजनोंमा नाकामयाबियों की करुण कहानी रहा है। कोई भी इस बात से नतीजा निकाल सकता है कि 25 सालों के बाद हमारी यह स्थिति है कि अगर एक बार सूखा पड़ जाय तो हम उस को सम्भाल नहीं सकते और हमारी पूरी अर्थ व्यवस्था, कृषि व्यवस्था का अन्जर पंजर ढीला पड़ जाता हैं। एक बार फसल कमजोर हो जाये तो हम दूसरे देशों के मोहताज हो जाते हैं। जिस बात का गर्व दो साल पहले किया था कि हम खाद्यान्न समस्या में आत्मनिर्भर हो गये हैं, वह गर्व समाप्त हो जाता हैं, दूसरे देशों से अन्न मंगाने के लिये विवश हो जाते हैं। एक झटका भी बरदाश्त करने की शक्ति 25 सालों की आजादी के बाद भी प्राप्त नहीं हुई—इससे बड़ा सुबूत हमारी नाकामयाबी का और क्या हो सकता है ? कृषि मन्त्रालय अपने लक्ष्यों में बिलकुल सफल नहीं हुआ।

किसी भी जनतान्त्रिक व्यवस्था को कायम करने के लिये सामन्तशाही व्यवस्था की समाप्ति बहुत जरूरी होती हैं। भूमि समस्या ही वास्तव में हमारे देश की मुख्य समस्या है और उस का आधार है कि जमीन का बटवारा सम्यक रूप से किया जाय। यह कम शर्म की बात नहीं है कि 25 सालों के अन्दर भी हम सब से पहला काम अभी तक नहीं कर सके। इस में हमें चीन का उदाहरण लेना चाहिये। जो काम 5 वर्ष में यानी 1947 की आजादी के बाद 1952 में हो

[श्री शारखंडे राय]

जाना चाहिये था—क्रांतिकारी उग्र भूमि-सुधार की सम्पूर्णता—वह आज तक नही हुई। जब कि यह काम आज भी उतना ही जरूरी है जितना पहले थी। काग्रेस सरकारे पूरे देश मे फैली हुई थी—लेकिन असफल हो गई। उस के बाद विनोबा जी इस काम के लिये उठे, उन्होने लक्ष्य बनाया कि पाच करोड एकड भूमि हिन्दुस्तान से वे दान मागगे और इस समस्या का समाधान करेगे, लेकिन, मान्यवर, वह बात भी सफल नही हुई और राज्य की सहायता के बिना विनोबा जी का आन्दोलन भी पूरी तरह से असफल हो गया और उन्हें हार कर बैठ जाना पडा। वे केवल 41 लाख 76 हजार एकड जमीन ही प्राप्त कर सके, जिस मे 18 लाख एकड जमीन बिल्कुल बेकार थी, किसी काम के लायक नही थी। बहुत सी ऐसी जमीन भी थी, जिस का पता ही नही कि वह जमीन कहा हैं, आसमान से हैं या रसातल मे हैं। इसी से ऊब कर भूतपूर्व खाद्य मन्त्री बाबू जगजीवन राम जी ने एक बार कहा था—उन्हें तो ऊबड खाबड भूमि ही मिलती हैं, कही कही तो ऐसी भूमि दी गई जिस का पता ही नही चल पाया कि वह कहा है।

इस तरह से काग्रेस सरकारे असफल हुई, विनोबा जी का आन्दोलन पूरी तरह से असफल हुआ—लेकिन काम होना बहुत जरूरी है। हमारे देश की राष्ट्रीय आय का करीब करीब 50 फीसदी खेती मे आता हैं, जब कि बहुत से दूसरे देशो से कृषि आय का प्रतिशत उनकी राष्ट्रीय आय मे बहुत कम हैं, इगलैण्ड मे 5 फीसदी हैं, जापान मे 1 फीसदी हैं। इस लिये जब तक हम कृषि की नीव को मजबूत नही करेगे, हमारे उद्योगो का भी विकास नही होगा—यह जड़ है, आधारशिला है, सुपर स्ट्रक्चर का, औद्योगीकरण का। इस लिये मैं सब से पहली बात यह कहूगा कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारो के साथ जितनी सख्ती सम्भव हो, उतनी सख्ती कर के, क्रान्तिकारी भूमिसुधारो के लिये आगे बढे। मन्त्री जी गरीबी हटाने की बात करते है, लेकिन गरीबी कम करने का सब से पहला और आसान तरीका जमीन का बटवारा है। मेरे पास जमीन नही है—मुझे अगर पाच एकड जमीन मिल जाये जो अच्छी हो तथा थोडे साधन मुहिया कर दिये जाय तो एक फसल के बाद हम को और हमारे बाल बच्चो को हल्वा पूडो या मुर्गे मसल्लम तो नही लेकिन रोटी दाल मिल सकती है। इस लिये गरीबी कम करने के वास्ते अकिचन और भूमिहीन लोगो को रोटी दाल देन का सबसे पहला तरीका है—जमीन का बटवारा—लेकिन उस में भी यह सरकार पूरी तरह से असफल हुई हैं।

आज कल प्रधान मन्त्री जी देश के विभिन्न प्रदेशो में और खास कर उत्तर प्रदेश मे भाषण करती फिर रही है—लेकिन कोई लक्ष्य सामने नही है। आज कल जोर कृषि और लघु उद्योगों पर है, उस के पहले बडी इन्डस्ट्रीज पर जोर था—लगता है कि कोई दिशा सामने नही है, कोई लक्ष्य स्पष्ट नही है, दिमागो में भ्रम है। जब जो चीज मुह से निकल जाय, जब जिससे फायदा दिखाई पडे, स्टन्ट के रूप में उस को ले लिया जाय लेकिन कोई स्पष्ट रूप-रेखा मालूम नही पडती। अभी इन्दिरा जी ने रायबरेली के भाषण में कहा है कि भूमि सुधार में जो भी

अड़चन डालेंगे, चाहे वे उन की पार्टी के भी हों, सरकारी अधिकारी हों, उन के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। मैं धमकियां सुनते सुनते कांग्रेस वाले भी हंस देते हैं, अधिकारी तो बरसरे-इक्तदार, मुल्क के मालिक हैं ही, उन की क्या बात है।

18 परसेंट जमीन हमारे यहां वैस्ट-लैण्ड है। अमरीकन एक्सपर्ट कमेटी ने इस बात का आग्रह किया था कि इस 18 फीसदी जमीन का काफी हिस्सा खेती में लाया जा सकता है, कम से कम फौरस्ट्री के लिये, घास पैदा करने के लिये तो उस का इस्तेमाल हो ही सकता है। प० जवाहरलाल नेहरू ने भी 1959 में नागपुर कांग्रेस के बाद कहा था कि लैण्ड रिफार्म हमारा 'आर्टिकल आफ फेथ" है। जोड़िये—कितने वर्ष हो गये 1959 के बाद, आज तक कार्यान्वित नही हुआ, चरितार्थ नही हो सका—वह सपना आज भी अधूरा है।

हमारे देश में, मान्यवर, 3 करोड़ से ज्यादा भूमिहीन खेतमजदूर हैं। क्या इन को रोटी-दाल का सहारा दिये बिना किसी समाज की कल्पना की जा सकती है। समाजवाद की बात तो छोड़ दीजिये, वह तो कायम ही नही हो सका, किसी भी बुजुआ पार्टी की सरकार समाजवाद कायम नहीं किया करती, सोशलिज्म की फिलास्फी तो छोड़ दीजिये, लेकिन रैडिकल बुर्जुवा रिफार्म किये बिना भी क्या 3 करोड व्यक्तियों को हम रोटी दे सकते हैं? नही दे सकते। इन को रोटी दिये बिना गरीबी हटाओ के नारे की बात छोड़ दीजिये, एक तिल भी गरीबी कम करने की कल्पना नही कर सकते।

हमारे देश में बड़े बडे सामन्ती प्रेत हैं—जरा उन को मुलाहिजा फरमाइये। मैं बिहार से शुरू करता हूं—टाटा की जमीदारी खत्म करने का फैसला हो गया है, लेकिन अमल नही हो रहा है। चम्पारन, सहरसा मधुबनी, दरभगा और दूसरे जिलों में जबरदस्त खेत मजदूरो के आन्दोलन चल रहे हैं, हजारो जमीन सम्बन्धी केसेज उन पर चल रहे हैं—क्या यह सम्भव नही है कि सरकार उन के मुकदमे फी कराये, उन खेत-मजदूरो को मदद दे। बैंको से ऋण मिलने की कोई सुविधा नही है, क्योंकि सम्पत्ति चाहिये, जिसके बल पर वह जमीन उन को मिल सकती है। हमारे देश में 70 फीसदी किसान हैं जिनमें 57 फीसदी ऐसे किसान हैं जिनका एक्रेज, जिनका रकबा दो एकड़ से कम है। दूसरी ओर हिन्दुस्तान में सबसे बडे जमीन चोर 5 है, पाच तरह के हैं—बड़े बड़े पूजीपति, बडे बड़े सामन्त, पुराने राजा महाराजा, कुछ ताल्लुकेदार, कुछ बड़े बडे हाकिम जो नये सामन्त बन गये हैं आजकल और कुछ राजनीतिक नेता जिनमे, माफ कीजिएगा, आप ही की तरफ के हैं। आप कुछ मुलाहिजा फर्माइये, हिन्दुस्तान का सबसे बडा जमीन चोर घनश्यामदास बिरला जिसके पास 80 हजार एकड जमीन है। महोली शुगर मिल, सीतापुर, उत्तर प्रदेश के पास 2800 एकड जमीन है। हिन्दुस्तान शुगर मिल हरदोई के पास 3300 एकड जमीन है; महाराजा पटियाला के पास 2500 एकड जमीन है। नैनीताल तराई में 5 हजार से उपर 3 फार्म हैं। 1 हजार से 5 हजार तक के 12 फार्म हैं। 5 सौ से 1 हजार के 250 फार्म हैं और एक सौ से 5 सौ के 1000 फार्म हैं। कैरि-

[श्री झारखण्डे राय]

यप्पा और बिर्ला जो सबसे करीब हैं उनको पांच पांच हजार एकड़ के फार्म आपके मन्त्रालय ने मैसूर में दिए हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा क्या यह सही है कि आपके मन्त्रालय ने बीकानेर जोधपुर की सरहद पर कानपुर के किसी उद्योगपति को 50 हजार एकड़ का फार्म भेड़ पालने के लिए दिया है।

श्री नाथू राम मिर्धा : (नागौर) : यह बिल्कुल गलत है। मैं जानता हूं इस बात को, मुझे राजस्थान की जानकारी है इसीलिए मैं कहता हूं यह बिल्कुल गलत है और प्रोपैगण्डा है। . . (व्यवधान)

श्री झारखण्डे राय : बिहार में 14 हजार एकड़ का फार्म रघुवश नारायण सिंह (पूर्णिया) के पास है। दो लाख एकड़ जमीन बेतिया राज के पास है जो बेकार पड़ी है, जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। 22 हजार एकड़ जमीन रामगुलाम साहू (भागलपुर) के पास है। इसी प्रकार से शुगर फार्म के नाम पर सैकड़ों फार्म बनाए गये हैं। वहां पर शुगरकेन बोया नहीं जाता है, वह जमीन पड़ती पड़ी रहती है।उस जमीन का बढ़िया इस्तेमाल नहीं होता है।

इसी प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश में एक जमनावाद फार्म है 4 हजार एकड़ का नैनीताल में। एक कलेक्टिव फार्म है 10 हजार एकड़ का नैनीताल जिले में। टी०पी० भल्ला (भूतपूर्व आई०जी०), ओंकार सिंह (भूतपूर्व डी०आई०जी०), इसलाम अहमद (अतिरिक्त आई०जी०), राजा भवरी, मेजर चिमनी, चीनी मिलों के फार्म सभी पुराने ताल्लुकेदारों ने, हाकिमों ने उत्तर प्रदेश के नैनीताल, गोरखपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर की तराई में बनाये हुए हैं। यह जमीन के चोर, सामन्ती प्रेत जब तक इस धरती पर हैं वह किसी न किसी बहाने से कानून को बाई पास करके जमीन को अपने पास रखें हैं तबतक कैसे भूमि सुधार होगा और कैसे गरीबी कम होगी---इस बात को तो आप छोड़िये। म आपके आग्रह करूंगा कि सबसे पहले इस विषय पर क्रान्तिकारी कदम साहस के साथ आगे बढ़ायें। इसमें सारा देश आपको साधुवाद देगा और हम सभी इसमें आपके साथ हैं।

मान्यवर, हमारे देश में खती सबसे ज्यादा ह ती है। हिन्देशिया में 29 फीसदी पर खती है, अमरीका में 14 फीसदी पर खती है, कनाडा में14 फीसदी खेती है और भारत 41 फी दी पर खेती है, हमार यहां खती का ज्यादा एकेज है फिर भी ह र अन्न की समस्या में अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सके। एक साल हुआ हमने बड़ी खुशी मनाई, अपने हाथ से अपनी पीठ ठोंकी लेकिन फिर ढाक के तीन पात, जहां के तहां पहुंच गए। 10 वर्षों में एक हजार करोड़ रुपया ग्रो मोर फूड पर व्यय किया गया लेकिन नतीजा उतना ही हुआ जितना होना चाहिए था। श्री राधाकमल मुकर्जी जो कि एक निर्विवाद एकोनामिस्ट रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि 18 एकड़, 20 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी परिवार के पास देश में कभी नहीं होनी चाहिए, इतनी जमीन काफी है एक परिवार के खाने कमाने के लिए जबकि परिवार के सभी लोग उसमें काम करें।

श्रीमन्, मुझे एक चीज याद है, एक पुरानी बात है, प० जवाहरलाल नेहरू ने किसी भावावेश में कहा था :

"I will have a million revolutions in this country rather than have millions of our peasantry living on the verge of starvation."

आज हम खुद स्वीकार करते हैं कि 22 करोड़ आदमी हमारे देश में पावर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। उस महान पुरुष का स्वप्न जहां का तहां धरा रह गया। यह सरकार की नीतियों का फल है। (व्यवधान) मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं हमारे यहां जो राजनीतिक जमीन चोर हैं—यह आंध्र का फोटो है, यह फोटो मध्य प्रदेश का है जिसमें एक कुत्ता भी जमीन चोर है। यह मैसूर का है, यह राजस्थान का है और यह महाराष्ट्र का है। (व्यवधान)

अब जहां तक धतूरा मिले हुए माइलो (बाजरा) का सवाल है या मिल्क पाउडर की बात है जोकि अखाद्य घोषित कर दिया गया, उसकी कहानी यहां पर बहुत कही जा चुकी है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं लेकिन मैं यह कहूंगा कि यह राजनीतिक अपराध है जिसका अपराधी यह मन्त्रालय है। यह एक नेशनल क्राइम कमिट किया है। इसमें मन्त्रालय के भी लोग, बड़े बड़े ऊंचे अधिकारी और बाहर भीतर के लोगों ने मिल कर सभी ने किया है। आपके जवाब से हम कभी भी सन्तोष नहीं कर सकते हैं। इस देश के करोड़ों लोगों ने महसूस किया है कि कहीं न कहीं कुछ काला है जो देशवासियों की जान से खेला जा रहा है।

अब रही उन्नत बीज और उन्नत खेती की बात। यह विशेषज्ञों की राय है कि 3 करोड़ 20 लाख एकड़ जमीन पर वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाये तो देश में अन्न की समस्या हल हो जायेगी। यह मेरी अपनी राय नहीं है, विशेषज्ञों की राय है। उसी तरह से कुछ एक्सपर्टस ने यहां तक कहा है कि भारत अपनी सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि का अगर केवल 5 फीसदी खेती में लगाये, नये ढंग से, तो फिलहाल जो देश की आबादी 55 करोड़ है उसके लिये खाद्य समस्या का समाधान हो सकता है। यह उन विशेषज्ञों की राय है जिन्होंने सरकार की सहायता से सर्वेक्षण किये हैं और कुछ परिणाम निकाले हैं। सरकारी आंकड़े भी कहते हैं कि 6 करोड़ एकड़ जमीन हमारे देश में थी और 5 करोड़ एकड़ तो ऐसी जमीन थी जोकि थोड़ी मेहनत से खेती लायक बनाई जा सकती थी। इस 11 करोड़ एकड़ जमीन में 3 करोड़ एकड़ जमीन हम तोड़ पाये है और बाकी पड़ती पड़ी है। तो क्या उस पड़ती जमीन और जंगल के नाम पर घिरी हुई पड़ती बंजर जमीन का बटवारा नहीं हो सकता ? हम जंगल के खिलाफ नहीं है लेकिन जंगल के नाम पर पड़ती जमीन घेर ली गई है जहां पर एक भी भरमेरिया का पेड़ तक नहीं लगा है। ऐसी जमीन को खाली छोड़ना नेशनल क्राइम है। कम से कम जंगल लगने तक के लिए क्या उसको बांटा नहीं जा सकता है ?

मान्यवर, उन्नत बीज ने हमारे देश की कृषि पर प्रभावशाली असर डाला है, इसको स्वीकार करेंगे और यह असलियत है। उन्नत

[श्री झारखण्डे राय]

बीज के बारे मे कोई दो राय नही है । इसमे मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान खीचूगा । गगानगर के कुलवन्तराय नाम के प्राइवेट किसान ने कुछ आविष्कार किया है, उसकी सूचना राजस्थान सरकार को है, भारत सरकार को, आपके मत्रालय को भी वह सूचना दी जा चुकी है । बीज भेजा जा चुका है, बाले भेजी जा चुकी है, मेरे पास भी उसका सैम्पुल मौजूद है मैं दिखा सकता हू । अब तक जितने बीज, हीरा, मोती, सब निकले हैं उन सबके बारे मे मैं कह सकता हू । मै भेज दूगा, आपके पास, उसका पौधा ड्योढा है । कही तो ऐसे बीज हैं कि जिनके पौधे छोटे होते हैं, अनाज जरूर ज्यादा होता है लेकिन पौधे छोटे होने की वजह से भूसे की समस्या हो जाती है । लेकिन इसमे दोनो बाते हैं, पौधा भी बडा होता है और अन्न भी ज्यादा निकलता है । मैं आपको वे बालें भेज दूगा जो श्री कुलवन्त राय ने निकाली हैं यह उन्होने नया आविष्कार किया है । किसी डठल से जो छोटी डठल निकलती है उसमे अब तक दाना नही आता था, उसके बारे मे आपके पूसा इस्टीट्यूट मे काफी खोज बीन हुई भी थी, लेकिन वह इसमे सफल नही हुए पर श्री कुलवन्त राय ने जो आविष्कार किया है जिसके द्वारा छोटी डठलो मे भी दाने निकल रहे हैं, इसकी जाच होनी चाहिये पूसा इस्टीट्यूट के जरिये और उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये । और अगर सिद्ध हो जाय तो सारे देश मे इसका परिचालन करना चाहिये । इस पर आपके ऐक्सपर्ट ने जो प्रारम्भिक जाच की है उन्होंने भी सन्तुति अच्छी दी है, राजस्थान सरकार ने जो लिखा है वह भी अच्छी रिपोर्ट है ।

14 00 hrs

मान्यवर, खाद्यान्नो का रख रखाव इतने पुराने और आउटडेटेड तरीको से किया जाता हैं कि उससे देश की बहुत क्षति होती है । इसके लिये जरूरी है कि सारे देश के अन्दर वैज्ञानिक तरीके से खाद्यान्नो को रखा जाय । अब आप गेहू के थोक व्यापार मे आ गये, चावल मे आने की आपकी हिम्मत नही हुई, जब कि अहमदाबाद मे आपकी पार्टी ने फैसला किया था, लेकिन चावल का थोक व्यापार अपने हाथ मे लेने मे अपका कलेजा हिल गया । गेहू मे आप आये हम उसका स्वागत करते हैं । श्रीमन्, बीस साल से कहते कहते हम लोगो के बाल सफेद हो गये बोलते बोलते हम लोग थक गये, 20 साल के बाद एक काम आपने साहस का किया कि गेहू का थोक व्यापार आपने अपने हाथ मे लिया जिसका हम समर्थन करते है । तो इस अनाज को रखने के लिये बहुत बडे बडे भडारो की जरूरत पडेगी । अभी जो खाद्यान्न रखने की पुरानी व्यवस्था है उससे मेरा अनुमान है कि एक करोड सत्तर लाख टन अनाज बर्बाद होता है, जिसका अगर रखरखाव वैज्ञानिक कर दिया जाय तो इतनी मात्रा अनाज की हम बचा सकते है और हमको अपनी जरूरत के लिये अमरीका कनाडा, आस्ट्रेलिया या न्यूजीलैण्ड से अनाज मागने की जरूरत नही पडेगी । हम विदेशो के मोहताज नही रहेंगे । इसमे पहला कदम यह होना चाहिये कि आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से खाद्यान्नो को जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर या जो भी स्तर आप मुनासिब समझे

रखने का इंतजाम किया जाय जिससे कि यह समस्या हमेशा के लिये समाप्त हो जाय ।

मान्यवर, एक, दो बातें और कहूंगा । कोआपरेटिव के बारे में मेरी धारणा यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था के समुद्र में कोआपरेटिव का जो टापू है, आइलैण्ड है, यह ठहर नहीं पा रहा है । और इनको अगर कहा जाय कि यह डकैती और डकैतों के अड्डे बन गये है तो कोई अतिशयोक्ति नही होगी । जितना करप्शन कोआपरेटिव में पाया जाता है उतना शायद किसी भी संस्था में नहीं है । 882 मामलों में जांच हुई जिसमें सवा करोड़ रुपये का घोटाला मिला । उत्तर प्रदेश के एक जिले का एक आदमी पकड़ा गया है जो 4 लाख रुपये का गबन किये हुये बैठा हैं । तो केन्द्रीय सरकार से या राज्य सरकारों से रुपया ले कर सहकारिता के नाम पर जो एक दम नग्न और नृशंस भ्रष्टाचार किया जा रहा है या तो इसकी रोकथाम कीजिये वरना इसको बाइन्ड अप कर दीजिये ।

सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई थी 9 मार्च को । 19-8-72 को माननीय फखरुद्दीन अली अहमद की अध्यक्षता में तय हुआ कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के तीनों वक्फ बोर्ड अलग अलग हो जायें । लेकिन आज तक नही हुये । पुराने वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, मैं उनका नाम नही लूगा, उनके खिलाफ जबरदस्त शिकायतें हैं आपके यहां । आप क्यों नही उनकी जांच कराते ? एक भूतपूर्व केन्द्रीय सरकार के डिप्टी मिनिस्टर, श्री यूनुस सलीम को 25,000 रु० पंजाब ट्रस्ट और शिमला ट्रस्ट से दिया गया नकद ....

MR. DEPUTY-SPEAKER: I do not think it is relevant. What are you trying to establish by this?

श्री झारखंडे राय : वक्फ बोर्ड को रीआर्गेनाइज किया जाय । पंजाब, हिमाचल और हरियाणा का जो एक साथ मिला हुआ बोर्ड है, इस को तीन हिस्सों में अलग अलग प्रान्त के लिये कर दिया जाय । और जो शिकायतें है उन को जाच की जाय ।

MR. DEPUTY SPEAKER: What has this got to do with Agriculture? No, please. This has nothing to do with Agriculture. Please try to conclude now.

श्री झारखंडे राय : यह मै इसलिये कह रहा हू कि माननीय कृषि मत्री उस विषय के भी मंत्री हैं ।

MR. DEPUTY SPEAKER: But, it has nothing to do with this Demand. You have exceeded your time.

श्री झारखंडे राय : खैर मैं उस को छोड़ता हूं । गेहूं का जो थोक व्यापार किया गया उस का हम से समर्थन किया । लेकिन उस बारे में आप को अगाह करता हूं कि जिस तरह से प्रतिक्रियावादी शक्तियां उस मामले को ले कर चारों तरफ इकट्ठी हो रही है, उस से आप हिलिये मत, आगे बढ़िये । और जो प्रगतिशील शक्तियां है हम सब आप की मदद करेंगे ।

आखिर मे कुछ सुझाव देना चाहता हू । सब से ज्यादा जोर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारे अब भी 25 साल बाद कृषि पर, सिचाई पर और विद्युत पर दे । दूसरी बात यह है कि चीनी के कट्रोल और उस के वितरण की व्यवस्था पूरे देश मे जो अभी एक सामान नही है उस को एक रूप बनाना चाहिय । गगा-कावेरी योजना नही बल्कि घाघरा, गण्डी और गडक योजना बनायी जाय जो ज्यादा जल्दी सफल होगा और अधिक कारगर और लाभदायक सिद्ध होगा । कृषि, सिचाई और विद्युत मत्रालय एक होना चाहिये, तान नही, तभी इस मे कोआर्डिनेशन और कोआपरेशन बढिया हो पायेगा । तभी हम गरीबी को दूर कर पायेगे और समाजवाद की तरफ बढेगे । हम आशा करत है कि मत्रालय इस पर गौर करगा क्या कि क्रान्तिकारी भूमि सुधार कर क हा परिवतन को और बढा जा सकता है या रक्त रजित क्रान्ति ही हागी इस के अलावा तासरा और कोई विकल्प नही है । इसलिय मैं चाहता हू कि मत्रालय 25 साल क बाद भा अब भी हिम्मत के साथ इस तरफ बढे ।

14.09 hrs

JOINT DECLARATION BETWEEN GOVERNMENT OF INDIA AND PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MR DEPUTY-SPEAKER. I have to interrupt the proceedings for a short while At the conclusion of the visit of the Bangladesh Foreign Minister, certain agreements were reached between India and Bangladesh. Shri Surendra Pal Singh to lay that Paper on the Table of the House.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH): Mr Deputy-Speaker, Sir: I beg to lay on the Table of the House the Joint Declaration between the Government of India and the People's Republic of Bangladesh, which is being issued today. [*Placed in Library. See* No LT-4810/73]

14.11 hrs

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

MINISTRY OF AGRICULTURE—*Contd*

श्री नाथू राम मिर्धा (नागौर) उपाध्यक्ष जी कृषि मत्रालय की मागो पर बहस करने के लिय मैं खडा हुआ हू । मैं इन मागो का समर्थन करता हू और इन मागो का समर्थन करते हुए थोडे समय मे कुछ मुद्दे सुझाव के रूप मे पश करना चाहता हू ।

MR DEPUTY-SPEAKER May I remind you that your Party has decided to allot ten minutes to each Kindly co-operate

SHRI NATHU RAM MIRDHA But, now it is 2 10 and I will finish at 2.20

माननीय झारखडे राव का भाषण मैंने बडे गौर से सुना और वह गरीब आध घटे तक बोले ।

MR DEPUTY-SPEAKER 23 or 24 minutes only And, that was his Party's time

श्री नाथू राम मिर्धा तो मैं कह रहा था कि उन्होने जमीन से शुरू किया, वह जमीन पर बोल रहे थे, जमीन चोरों का जिक्र कर रहे थे, और जहा तक मैं समझ पाया मेरे स्टेट के सम्बन्ध में बिल्कुल गलत प्रचार कर रहे थे । यह यू० पी० में मिनिस्टर रह चुके

हैं थोड़े समय पहले । अभी यू० पी० के बड़े बड़े जमीन चोरों का जिक्र कर रहे थे । यह मंत्रालय उन के हाथ मे था । उस समय उन्होंने चोरों की छुट्टी क्यों नही कर दी थी ? जिस समय उन का काम करने का वक्त था उस समय श्रीमान् जो मूर्ति बन कर बैठे थे और आज यहां पर भाषण देने के लिये खड़े है । यह केवल उन की पार्टी का स्टन्ट है और प्रोपेगेन्डा के लिये है । इस लिये मुझे इस का कोई दुःख नहीं है ।

मै तो सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हू कि कृषि हमारे देश के लिये बहुत ही अहम विषय है और यह मंत्रालय बहुत अहम मंत्रालय है । किसानों की कमाई का जरिया, जो देश की कुल आबादी का 75 फीसदी हिस्सा है, कृषि है और इस कृषि पर ही सारे देश का अर्थव्यवस्था आधारित है । जब हम कृषि की बात करते है तो वनों की बात आती है और जब जमीन की पैदावार की बात आती है तो उस मे वन और जंगल भी आते है । और इन मे जुड़ी हुई व्यवस्था के जो मामले है उन का इस मंत्रालय से सम्बन्ध है । चूंकि इस का इतना बड़ा दायरा है, इस लिये दस मिनट मे बहुत कुछ कहना सम्भव नही है । फिर भी मै इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे देश के कृषि मंत्रालय ने, केन्द्रीय मंत्रालय ने देश की योजनाओं का इस प्रकार गठन किया और सारे काम को इस तरह से आगे चलाया कि राज्यों का सारा विषय होते हुए भी जितना तालमेल सम्भव था उस के अनुसार नीतियों का निर्धारित करते हुए इस देश के कृषि उत्पादन को बढ़ाया । जिस समय हम आजाद हुए थे हमारे देश का कृषि उत्पादन सिर्फ 500 लाख टन था, खाद्यान्नों का । वह बढ़ कर आज करीब 1100 लाख टन तक पहुंच गया है । हम को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना मे 1290 लाख टन तक पहुंचना है । हो सकता है कि उतना हम न पहुंच पायें लेकिन फिर भी जो कमी रहेगी उस को हमे पांचवी पंच-वर्षीय योजना मे पूरा करना है क्योंकि इस देश की आबादी काफी तेजी से बढ रही है । आज हमारी आबादी 54–55 करोड़ के लगभग है । उस को हम को खुराक देनी है । खाद्यान्न भी है और बाहर के तत्व भी उस मे है जो हम को खाने पीने की चीजों के साथ देने है । कृषि से उत्पादित होने वाली वह चीजें है तिलहन, दालें, गन्ना और उस के साथ साथ कपास आदि भी है । हम को इन चीजों का भी इतना उत्पादन करना है जिस से हम देश के लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकें । न केवल हम को अपने देश के लोगों की जरूरतों को ही पूरा करना है बल्कि उस मे भी आगे बढ़ कर हम इस योग्य हों कि हम उन का एक्सपोर्ट कर सकें ।

इन चीजों के करने के लिये जितना अनुसन्धान और ज्ञान है वह हमारे पास प्रचुर मात्रा मे है । हम इन सारी चीजों का उत्पादन बढ़ाने की क्षमता रखते है । हमारे पास सारा ज्ञान और टेकनालोजी मौजूद है पर उस ज्ञान और टेकनालोजी को धरती पर उतार कर किसानों के घर तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था हमारे पास नही है । इस में हम को सुधार करने की जरूरत है । इस मे हम को अपनी सहकारी संस्थाओं और पंचायत राज संस्थाओं का सहारा लेना पड़ेगा । हम

[श्री नाथू राम मिर्धा]

ने आज जो कुछ भी व्यवस्थाये जमाई है उन मे बहुत कमिया हैं । आज जो भी सहकारी सस्थाये हमारे देश मे काफी अर्से से चल रही है वह सारे लेवेल्स पर है, चाहे वह क्रेडिट सस्थाये हों या मार्केटिंग सस्थायें हों । उन्होने सारा बोझ अपने जिम्मे ले लिया है, पर उन को मजबूत करने की जरूरत है ।

हम को कृषि के अन्दर जितने उतार चढाव देखने पड रहे है उस का मुख्य कारण है हमारे देश का कृषि हाट बाजार व्यवस्था । जब तक हम इस देश के किसानो को इस बात की गारन्टी नही दे पाते कि जो चीजे खेतो मे पैदा होती है या पशुओं से पैदा होती है उन का दाम एक निश्चित लेवेल से नीचे किसानो को नही मिलेगा तब तक हमारा उत्पादन नही बढ सकता । हम ने आज इस के बारे मे कदम उठाया है और रबी मे गेहू के व्यापार का सरकारीकरण करना चाहते है और होलसेल ट्रेडर्स को बीच मे से रोकना चाहते है । चावल का भी अगली फसल से सरकारीकरण करना चाहते है । लेकिन हम को काफी दूर की मजिल तक पहुचना पडेगा क्योंकि कुछ राज्यों मे कोर्स ग्रेन भी अपना महत्व रखता है । कोर्स ग्रेन के व्यापार को भी इसी तरीके से अगले सीजन से अपने हाथ मे करना पडेगा । जब तक हम कीमतो मे टिकाउपन नही ला सकते तब तक सारे देश की अर्थ व्यवस्था मे स्थायित्व नही आ सका । यही कारण है कि जब कभी किसान के यहा गन्ना ज्यादा पैदा होता है तब मिल वाले उस को ले लेते हैं और सस्ते दामो पर लेते है । इसी तरह से अगर जूट ज्यादा पैदा हो जाये तो उस में भी कई बिचौलिये बैठे होते हैं और किसानों को उस का पूरा रिटर्न नही मिलता । यही हाल काटन का है । हम ने काटन कारपोरेशन बनाया है । इसी तरह से आयल सीड्स के वास्ते व्यवस्था करनी पडेगी । उस की मार्केटिंग के वास्ते हम को सारी व्यवस्था मे बदलाव लाना पडेगा । यह बहुत पेचीदा काम है । इस के लिये कृषि मंत्रालय का जो अपना प्राइस कमिशन है उस को बहुत मजबूत करना पडेगा । उस का एक ही दृष्टिकोण है और वह यह है कि जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज किसान पैदा करता है किस तरीके से उस का उचित मूल्य किसान को दे सके और सारी चीज की गारंटी कर सके कि जितना उत्पादन होगा, जिन तरीको से उत्पादन होगा और जिन चीजों का होगा उन को निश्चित मूल्य पर खरीदने के लिये वह तैयार होगे । इस तरह से एक्रेज का बैलेंस भी आयेगा और चीजो के उत्पादन मे भी निश्चितता आयेगी । इस के हिसाब से हम देश के उद्योगो की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर सकेंगे और किसानो को एक फिक्स्ड प्राइस भी दिला सकेंगे । साथ ही अगर हम इन चीजो को मैनुफैक्चरर को सही दामो पर बेच देंगे तो मैनुफैक्चरर से भी अपेक्षा करेंगे कि वह भी एक फिक्स्ड प्राइस के ऊपर चीजो को उपभोक्ताओं को मुहैया करा सके ?

इस सारी व्यवस्था के अन्दर हम ने जो महान शुरूआत की है उस को हमे दूर तक ले जाना होगा । इस से हमारी सारी अर्थ-व्यवस्था को एक स्टेबिलिटी मिलेगी । यह शुरूआत हम को ऐग्रीकल्चरल कमोडिटीज से करनी होगी और उस के बाद हम को इसी तरीके से आगे

जाना पडेगा । हमारे यहा अभी दालो की कमी है उस के उत्पादन को बढ़ाना है । खास तौर से बीज के बारे में, खाद के बारे मे क्रेडिट के बारे मे जो सिफारिशें कृषि आयोग ने सरकार के सामने पेश की है उन के अनुसार पुरानी नीतियो मे परिवर्तन करने की आवश्यकता है । हम को यह देखना होगा कि इन नीतियो मे क्या खामिया हैं और उन को कैसे दूर किया जाये । इन सारी बातो मे जा कर के करीब चौदह अहम मुद्दो पर उस ने सरकार के सामने रिपोर्ट पेश की है ? अगर हम उन सिफारिशो पर विचार कर के तुरन्त निर्णय ले सकें और उन का उपयोग पाचवी योजना मे कर सकें तो निश्चित रूप से कृषि उत्पादन बढाने मे सारी दिशाओ मे बल मिलेगा और हम तेजी के साथ उन कमियो को दूर कर के कृषि उत्पादन को बढा सकेंगे । साथ ही खास तौर मे मार्केटिंग के बारे मे भी आयोग ने सोचा और उस के बारे म कुछ सिफारिशें बुनियादी तौर से सरकार के सामने करना चाहता है ।

जब हम कृषि उत्पादन की बात करते है तब मै एक मिनट मे पशु पालन के सम्बन्ध मे भी कुछ कहना चाहूंगा । पशु पालन इस देश के लिये एक अहम विषय है । हमारे यहा की चार योजनाओ के अन्दर जितना जोर इस पर देने की आवश्यकता थी उतना हम नही दे पाये है । खास तौर से कैटल डेवलपमेंट का बहुत बडा पोटेंशल हम इस देश मे देखते हैं । इस के लिये हम को यहां पर फारेन ब्लड लाना है और क्रास ब्रीडिंग को बढाना है । कैटल ब्रीडिंग के सिलसिले मे अगर हम यहां पर बाहर की ब्रीड का ब्लड इंट्रोड्यूस करे तो हमारे यहा की क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनो मे दुगने या ढाई गुने का फर्क आ सकत है, जिस से हम को फारेन एक्सचेंज मिल सकता है । इसी तरह हमारे यहा ऊन का भी पोटेंशल बहुत है । हाईब्रीडिंग कैटल के लिये हम यहा पर बाहर का ब्लड इट्रोड्यूस करे । इस के बारे मे मत्रालय कुछ प्रयत्न कर रहा है लेकिन वह बहुत कम है । इस दिशा मे जितना काम हो रहा है उस मे और ज्यादा बढोतरी करने की जरूरत है ।

मैं एक सुझाव यह भी देना चाहता हू कि जो कैटल आप के फार्म पर आते है वहा पर उन की देख रेख जिस तरीके से होनी चाहिये वह नही हो पाती है । इस लिये काम तेजी से नही चलता । आप चाहे तो इस मे प्राइवेट एन्टिमेंट को भी कुछ शर्तों के साथ ले ले ताकि जो प्रोजेनी पैदा हो उन को हम दूसरों को आगे दे सके । अगर प्राइवेट कैटल ब्रीडर्स मे भी यह काम करवाया जाय तो हमारे देश मे इस काम को आगे बढाने का मौका मिलेगा ।

इसी तरह से हमारे यहा फिश का भी बडा भारी पोटेंशल है । अगर आप देखेंगे तो इस साल हम ने करीब 50 करोड की विदेशी मुद्रा इस से कमाई है । शायद इस म ट्रान्सर्स न होना एक बडी बाधा है । तो चाहे आप ट्रान्सर्स रशिया से ले या अमरीका से लें । अगर ज्यादा पैमाने पर आप ले सके तो आप उस मे डीप सी फिशिंग करे और सी के नजदीकी जो स्थान हैं उन को छोटे लोगो के लिये छोड दे । इस बडे पोटेंशल मे हमारे देश के लोगो को प्रोटीन और रिच फूड भी मिल सकता है । इनलैंड फिशरीज का डेवलपमेंट कर के हम छोटे लोगों की मदद कर सकते है । इस तरह से

[श्री नाथू राम मिर्धा]

देश के अन्दर पशुपालन की ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है ।

अन्त में मैं यही कह कर खत्म करना चाहता हूं कि हमारे देश के फारेस्ट हमारे लिये बहुत अहमियत रखते हैं । दुनिया के देशों में जहां एक एकड़ फारेस्ट से 200 रुपये का नैट प्राफिट मिलता है वहां हमारे यहां पर एक एकड़ फारेस्ट से 10 रुपया मिलता है । इस पर हम को बड़ी गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है । आयोग ने एक रिपोर्ट खास तौर से मंत्रालय को पेश की है और इस के लिये कहा है कि एक लाख हैक्टेयर जंगल को काट कर मेनमेड फारेस्टिंग को बढ़ावा दिया जायेगा तो इस से लेबर को एम्प्लाय किया जा सकेगा और सारी इंडस्ट्रीज का कोआर्डिनेशन किया जा सकेगा । इस पर विचार करने के लिये एक प्लेनिंग सेल आप को इस साल सारे देश के लिये बनाना है । कार्पोरेशन्ज बनाकर उस रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन करने से हमारे देश का जंगल का धन बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है । जब दुनिया के लोग एक एकड़ से 200 रुपया नेट कमा सकते हैं, तो हम लोग केवल दस रुपये क्यों कमायें ? मैं उस रिपोर्ट की ओर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं, लेकिन चूंकि मैंने सिर्फ दस मिनट का वायदा किया था, इसलिये मैं इन सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*SHRI M. S. SIVASWAMY (Tiruchendur): Hon. Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to express my views on behalf of my party, the Dravida Munnetra Kazhagam, on the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture. I need not say that the Agriculture Ministry is an important and vital Ministry. The Demands for Grants of the Ministry of Agriculture include the Demands for Grants of the Department of Food, of the Department of Cooperation and of the Department of Community Development. Initially a duration of six hours was fixed for the discussion of these Demands for Grants and later on the duration was extended to nine hours. I am personally of the view that this time also is not enough for the discussion of Demands for Grants of the Ministry of Agriculture. I would appeal to the hon. Minister of Parliamentary Affairs, Shri Raghuramaiah, that four more hours should be allotted for this discussion. Then only the hon. Members participating in this debate can do justice to the problems involved in agricultural development.

Sir, agriculture is the backbone of the entire country. Out of the total population of 55 crores in our country, 7.82 crores are cultivators and 4.75 crores are agricultural labourers. Out of 55 crores of people, 12.57 crores are engaged in agriculture. The remaining population of 42.43 crores are fed by the sweat and labour of these 12.57 crores of people engaged in agriculture. From this you can very well imagine the importance of agriculture in our country. I would also refer to another paradoxical situation in our country. 20 per cent of the total cultivated area in our country is tilled by 62 per cent of the farmers who happen to be small farmers owning less than 2 hectares. In this country where socialism has become the watchword of the high and low, there is this unfortunate situation that the fruits of labour are not enjoyed by those who labour but by some others.

*The original speech was delivered in Tamil.

The people owning 5 acres and less are larger in number, but the area of land cultivated by them is just 20 per cent of the total cultivated area. Though the people owning large areas of cultivable land are smaller in number just 38 per cent, they happen to cultivate 80 per cent of the total cultivated area. In this land, where the Government day in and day out swear by the establishment of an egalitarian society at the earliest, this distressing disparity continues to persist even after two and half decades of independence. I have no hesitation in saying that unless this disparity is done away with quickly, there can be no meaningful agricultural development. In order to give land to the millions of landless agricultural labour, the Central Agricultural Ministry should evolve a uniform land policy throughout the country. If there is no land ceiling legislation on an all-India level, such disparities will continue to bedevil our agriculture. I would urge upon the Minister of Agriculture to bestow his personal attention on this important problem.

Sir, I am sure that the hon. Minister of Agriculture in his reply to the debate will refer to Small Farmers Development Agency and to the Marginal Farmers and Agricultural Labour Agency, which are meant to assist these people. I consider it my duty to explode this myth. One Small Farmers Development Agency is meant to cover 50,000 small farmers and there are 46 such agencies in our country covering about 23 lakhs of small farmers. Similarly, one Marginal Farmers and Agricultural Labour Agency is meant to cover 20000 marginal farmers and we have 41 such agencies covering about 8.20 lakhs of marginal farmers. Out of the total of 12.57 crores of agriculturists in our country, these two projects together cover 31.20 lakhs of small farmers and marginal farmers. What have the Central Ministry done to improve the lot of remaining 12.26 crores of farmers? And, how long will the Agriculture Ministry at the centre take to cover all the 12.57 crores of agriculturists in our country by these projects? Sir, you will definitely be astonished to know the paltry sum allotted to these two projects. A sum of Rs. 1.5 crores has been allotted for one Small Farmers Development Agency and Rs. 1 crore to one Marginal Farmers and Agricultural Labour Agency. Under these two schemes, a small farmer will be getting Rs. 66 per annum and a marginal farmer a sum of Rs. 43 per annum. What is he expected to do with this niggardly amount? Can he utilise this money for installing a pump-set in his field or for digging a well or for purchasing improved varieties of seeds or for buying the required quantities of fertilisers? I am constrained to say that these projects will serve only to quench the propaganda thirst of the ruling party. You will agree with me if I say that with these meagre allocations these projects are not meant to meet the needs of the small farmers and the marginal farmers. I appeal to the hon. Minister of Agriculture that more funds should be provided for these projects if the Government really want to assist the farmers.

After four Five Year Plans, the total investment in irrigation projects comes to Rs. 2700 crores and a total sum of Rs. 4,800 crores has been invested in power projects. The investment of Rs. 7,500 crores in irrigation projects and in power projects is meant mainly to serve the interests of agriculturists in our country. But, a noted German Economist, Dr. Schmacher, who recently visited India, was compelled to remark that 80 per cent of the rural population in India lives in an intellectual ghetto I do not think that he has in any way exaggerated the existing situation in our country because of the fact that even in 1973-74 Economic Review of the Central Government it has been mentioned that on account of failure of monsoon in 1972-73 there is fall in agricultural production. I do feel that

[Shri M S Sivaswamy]

the Central Government should feel ashamed to make such a statement after the implementation of Four Five Year Plans Don't you agree, Sir, that it is shame to say, especially after investing 7,500 crores in irrigation projects and in power projects, that agriculture is still dependent on the vagaries of weather?

From 1949 to 1965 the rice production was going up by 3 per cent, but during the period 1966 to 1972, the rice production went up by only 1 per cent During the past decade. the production of pulses had been stagnant The most important commercial crop, sugarcane has also not been maintaining a uniform level of producton I am not as a member belonging to the Opposition Party, saying all this as a matter of criticism All these are statements of facts contained in the Central Government's latest Economic Review It has also been categorically stated in the Approach Document to the Fifth Five Year Plan that the Central Agricultural Ministry has not so far brought about meaningful agricultural reforms and if the Ministry want to help the small farmers and the marginal farmers there must be immediate reorganisation of institutional set-up Shri Minhas, a Member of the Central Planning Commission has expressed his opinion that 90 per cent of the agriculturists have not derived any benefit from the huge investments made in irrigation projects and in power projects. From the massive investment of 7500 crores in irrigation projects and in power projects all the benefits have accrued only to 10 per cent of the agriculturists in our country I, who belong to the D M.K Opposition Party, do not say this It has been specifically stated by a Minister who has been holding office continuously for the past 25 years at the Centre Shri Jagjivan Ram has made this remark I wonder what has been contribution of the Central Ministry of Agriculture so far for the welfare of agriculturists and for the development of agriculture in the country I hope that the Ministry of Agriculture will now at least wake up to the situation and formulate worthwhile proposals from which all the agriculturists in the country will be able to derive the maximum benefit

Having accepted that the agriculture in our country is dependent upon the vagaries of weather, let us see what the Central Government have done so far in finding a permanent solution to the recurring drought situation From 1970-71 to 1972-73 a sum of Rs 67 79 crores has been spent on drought relief programmes You will be surprised to know that the annual loss of foodgrains due to drought has been estimated to be of the order of Rs 300 crores I have no words to explain the passivity of this Government You know Sir, that last year there was acute drought in many parts of the country The Central Government sent many teams of high officials to all the States afflicted by the drought to study the situation and to assess the financial requirements of the States to tackle the worsening situation These Central Teams recommended a sum of Rs 192 84 crores for giving as assistance to the drought affected States But the Central Government exposed their munificence by allocating just Rs 123 54 crores If the actual requirement as assessed by the Central Team of officials is not to be sanctioned what is the need for sending such teams to the States? One such team recommended that a sum of Rs 14 66 crores should be given to Orissa but the Central Government sanctioned only Rs 6 crores The Team that visited Tamil Nadu in October last recommended Rs 1 5 crores as drought relief to Tamil Nadu But, probably because an opposition party is ruling the State the Central Government did not give even a single rupee under this assistance programme—not even a few lakhs of rupees as an eye-wash Similarly West Bengal was recommended a sum of Rs 10 08 crores, but the sanctioned

amount was only Rs. 5.04 crores. I do not understand why the Central teams of officials should be sent to the States, if their recommendations are not to be accepted.

Sir, I come from a dry area. My constituency, Tiruchendur, and the nearby districts like Tuticorin, Ramanathapuram etc. get rain for three days in a year. The cultivators are to depend on the three days' rain in a year for doing their agriculture. Even if it happens that there is a spring-well in a dry area, the Commercial Banks refuse to give advances or loans to the farmers from dry area. They have also no other source of revenue. I would appeal to the hon. Minister of Agriculture that he should ensure that at least the 14 nationalised Banks give loans and advances to the farmers from dry area whose sufferings cannot be recounted in this House in a few minutes.

Sir, during the past twenty years, the total loss incurred by the agriculturists due to floods in the form of damage to foodgrains, destruction of their cattle and their tenements, amounted to Rs. 650 crores. But, the Government have so far spent Rs. 230 crores on flood control measures. I would like to urge upon the hon. Minister of Agriculture that immediately permanent solutions should be found out for tackling the ever recurring drought and floods in our country. These cannot be brushed aside as mere natural calamities.

Sir, the performance of the Central Agriculture Ministry presents a dismal picture. In 1970, the Ministry formulated a proposal to open 5000 agro-Service Centres throughout the country during the Fourth Plan period. In 1971-72 only 260 agro-service centres were opened. The target in 1972-73 was 1000 agro-service centres. But the hon. Minister of Agriculture has sympathetically conceded that this target is not possible of achievement. The Ministry plans for 5000 Agro-service centre, but only 260 centres have so far been opened. The programme started with a bang and seems to have ended in a whimper. I have no other name except to call them as 'Thughlak' schemes serving the propaganda interests of the ruling party. If the Ministry cannot implement such a scheme, I wonder how the Ministry should have the gumption to formulate such a proposal.

Sir, there is acute shortage of foodgrains throughout the country, necessitating the import of foodgrains last year to the tune of 22 lakh tonnes. There is universal power scarcity in the country. The improved varieties of seeds, the agricultural implements like tractors etc., and the fertilisers are in short supply. It is feared that if the monsoon fails again the situation may become uncontrollable. When this is the position prevailing in the country, I strongly condemn the failure of the Agriculture Ministry in utilising fully the allotted money. In 1970-71 under the Demand No. 30—Agriculture, the Ministry surrendered a sum of Rs. 2.95 crores! For instance, in my State, the Ministers are vying with one another to get more allocations for their Departments so that they can implement more welfare schemes. But, here the Central Ministry of Agriculture surrendered a huge sum of Rs. 2.95 crores meant for agricultural development. I have to term this failure as a heinous crime. I also do not hesitate to say that the officials responsible for this unpardonable lapse, a lapse which should be treated as a crime committed under the Indian Penal Code, must be brought to book under the I.P.C. It is not that I have found out this lapse on the part of the Agriculture Ministry. The Public Accounts Committee of this House in their 369th Report on page 67 has referred to this in highly critical terms. I would urge upon the Minister of Agriculture that strict measures should be adopted to ensure that the allocations are spent fully.

I come from an area where fisheries predominate. In the whole of east-

[Shri M. S. Sivaswamy]

coast in my area, fisheries have an important role to play in the livelihood of many millions of people. Still, the commercial banks refuse to give loans and advances to fisheries on the ground that under the Reserve Bank of India Act fisheries have not been treated on par with agriculture. The Central Governmenut accepted the contention that fisheries should be treated on par with agriculture and promised to amend the R.B.I. Act. But so far it has not been done. I would appeal to the Minister of Agriculture that he should use his good offices in getting the R B.I. Act amended for this purpose.

This Ministry has eminently succeed in one respect and that is in respect of using Hindi in the Ministry and in the offices under its charge. the Annual Report of the Ministry you will find elaborate reference to this aspect of their work. I want to know from the hon. Minister whether all the 13 crores of agriculturists have their mother-tongue as Hindi. Has food production gone up by greater use of Hindi? Has the Ministry been able to stop by the use of Hindi the destruction of foodgrains by millions of rats in the country, quantities of foograins which can feed 4 crores of people annually? I want to know whether greater use of Hindi in the Ministry has led to any reduction in the damage to grains in the godowns of Food Corporation of India, which is reported to be of the order of Rs. 200 crores a year.

Sir, last year the Central Government imported 20 lakh tonnes of foodgrains from abroad in spite of heavy strain on our slender foreign exchange resources. But from January 72 to February 73, 13,114 tonnes of foodgrains had got damaged in the foodgrain godowns of Food Corporation of India. It is also reported that another 16,240 tonnes of damaged foodgrains are in the hands of the Food Corporation of India. I would like to know the reasons for such colossal damage to foodgrains in the godowns of Food Corporation of India.

Before I conclude, I would refer to the requirements of Tamil Nadu. In the Indian sub-continent, the Punjab and Tamil Nadu are standing in the forefront in the matter of foodgrains production. In 1972-73 the Tamil Nadu Government wanted 2.74 lakh tonnes of nitrogen, but the Central Government allotted only 50 per cent of the requirement, i.e. about 1.49 lakh tonnes of nitrogen. In the recent Zonal Conference held at Bangalore, the Tamil Nadu Government has demanded for the current khariff crop 1.20 lakh tonnes of nitrogen, 20,935 tonnes of phosphate, and 10866 tonnes of potassium. I urge upon the Minister of Agriculture that the requirement of fertilisers by Tamil Nadu should be met in full.

Sir, the Tamil Nadu Government has paid a sum of Rs. 4 lakhs to Bharat Electronics Bangalore for the purpose of setting up a Liquid Nitrogen Plant for storage of animals semen as recommended by the Dairy Development Corporation But there has been inordinate delay in setting up this unit for want of machinery etc I request the hon Minister to look into this also.

One word more and I have done Under an Indo-German Nilgiri Project, a German organisation gave us a gift fertilisers worth Rs. 70 lakhs for potato cultivation in the Nilgiris. Our sympathetic Central Government have not hesitated to charge excise duty on the consignments. There is a proverb in Tamil Nadu which means that Perumal begs with his bowl, but that bowl is snatched away by Hanuman The action of the Central Government in charging excise duty on gift consignments has supplanted this proverb in Tamil Nadu.

With these words, I conclude.

*SHRI K. SURYANARYANA (Eluru): Mr. Deputy-Speaker, Sir almost all the State Governments passed laws with regard to the land reforms and also framed rules to provide for allotment of Government fallow lands

*The original speech was delivered in Telugu.

and surplus lands or a priority basis to landless laburers including Schedule Castes, Schedule Tribes and other backward classes. Because the distribution of surplus land is not being done according to the policies that were laid down by the Government, I am happy to note, the decision of the Central Government to set up a land reform centre at the Gokhlay Institute of Politics and Economics at Poona. So far the Government have estimated that 5 million acres of land would be surplus. Out of this 20 lakhs 40 thousand acres is suitable for distribution in the States. So far they have been able to distribute 10 lakhs 25 thousand acres of land to the landless poor Because of the insufficient and inadequate policies of the State Government in the question of distribution of surplus land some difficulties are being faced

In my own constituency an agitation is going on In that connection I would like to read a telegram which has been received by me·

"Convey Prime Minister our thanks for helping water for second crop Requesting to represent atrocities of Murthiraju against fishermen and agricultural coolies in Kolleru area Murthiraju pressing two bags paddy per acre as if water given by his generosity and also posting false case —Fishermen Agadallanka Agricultural collies.

In connection with the same matter 245 fishermen and others who are effected have submitted a memorandum to the Collector and sent a copy of it to me for submission to you here. I would quote a few sentences from that memorandum:

"Shri Murthiraju, MLA, and Ex-Minister is very powerful in our parts. He has founded a society known as Thokalapalli Co-operative Joint Farming Society in or about the year 1956 and eversince he has been in full control over it taking the lands on periodical leases from Government. The said society was subsequently bifurcated into five societies. Though there are nominal boards for the above societies with Presidents, Secretaries etc., he has been managing to admit only such members as are subservient to him. He has been collecting 2 bags per acre over the 1100 acres of land taken by the society on lease from the Government." Besides he has been selling away the fishery rights in the said lands and realising large amount."

The memorandum further states:

"We have been representing to Sri Murthiraju from 1969 onwards that it was not just and proper on his part to sell the fishing rights in Society lands and Samsta lands and we, who have been having fishing licences and depending on fishing may be permitted to carry on fishing without any interference from him."

As per the Government of Andhra Predesn orders which state,

"That the lessees of land shall have the right to fish or dispose the fishery avaliable in Jadas and Gundams formed in Collair lake and in the plots leased out to them for cultivation The fishery licence holders can enjoy the fishing available in Jadas and Gundams before the transplantation of the second crop (which commences generally in early February) without causing any damage to the Buda."

This order has been flouted by him and the Government is not in a position to check him. Several people who agitated were victims of false cases that were foisted upon them. Another petition has been submitted to Collector Eluru on 14th of this month when

[Shri K. Suryanarayan]

a false case has been foisted against them because they protested against unlawful exploitation of the resources of the lake when such an exploitation is permitted any amount of land reform would not do good to the people.

Even before the advent of the irrigation in Godavari delta area project, in Kolleru lake several families are producing good crop in that area. They were cultivating that land for the last 200 years. The Government has not done anything to distribute this land to these people who are working on it. I have written to the Government of Andhra Pradesh in the matter. I have suggested that all these lands should be surveyed and distributed as quickly as possible. The Government replied stating that "Regarding the suggestion to grant pattas for the lands to the cultivators to enable them to secure long term loans, etc. by collecting from them market value at the rate of Rs. 500 per acre on the average, this Government hold the view that the proposal of assignment of Kollair lands may be deferred till the lands are rendered fit for dependable wet cultivation after the drainage schemes contemplated by the Mitra Committee report for the area are completed." It is seven years since Mitra Committee submitted its report. Because of lack of funds with the Government they are not able to implement the recommendations of that Committee. The land which is about 30,000 acres has not so far been distributed. Some influential landlords are taking advantage of the situation. I submit that the Centre should suggest to the State Government to distribute that land among the farmers who are already working at an early date. This is an opportune time the State is under President's rule.

I suggest that this land may be taken over by the State Farms Corporation. If it is taken over then the policies of the Government could be very effectively implemented. In this connection I would suggest further that the Chairman of the State Farms Corporation should go into the feasibility of taking over and submit a report to the Government.

The land in the Kollaru area is being given on one year lease. The farmers are deprived of their rightful due by some influential landlords. I may add that 20,000 tons of fish is being produced every year and is being exported to Calcutta. Middlemen are making exorbitant profits while the fishermen are exploited and paid only a rupee a kilo whereas it is sold at the rate of Rs. 7 per kilo in Calcutta.

Two years back hon. Shri Shinde came to that area to lay the foundation stone for a transformer for electricity. We are able to electrify 10 to 12 villages in that area with the help of State Electricity Board .

I would like to mention here another important matter about sugar factories. We proposed to construct about 40 new sugar factories in the country. Out of which 30 of them are proposed in the Cooperative Sector. These factories are not coming up as expected because of the lack of necessary materials like cement, iron and steel etc. Because of delay in the construction of the factories the prices have gone up and the estimates were boosted up. One sugar factory at Bhimadole whose estimate has increased from 2 crores 75 lakhs to 3 crores 40 lakh is a case in point. I therefore submit that the loans that were sanctioned by the National Cooperative Development Corporation should be suitably enhance to meet the price rise. Otherwise the licences would lapse and a serious impediment would result in the progress of Cooperative Sector in the field of sugar industry.

Another point I would like to mention is about the food production. The farmers are working very hard and are producing considerable amount of

foodgrains. They are facing difficulties in getting loans and fertiliser at reasonable terms. I had an informal talk with the hon. Minister Shri Barooah yesterday. I am glad that he has agreed in principle to the suggestion that there should be fertiliser factory in the Circars districts. So far we are getting fertilisers from other States. The other States are not able to utilise their quota comp'etely. You all know the importance and necessity of fertiliser in the cultivation of high yielding varieties of crops. Here I would like to state that the marginal farmers are facing great difficulties in securing loans after the implementation of land reforms. Neither the Government is giving loans nor the cooperative societies have any money with them While concluding I would like to submit that the farmers in my district are also facing these difficulties.

In this Rabi season in West Godavari district we have produced 2 lakhs 40 thousand tonns of foodgrains of high yielding varieties. This is inspite of the political turmoil which overtook my State. I am proud of the performance of the farmers as well as the agricultural labourers in the matter.

Finally I would submit here that the farmers in my State would be able to his best when peaceful conditions return after the bifurcation of the State of Andhra Pradesh as desired by them. I assure the Government that much more foodgrains would be available from the State of Andhra Pradesh if such a step is taken by the Government.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राष्ट्र के जीवन में कृषि का बहुत महत्व है और हमारी राष्ट्रीय आय का करीब आधा आय हमको कृषि से मिलता है । इसके अतिरिक्त बहुत सारे उद्योग-धन्धे भी ऐसे है जो कृषि पर आधारित हैं इसलिए हमारे राष्ट्रीय जीवन में कृषि का महत्व कम नहीं कहा जा सकता । कृषि का बहुत बड़ा महत्व है ।

15 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair.*]

और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए यह बात भी ठीक है जो माननीय सदस्यों ने कही कि सब से आवश्यक चीज जिससे हम कृषि का उत्पादन बढ़ा सकते हैं वह पानी है, सिंचाई है । उसके बगैर हम चाहे कितना ही अच्छा बीज डालें, कितनी ही खाद दे या और साधन हो, उन सब साधनों का उपयोग तभी हो सकता है जब सब से पहले हमारे पास पानी उपलब्ध हो । इसलिए पानी का सब से बड़ा महत्व है और कृषि मंत्रालय ने इस बात पर अधिक जोर दिया है कि हम अपनी जो स्कीमे बनायें उस मे अधिक से अधिक जोर हम सिंचाई के बढ़ाने पर दें । और इसलिए ग्राउंड वाटर डेवलेपमेंट और रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन, इनके ऊपर हर वर्ष 250 करोड़ रु० करीब ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट के ऊपर और 150 करोड़ रु० रूरल इलैक्ट्रिफ़िकेशन पर खर्च होता रहा है । और उसके द्वारा कितनी नई भूमि को सिंचाई मिली है यह भी मैं आंकड़े आपके सामने उपस्थित कर दूं । 1968–69 में आज से पांच साल पहले चौथी पंचवर्षीय योजना आरम्भ हुई तब हमारे देश में डग वैल्स की कुल संख्या थी 56 लाख 95 हजार और इस चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में उन की संख्या 65 लाख हो गई । इसी तरह प्राइवेट ट्यूब वैल्स की संख्या 2 लाख 66 हजार थी और वह इस पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 8 लाख 73 हजार हो जायेगी । इसी तरह पब्लिक ट्यूब वैल्स की संख्या जो 15,000 थी वह 20,000 हो जायेगी । इलैक्ट्रिकल

[प्रो० शेर सिंह]

पम्पस 10 लाख 89 हजार थे, 1968–69 मे, जब चौथी योजना आरम्भ हुई, और अब उनकी सख्या 25 लाख 884 हजार हो जायेगी । इस तरह डीजल पम्प सैट्स 8 लाख 37 हजार थे और इस योजना के अन्त तक उन की सख्या 14 लाख 37 हजार हो जायेगी । इस तरह जो सरफेस माइनर इर्रीगेशन स्कीम्स और ग्राउड वाटर के द्वारा जिनका विवरण मैंने रखा, उसके द्वारा जहा 12 88 मिलियन हैक्टेयस को सिचाई उपलब्ध थी 1950–51 मे, वह अब 23 50 मिलियन हैक्टेयर्स को पानी मिल जायेगा चौथी पचवर्षीय योजना के अन्त तक तो अगर आप इसका हिसाब देखे तो करीब 90 प्रतिशत के करीब वृद्धि हुई है ग्राउन्ड वाटर डेवलेपमेंट और सरफेस माइनर इर्रीगेशन स्कीम्स के द्वारा जो सिचाई हुई उस मे ।

यह प्रश्न किया गया कि क्या बात है कि जब सिचाई बढी तो पैदावार क्यो नही बढी ? लेकिन मेरे सहयोगी ने बताया था कि जहा पहले 55 मिलियन टन्स, यानी साढे पाच करोड टन अनाज का हमारा उत्पादन था 1956 के करीब वहा 1970–71 मे 10 करोड 80 लाख टन के करीब पहुच गया । तो इसका अर्थ यह है कि 90 प्रतिशत के करीब सिचाई बढी । उसी के अनुपात से बल्कि उससे भी अधिक हमारी पैदावार बढी । इसलिये यह कहना कि हमारी पैदावार नहीं बढी है यह गलत है ।

यह ठीक है कि पिछले वर्ष देश के काफी इलाको मे सूखा पड़ा और सूखा पडने के कारण जो मोटे अनाज है, तिलहन, दाल वगैरह की पैदावार मे कमी हुई । लेकिन उस समय कृषि मंत्रालय ने कदम उठाये कि इस दौरान मे भी जितना पानी उपयोग मे ला सकते है लाना चाहिये, और इसलिये इमरजेंसी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोग्राम चालू किया गया और उसके फलस्वरूप हमारा अदाजा है कि शायद 30, 40 लाख टन के करीब अतिरिक्त अन्न की पैदावार हुई इसी के कारण जो हमने इमरजेंसी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोग्राम लिया । और उसके द्वारा

(व्यवधान)

सभापति महोदय आप बराबर व्यवधान न कीजिए ।

प्रो० शेर सिंह कोई साढे सात लाख एकड के करीब नई भूमि को सिचाई मिली और उसके कारण वृद्धि हुई । तो यह कहना कि कोई सिचाई का लाभ नही पहुचा यह गलत बात है आखे बन्द करना है तथ्यो से ।

हमारे सहयोगी ने बताया था कि सूखे का प्रभाव काफी व्यापक है, हमारे देश तक ही सीमित नही था, और देशो मे भी था और बहुत सारे देशो को और देशो से भी बाहर से अनाज लेना पडा । हमारे देश ने सब से कम लिया और हम अपने देश की प्रशसा खुद नही करते, बल्कि एफ० ए० ओ० के लोगो ने स्वीकार किया है । पिछले वर्ष मे रशिया का भी उत्पादन कम हुआ है इस साल भी कम हुआ है । चाइना के अन्दर भी कम हो रहा है और भी एशिया के देशो के अन्दर कम हो रहा है । लेकिन जो कदम भारत ने उठाये उनके फलस्वरूप जितना

अंदेशा था उस के हिसाब से यहां पर कमी नहीं आई, बल्कि पिछले दिनों जो कदम उठाये उसका फ़ायदा यह हुआ कि रबी की फ़सल पिछले साल से तगड़ी है। पिछले साल गेहूं 2 करोड 65 लाख टन के करीब था। इस साल हमारा अन्दाजा है कि शायद 3 करोड़ टन के करीब उत्पादन पहुंच जायगा। इसलिये यह कहना कि कोई लाभ नहीं हुआ सिंचाई का यह गलत बात है।

जमीन के बारे में माननीय झारखंडे राय ने एक बात कही कि बहुत सारी परती जमीन पड़ी हुई है जिसका उपयोग हम नहीं करते है। उस का उपयोग अगर करें तो काफी वृद्धि पैदावार में कर सकते है, उस का उपयोग चाहे जंगलो के लिये करें, चाहे खेती के लिये करें, लेकिन उस का उपयोग होना चाहिये। हमारे देश मे पहली बार एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस बात पर विचार लगा है, और पंचवर्षीय योजना मे लिये प्रोग्राम बना रहे हैं कि सब से पहले जो भूमि हमारा सब से बडा साधन है इस देश का, उस साधन के बारे में पूरी जानकारी जो हमें नहीं है, वह पूरी जानकारी प्राप्त हो। उसके लिये हम सोइल सर्वे करें, बहुत बडे पैमाने पर सोइल मैप तैयार करें जिसमे हमें जानकारी हो कि कौन सी जमीन किस फ़सल के लिये उपयुक्त है, कौन सी फसल वहां पर लगानी चाहिये, क्या वहां पर क्रौपिंग का पैटर्न होना चाहिये। उस के सम्बन्ध में वैज्ञानिक ढंग से विचार करके कोई 10 करोड रु० के करीब हमने मांगा है कि अगली पंचवर्षीय योजना में इस बात के लिये पैसा रखा जाये जिससे यह तो जान लें कि जो भूमि हमारे पास है, जो साधन हैं, उन साधनों का उपयोग किस जगह और किस चीज के लिये कितना कर सकते हैं, उससे कितना लाभ कमा सकते हैं, कौन सी जमीन में खेती करें, कौन सी जमीन में हाई यील्डिंग वैराइटीज की खेती करें, कौन सी जमीन में तेल, तिलहन पैदा हो सकता है और कौन सी जमीन में गन्ने की खेती करें, कौन सी जमीन में पास्चर डवलप करें ताकि पशुपालन कर सके। तो हम अपनी जमीन का किस ढंग से औप्टिमम उपयोग कर सकते हैं, कौन सी जमीन किस लायक है, उस के सम्बन्ध में विचार किया है।

इसी तरह में जो बहुत सारी जमीन हमारे डेम के नीचे आ गयी, वाटर लागिंग हुआ, वैसे हमारे देश में जो सरफ़ेस इर्रीगेशन की मेजर और माइनर स्कीम्स थी, दुर्भाग्य की बात है कि उस की करीब एक तिहाई जमीन हमारी खराब है। जो नहरे हमने निकाली उस के आस पास की जमीनो में वाटर लागिंग हुआ, सेम आयी, और उस की वजह से कोई 6 मिलियन एकड़ जमीन पर असर हुआ। उस जमीन को भी हम लाईनिंग करे, जो सारी नहरे हैं उनको पक्की करे, सी पेज वेनेज का इन्तजाम करें, जमीन का रिक्लेमेशन करे। काफ़ी बडी माडवा में जो जमीन बेकार हो गई है पानी की कमी की वजह से उसको रिक्लेम कर के हम काम में ला सकते हैं। और उत्पादन बढा सकते है इसके लिये भी योजना बनाई गयी है इसी तरह से जो बडे बड़े रिजर्वायर हैं, वाटर शेडस है जहां मिट्टी बहकर आ सकती है बारिश के साथ, जिस से सिल्टेशन होना है, उन की लाइफ छोटी होने का अन्देशा हो रहा है। इस के लिये भी

[प्रो० शेर सिंह]

हमने प्रोग्राम बनाया है। इतनी बड़ी प्रोजेक्टस के ऊपर पिछली पंच-वर्षीय योजना में 25 करोड़ रुपया खर्च किया गया था और अगली पंच-वर्षीय योजना में और अधिक हम खर्च कर रहे हैं। इसी तरह से फ्लडस के बारे में भी कुछ कदम उठाने हैं। इन सब का उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक पानी को ठीक ढंग से इस्तेमाल कर सके और जमीन खराब न हो, तथा जिस जमीन से से जो उपज हम ले सकते हैं वह ले सकें। इस के लिये विशेष रूप से ठोस कदम उठाये गये हैं।

SHRI B. V NAIK (Kanara): Has the hon Minister given any thought to the reclamation of saline land around India's coast-line of 3,500 miles?

प्रो० शेर सिंह. सैलाइन लैंड के लिये भी रि-क्लेमेशन का कार्य चल रहा है। कर्नाल में जो हमारा इन्स्टीट्यूट है वह इस पर गौर कर रहा है। सैलाइन लैंड से हम कौन सी फसलें उगा सकते हैं इस बारे में जांच हो रही है। उसमें अगर बीट उगा सकते हैं अथवा दूसरी फसलें उगा सकते हैं या नहीं, इस के बारे में अनुसंधान हो रहा है। उसी ढंग से जो जमीन खराब हो गई है, सैलाइन हो गई है, वाटरलागिंग हो गई है उस को किस तरह से हम रिक्लेम कर सकते हैं इस के बारे में काफी काम हो रहा है। यह कोई बहुत बड़े कार्य क्रम नहीं है लेकिन विचार चल रहा है।

एक बात और कही गई कि जितना हमारा सिंचाई का कार्यक्रम चलाया गया और कृषि उत्पादन बढ़ाने की बात चलाई गई, उसका लाभ बड़े किसानों को हुआ, बड़े जमींदारों को हुआ, छोटे किसानों तक उसका लाभ नहीं पहुंचा। इस बात से काफी हद तक सच्चाई है। यह ठीक बात है कि पिछले वर्षों में जितने हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम चले कृषि से उत्पादन को बढ़ाने के लिए और सिंचाई जमीन को और अधिक देने के लिये उसका अधिकतर लाभ बड़े बड़े लोगों को पहुंचा है। यह बात नहीं कि उसका लाभ छोटे किसानों को नहीं पहुंचा, उनको भी पहुंचा है, लेकिन देश में छोटे किसानों की आबादी बहुत है और जमीन उनके पास थोड़ी है—हमारे यहां 70 फीसदी छोटे किसान है लेकिन उनके पास करीब 30 फीसदी जमीन है। इस लिये जो भी लाभ पहुंचता है छोटे किसानों को सिंचाई वगैरह का अगर एक एक किसान के हिसाब से देखा जाय तो छोटे किसान को लाभ तो पहुंचता है लेकिन थोड़ा पहुंचता है। यह ठीक बात है कि जो उत्पादन के नये तरीके अपनाये गये, वैज्ञानिक ढंग अपनाये गये उनका लाभ छोटे किसान नहीं उठा पाये। लेकिन चूंकि उनके पास साधन नहीं थे इस लिये जितना लाभ वह उठा सकते थे उतना नहीं उठा पाये। इसी लिये जो कमजोर वर्ग हैं, जो छोटे किसान हैं उनके लिये हम ने विशेष कार्यक्रम चलाये। उनकी चर्चा भी यहां पर हुई।

स्माल फार्मर्स डेवेलपमेंट एजेंसी और मार्जिनल फार्मर्स ऐंड ऐग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए पाइलट प्रोजेक्ट्स बने। 46 पाइलट प्रोजेक्ट्स स्माल फार्मर्स डेवेलपमेंट एजेंसी के लिये बनाये गये और 41 पाइलट प्रोजेक्ट्स मार्जिनल फार्मर्स ऐंड ऐग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिये बनाये गये। पहले वर्ष में यह काम कुछ थोड़ा हुआ क्योंकि पहले तो इस बात का निर्णय करना था कि किसी एक क्षेत्र में छोटे किसान कितने हैं। उनका आइडेंटिफिकेशन

करना था। इसी तरह से मार्जिनल फार्मर्स ऐंड ऐग्रीकल्चरल लेबरर्स का आइडेंटिफिकेशन करना था। उसके बाद ही उनको सुविधायें पहुंचा सकते थे। इसकी तैयारी करनी थी। उसके बाद 1971–72 और 1972–73 में काफी काम हुआ है। मैं आपकी आज्ञा से एस०एफ०डी०ए० और एम०एफ०ए०एल० के लिये जो काम हुआ है उसके बारे में बतलाना चाहता हूं। नम्बर आफ पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिफाइड—22,62,000/10,80,000 छोटे किसानों का आइडेंटिफिकेशन किया गया। इसी तरह से मार्जिनल फार्मर्स और ऐग्रीकल्चरल लेबरर्स का आइडेंटिफिकेशन किया गया। इस कार्यक्रम की तहत अब तक जो काम किया गया वह इस प्रकार है :

	एस०एफ० डी०ए०	एम०एफ० ए०एल०
बेल और ट्यूब वेल	48341	5250
पम्पसेट	12935	2442
माइनर इरिगेशन वर्क्स और दूसरे छोटे वर्क्स	16996	391

इसी तरह से मिल्च कैट्ल के बारे में है। छोटे किसानों को दूसरा सहारा देने के लिये, दूसरा रोजगार देने के लिए यह प्रयत्न किया गया कि वह पशुपालन कर के अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकें। इस कार्यक्रम के तहत 22566 मिल्च कैट्ल एस०एफ०डी०ए० में दिये और 13313 मिल्च कैट्ल एम०एफ० में दिये। इसी तरह से पोल्ट्री यूनिट्स 2655 एस०एफ०डी०ए० क्षेत्रों में दिये और 2066 एम०एफ०ए०एल० क्षेत्रों में दिये। इसी प्रकार रूरल आर्टिजन्स की बात है। जो देहात के कारीगर हैं उनमें से 1044 को एस०एफ० डी०ए० में मदद दी गई और 13 को एम०एफ० ए०एल० में मदद दी गई। इसी तरह से रूरल वर्क्स के बारे में है। इसकी तहत भी 15711 लोगों को रोजगार मिला एम०एफ०डी०ए० में और 5560 लोगों को रोजगार मिला एम०एफ०ए०एल० मे।

इनके बारे में थोड़ा भ्रम था और माननीय सदस्य ने अभी कहा कि जो रुपया इसके अन्दर रखा गया है वह एम०एफ०डी०ए० मे एक आदमी के पीछे 1 हजार 66 रु० और एम०एफ०ए०एल० में 46 रुपया आता है। इससे क्या बनेगा ? इतना इतना रुपया हर व्यक्ति को देना है। उसे साधन देने होंगे, सुविधायें देनी होंगी, उनको कर्जे दिलवाने हैं जिससे वह अपना कारोबार कर सकें। इस लोन की सहायता देने के बाद उनको सब्सिडी मिल जाये। अगर ऋण मिलने में कोई दिक्कत हो तो उसकी गारेन्टी सरकार दे दे, रिस्क फंड बना ले। इसके लिए 1.50 करोड़ रुपया एस०एफ०डी०ए० के अन्तर्गत रखा गया और 1 करोड़ रुपया एम०एफ०ए०एल० के अन्तर्गत रखा गया। जो रिस्क फंड बनाया गया है उसका यह मतलब नहीं है कि केवल इतना ही रुपया उनको मिल सकेगा। इसके लिये कोआपरेटिव को मार्फत कर्जा मिला है, एस०एफ०डी०ए० के अन्तर्गत 27 करोड़ 19 लाख का शार्ट-टर्म लोन मिला है और एम०एफ०ए०एल० प्रोजेक्ट्स में 2 करोड़ 42 लाख रुपया मिला है। मीडियम टर्म लोन

[प्रो० शेर सिंह]

एस०एफ०डी०ए० के अन्तर्गत 6 करोड़ 41 लाख मिला है और एम०एफ०ए०एल० के अन्तर्गत 1 करोड़, 69 लाख, 75 हजार मिला है। इसी तरह से लांग टर्म लोन 16 करोड़, 45 लाख, 50 हजार एस०एफ०डी०ए० प्रोजेक्ट्स में और 1 करोड़, 58 लाख, 85 हजार एम०एफ०ए०एल० में मिला है। इसी तरह से कामर्शल बैंक्स से भी मिला है।

इस तरह से देखा जाय तो हमारा यत्न यह है कि हम अपने नियमों में सुधार करें जिससे छोटे किसानों और मार्जिनल फार्मर्स को सहायता मिल सके। इसी प्रकार हमारे यहां जो ऐग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं और दूसरे लोग हैं उनमें बेरोजगारी बहुत है। कल शायद एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हमारे देश में देहात में ढाई करोड़ के करीब आदमी बेरोजगार हैं। वह रोजगार की तलाश में हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता। इसके लिए विशेष कार्यक्रम हमने चलाया। 1971–72 में क्रैश प्रोग्राम फार रूरल एम्प्लायमेंट के सम्बन्ध में 32 करोड़ रुपये खर्च किये गये। चूंकि यह काम देर से शुरु हुआ था, काम के लिये छः महीने बाकी थे, इस लिये थोड़ा काम हुआ। 50 करोड़ रुपये रखे गये थे लेकिन 32 करोड़ रुपये खर्च हुए। लेकिन इसमें 800 लाख मैन डेज लगे। अगर हम इसको 200 से डिवाइड करें तो 4 लाख आदमियों को 200 दिन काम मिला। इस वर्ष हमें आशा है कि 50 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हो जायेगा। पिछले साल का बचा हुआ जो पैसा है वह भी दिया है। यह सब पैसा स्टेट्स को जा चुका है। कुल मिला कर 51 या 52 करोड़ रुपया हो जायेगा। इससे हो सकता है कि यह 800 मैन डेज के बजाय 1200 मैन डेज तक पहुंच जाये।

इसी तरह से कुछ प्रोजेक्टस बने थे इस बात की जांच करने के लिये कि हमारे देश में बेरोजगारी कितनी है। वैसे तो इसके लिये एक कमेटी पहले ही बैठी थी, भगवती कमेटी, लेकिन वह एक सीमित प्रोग्राम था जो हर जिले में चलाया गया था एक हजार आदमियों को दस महीने काम देने के लिये। हम चाहते थे कि इस प्रोग्राम को और बढ़ाया जाये। इसको देखने के लिए कि कितने आदमी हैं जिनको काम मिलना चाहिए, हम ने जांच की। इस के लिये हम ने सारे देश में पन्द्रह प्रोजेक्टस बनाये। हम समझते थे कि एक क्षेत्र में शायद 2800 और 3000 के करीब आदमी पंद्रह साल और उनसठ साल के बीच की उम्र के ऐसे होंगे, जितको काम चाहिए। लेकिन अलग-अलग प्राजेक्टस से हमारे पास जो सूचनायें आ रही हैं, उन से पता लगता है कि एक्चुअली जो लोग काम पर आ रहे हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ड्राउट एफ़ेक्टिड एरिया में बहुत बड़ी सख्या में लोग आये—40 हजार आदमी आये। कहीं 7 हजार आये, कहीं 8 हजार आये, कहीं 15 हजार आये और कहीं 20 हजार आदमी आये। हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम इस अनुभव से लाभ उठा सकेंगे और हम को पता चलेगा कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने दिनों के लिए बेरोजगार हैं, कौन से महीनों में बेरोजगारी ज्यादा होती है, कौन कौन से काम गांवों में चालू किये जा सकते हैं, जिनके द्वारा हम गांवों में ही लोगों को काम दे सकते

हैं और बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हैं, आदि ।

सूखा पीड़ित इलाकों—ड्राउट प्राउन एरियाज—का कार्यक्रम 1970–71 से चालू है । उसके अन्तर्गत सारे देश में 54 जिले चुने गये और उसके लिए 100 करोड़ रुपया—हर जिले के लिए 2 करोड़ रुपया—मख़सूस किया गया । पहले वर्ष में कुछ थोड़ा काम हुआ, लेकिन इन तीन वर्षों में जो काम हुआ है, हमारा अन्दाजा है कि उसमें 100 करोड़ रुपये में से 70 करोड़ रुपये का उपयोग इस साल के अन्त तक हो सकेगा । दिसम्बर, 1972 तक 52 करोड़ रुपया खर्च होने की सूचना तो हमारे पास आ भी चुकी है । उसके बाद के तीन महीनों में काफी तेजी से पैसा खर्च हुआ है । हमारे पास कुछ राज्य सरकारों की यह सूचना आ रही है कि जितना पैसा उनको दिया गया है, शायद वे उससे ज्यादा पैसा खर्च करेंगी । उनकी मांग है कि उनको और ज्यादा पैसा दिया जाये । जो 30 करोड़ रुपया बचा है, वह अगले वर्ष खर्च करना है ।

इस साल कुछ कटौती की बात चल रही है । लेकिन श्री फखरुद्दीन अहमद साहब ने वित्त मंत्री महोदय को पत्र लिखा है कि यह पैसा सूखा-पीड़ित इलाकों के गरीब आदमियों के लिए है, इस लिए उसमें कटौती न की जाये, बल्कि पूरा पैसा दिया जाये, ताकि देश के 54 जिलों के सूखे से दुखी आदमियों को पैसा मिल सके ।

हमारा ड्राई लैंड फार्मिंग का कार्यक्रम भी चल रहा है । उस में भी नये अनुसन्धान हुए हैं कि कौन कौन सी फसल किस किस इलाके में उगाई जा सकती है, ताकि हम थोड़ी बारिश होने पर भी ज्यादा पैदावार कर सकें और उन इलाकों में रहने वाले छोटे किसान अपना जीवन-यापन ठीक ढंग से कर सकें । हमारे ये अनुसन्धान काफी उपयोगी सिद्ध हुए हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने पशु-पालन का भी जिक्र किया है । यह ठीक है कि अगर देश के देहात में बसने वाले करोड़ों आदमियों को कोई रोजगार देना है तो उसका सबसे बड़ा साधन पशु-पालन हो सकता है । इस सम्बन्ध में पशुओं का दूध बढ़ाना, पशुओं की नस्ल सुधारना, बाहर से अच्छे पशु ला कर संकर-प्रजनन की व्यवस्था करना, आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं । लेकिन, जैसा कि श्री मिर्धा ने कहा है, दूध के बेचने और किसान को उसकी ठीक कीमत दिलाने का प्रबन्ध भी करना चाहिए । अगर हम दूध बढ़ाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ायें और उसके बिकने और किसान को ठीक मूल्य दिलाने की चिन्ता न करें, तो फिर हमें सफलता नहीं मिल पायेगी ।

इसी लिए आपेरेशन फ्लड का प्रोग्राम चलाया जा रहा है । हमारे चार बड़े शहरों में रोजाना दस लाख लिटर दूध की खपत होती है । हम चाहते हैं कि उन शहरों में साढ़े सताईस लाख लिटर रोज की खपत हो । हम चाहते हैं कि हम शहरों की खपत को पूरा करें और गांवों के जिन किसानों ने स्माल फ़ार्मर्ज और मार्जिनल फार्मर्ज के कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु लिये हैं, उनको और बड़े शहरों के आस-पास मिल्क शेड एरियाज़ के किसानों

[प्रो० शेरसिंह]

को भी लाभ हो सके। इस लिए साढ़े सताईस लाख लिटर रोजाना दूध के प्रासेसिंग का इन्तजाम करने के लिए डेरी के एक्सपेन्शन का कार्यक्रम चल रहा है। कुछ काम इसी वर्ष चार पांच महीने में पूरा हो जायेगा।

उसके बाद मदर डेरीज के जरिये कोई 14 लाख लिटर और दूध सप्लाई करने की योजना है। उसके लिए भी चारों जगहों पर काम चालू है। हमें उम्मीद है कि अगले साल, 1974 में, ये सब डेरीज बन कर खड़ी हो जायेंगी। हम बाकी शहरों के लिए भी योजना बना रहे हैं।

इन चार शहरों के इर्द-गिर्द दस स्टेट्स के कुछ जिलों में, जो मिल्क शेड एरिया बने हैं, आपरेशन फ्लड के ढंग का हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हम पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में उसको और बढ़ाना चाहते हैं। कानपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, पूना, बंगलौर और हैदराबाद जैसे दस लाख से ज्यादा आबादी के नगरों के आस-पास भी कुछ और जिलों को लेकर, जो मिल्क शेड एरिया हैं, हम पांच छः और काम्पलेक्सिज कायम करना चाहते हैं ताकि हम दूध की पैदावार बढ़ा सकें और उसका मार्केट क्रीएट कर सकें।

इस वक्त हम स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर आयल से जो दूध बना रहे हैं, उसको हम खत्म करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम आगे भी बाहर से स्किम्ड मिल्क पाउडर पर ही अपने देश में दूध का काम चलाते रहें। हम चाहते हैं कि हम अपने देश में ज्यादा दूध पैदा करें और उसके बाद बाहर से स्किम्ड मिल्क पाउडर लाना बन्द कर दें। आपरेशन फ्लड का मतलब यही है कि हम अपने देश में ज्यादा दूध पैदा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्रेश मिल्क पिलायें।

जहां तक फ़ारेस्टस का सम्बन्ध है, श्री मिर्धा ने मैन-मेड फ़ारेस्ट्स के बारे में जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने विशेष रूप से उसका जिक्र किया है। यह ठीक है कि आम तौर पर फ़ारेस्ट्स ऐसे इलाकों में हैं, जहां हमारे आदिवासी और दूसरे गरीब लोग बसते हैं। अगर हम फ़ारेस्ट्स का डेवेलपमेंट कर सकें उनसे आमदनी बढ़ा सकें और उन के एक एक्सपेंशन के काम को आगे ले जा सकें, तो हम अपने आदिवासी लोगों को, उन करोड़ों लोगों को, जो जंगलों में बसते हैं, काम दे सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं।

मैन-मेड फ़ारेस्ट्स की स्कीम में यह सुझाव दिया गया है कि हम सब स्टेट्स में कार्पोरेशन्स बनायें और सारा काम ठेकेदारों को देने के बजाये इंस्टीटयूशनल फ़िनांस की सहायता से फ़ारेस्ट्स से सम्बन्धित सब काम—फ़ारेस्टेशन, फ़ेलिंग, लागिंग, इंडस्ट्रीज के लिए रा मैटीरियल सप्लाई करना और इकानोमिक प्लान्टेशन आदि—उन कार्पोरेशन की मार्फत हो। राज्य सरकारों के पास साधन कम हैं। सब से बाद में फ़ारेस्ट्स का महकमा आता है। जब सब जगह धन बट जाता है, तो मामूली सा पैसा फ़ारेस्ट्स के लिए मिलता है। सैंट्रल बोर्ड आफ़ फ़ारेस्टी ने इस सुझाव को मान लिया है।

SHRI B. N. REDDY (Niryalguda): I am not putting any question. Just I seek a clarification about forests. Is there any proposal before the Government to give cultivable land in the forests to the landless labour as part of the deforestation programme?

PROF. SHER SINGH: No.

SHRI VASANT SATHE (Akola): We want aforestation, not deforestation.

श्री० शेर सिंह : तो फारेस्ट के बारे में यही निवेदन मैं कर रहा था कि फारेस्ट के साधन बढ़ाये जायें, एफारेस्टेशन और ज्यादा हो, हम और ज्यादा एफारेस्टेशन कर के बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हमारी हैं उनको रा मैटीरियल दें और उसका लाभ ट्राइबल लोगों को मिले यह हमारी योजना है ।

वाइल्ड लाइफ का बिल आप ने पिछले दिनों पास किया । उस के ऊपर भी अमल चल रहा है । लेकिन अभी एक टाइगर प्रोजेक्ट 4 करोड़ रुपये का शुरु कर रहे है । 90 प्रतिशत उस का जो पैसा है वह मजदूरी मे लेबर को जायेगा और ट्राइबल लोगों के काम आएगा । वह लेबर इंटेसिव स्कीम है । इस प्रकार फारेस्ट के द्वारा हम ने अन्दाजा लगाया है कि 50 मिलियन मैंने डेज एक साल के अन्दर जो होते है इतना काम हम दे सकते हैं । इसके लिए अगर हम फारेस्ट के काम को आगे चल कर बढ़ाएं तो बहुत सारे ट्राइबेल लोगो को काम दे सकते हैं । यह मैं ने इसलिए निवेदन किया ————(व्यवधान) ....

कुक्कुट पालन का काम हमारे देश में बहुत बढ़ा है । पिछले पांच सात वर्ष में इतने ज्यादा कुक्कुट हो गए और इतने ज्यादा अंडे हो गए कि खाने वाले थक गए है खिलाने वाले, पैदा करने वाले नहीं थके हैं। इन शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय, आप का धन्यवाद करता हूं कि आप ने मुझे समय दिया और यह थोड़े से तथ्य मैंने आप के सामने रखे है ।

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव (कटिहार) : सभापति महोदय, आपने कृषि अनुदान पर बोलने का अवसर मुझे दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । कृषि हमारे आर्थिक जीवन का एक मेरुदण्ड है और हमारी राष्ट्रीय आय का आधा भाग कृषि के उत्पादन पर ही निर्भर करता है । आजादी के गत 25 वर्षों मे कृषि पर जितना चतुर्दिक ध्यान देना चाहिये था उतना नही दिया जा सका । इसके कारण कृषि के उत्पादन में अगर कभी कभी चढ़ाव दिखाई पड़ता है तो फिर गिरावट भी नजर आती है ।

भारत भूमि शस्य श्यामला भूमि, काफी उपजाऊ भूमि रही है । लेकिन आज देश का आधा के अधिक भाग सूखे से ग्रस्त है और बिल्कुल अकाल की काली छाया देश के ऊपर विराजमान है । मैं यह नही कहता कि कृषि मंत्रालय ने कुछ काम नहीं किया । कुछ ऐसे काम उन्होंने किये हैं । कृषि अनुसन्धान में लगे हुये जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने उन्नत किस्म के बीज का आविष्कार करके किसानो को "ग्रो मोर फूड", अधिकतम अन्न उपजाओ, में बहुत बड़ी सहायता प्रदान की है । भारत किसानों ने भी उन्नत

[ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव]

कृषि के ढंग को अपना करके, उन्नत बीज को अपना करके अधिकतम अन्न उत्पादन में अपना योगदान दिया है। यह बात सत्य है कि उन्नत बीजो को छोटे किसानो ने और मध्यमवर्गीय किसानो ने अंगीकार नही किया और अधिकतम अन्न उत्पादन का फायदा देश के बडे बडे किसानो को ही मिला। आज भले ही कृषि मंत्रालय इस बात पर खुशी प्रगट करता हो कि हम कृषि के मामले मे आगे बढे है लेकिन मै कहना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर बडे बडे काश्तकारो ने ही कृषि मे किये गये वैज्ञानिक अनुसन्धानों का, उन्नत बीजो का लाभ उठाया है। फिर भी हम कृषि वैज्ञानिकों और अधिकतम अन्न उत्पादन मे लगे हुये किसानो को बधाई दिये बिना नही रह सकते।

अधिकतम अन्न उत्पादन हो उसके लिये इस बात की आवश्यकता है कि हम उत्तम बीज, खाद और पानी का प्रबन्ध आम किसानों को मुहैया करे। लेकिन आज उर्वरक को ही आप ले लें, विगत पाच वर्षों मे खाद की क्या स्थिति हुई है और इस पर विचार करे तो किसानो को खाद आज से पाच वर्ष पहले जिस कीमत पर मिलती थी क्या उस कीमत पर आज मिलती है? लगभग दुगुनी कीमत पर किसानो को खाद आज मुहैया की जा रही है और साथ साथ जितनी खाद की आवश्यकता है अधिकतम अन्न उत्पादन के लिये उतनी खाद का प्रोडक्शन भी इस देश मे नही हो रहा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि एक ओर खाद के उत्पादन का विस्तार जहा हो रहा है उसके साथ साथ कृषि मंत्रालय इस बात पर भी विशेष ध्यान दे कि ग्रीन मन्योरिंग के लिये किसानों को प्रेरित किया जाय। अपने अनुसन्धान मे लगे वैज्ञानिकों को इस बात के लिये संकेत दे कि ग्रीन मन्योरिंग से भी किसान अपने खेतो की मैन्योरिंग कर सकें उसके ऊपर भी वह ध्यान दे।

दूसरी बात पानी की आती है। पानी के बारे मे सोचते है तो कभी कभी तो हमको इस बात पर काफी चिन्ता और कष्ट होता है कि भारत की नदियो जो वास्तव में वरदान थी वह नदिया आज अभिशाप बन गई हैं। नदियो के कारण कही पर बाढ की स्थिति दिखाई देती है तो कही पर कटाव की स्थिति दिखाई देती है। कई सदस्यों ने आपसे मांग की है कि आपके विभागो मे समन्वय होना चाहिये। मैं तो यह चाहता हूं कि लघु सिंचाई विभाग आप अपने जिम्मे रखें। उसके द्वारा आप किसानो की बहुत सी समस्याओं का समाधान कर सकते है। आज यह नदिया जो अभिशाप बन गई हैं क्या वह वरदान नही बन सकती? क्या नदी किनारो पर छोटे छोटे पम्प बिठाकर आप किसानों के खेतो मे पानी नही पहुचा सकते हैं? क्या नदियो का पानी जो समुद्र में जा कर बेकार गिर जाता है उसका अधिकतम उपयोग नदी के किनारे पर काश्त करने वाले जो छोटे छोटे किसान हैं उनके खेतों मे पानी पहुचा कर आप नही कर सकते? क्या उनके खेतों मे उन नदियो का पानी उठा कर आप नही दे सकते? जरूर दे सकते हैं। अगर सरकार थोडा सा भी ध्यान इस ओर दे तो वास्तव मे इस योजना से किसानो को अधिकतम लाभ पहुचेगा।

बिहार के अन्दर अकाल के इस समय मे थोड़ा सा ध्यान इस बात पर दिया गया है। नदी किनारे पर छोटे छोटे पम्प बीस बीस हार्स पावर के, दस दस हार्स पावर के लगा करके इस सुखाड़ का मुकाबिला बहुत कुछ सरकार ने किया है। उसके लिये भी मैं सरकार को बधाई देता हू और साथ साथ कृषि मन्त्रालय से आग्रह करता हू कि इस प्रकार की एक विशद योजना ले कर आप देश मे चलें तो वास्तव मे आज आप जो तत्काल लाभ चाहते हैं कि अधिकतम उत्पादन हो, उसमे आपको तत्काल लाभ पहुचेगा।

आज देश मे सिंचाई की आपने जो व्यवस्था की है उसमे लगभग 48 करोड एकड भूमि देश के अन्दर कृषि योग्य है जिसमे से केवल 7 25 करोड एकड भूमि मे आप सिंचाई कर सके है। उसने भी आकड़े तो जरूर आपने दिये हैं कि ह ने इतनी भूमि मे सिंचाई की व्यवस्था की है, लेकिन अगर मैं कोसी नहर की ओर कृषि मन्त्रालय का ध्यान आकृष्ट करू तो कोसी नहर के द्वारा जो खेतो की सिंचाई की व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के बारे मे सारे उत्तर बिहार का किसान और खास कर के पूर्णिया और सहरसा जिले के किसान रो रहे हैं। उनकी हालत को देखने वाला कोई नही है। नहरो में पानी नही है उसमे बालू भर गया है। करोडो रुपये खर्च किये गये। बडी सिंचाई योजना के बारे मे लोग हल्ला करते हैं, मैं तो कहना चाहूगा कि आपकी बडी सिंचाई योजना किसानों के लिये कतई कारगर नहीं हो सकती है। उसमे लम्बी अवधि लगती है और पैसा भी ज्यादा खर्च होता है। हमको तो छोटी योजना चाहिये जिससे किसानों के खेत में पानी पहुंच सके। आपने नहरें जो बनाई हैं उसके कमाड एरिया में बहुत बडी भूमि आपने दिखा दी। नतीजा क्या होना है कि किसानों पर इर्रीगेशन टैक्स लग जाता है। आज मैं जिस क्षेत्र से आता हू पूर्णिया और कटिहार अनुमडल का फलका, कोडा, मनिहारी और बरारी क्षेत्र जो हैं वहा का किसान रो रहा है। ऐसे ऐसे किसान को भी इर्रीगेशन टैक्स की नोटिस दी गई है जिनके पास काश्त की जमीन वहा नही हैं और जिनका खेत नहर एरिया से मीलों दूर है जहा एक भी चुल्लू पानी नहर का नही पहुच पाता है। ऐसे किसानों को भी इर्रीगेशन टैक्स की नोटिस दी गई है। अगर इस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था करके आप यह सोचते हैं कि इतने एकड भूमि सिंचित हो गई है तो मैं कृषि मन्त्रालय से अनुरोध करूंगा कि उसका सर्वे वह कराये और तब पता चलेगा कि इस देश की कितनी भूमि सिंचित है और कितनी असिंचित है। इसके बावजूद कृषि के उत्पादन मे हमारे किसानो ने जो योगदान दिया और कृषि मन्त्रालय मे लगे हुये वैज्ञानिको ने जो परिश्रम किया उसके फलस्वरूप 1969–70 मे 6.7 प्रतिशत और 1970–71 मे 7 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परन्तु थोडा सा झोंका प्रकृति के प्रकोप का आया। देश के पूर्वी हिस्से मे थोडी सी बाढ़ की छाया दिखाई दी, उड़ीसा मे तूफान न आ जाय, कही पर ज्यादा जोर की वर्षा हो जाय तो हमारी सारी प्रगति ठप्प हो जाती है। कृषि के क्षेत्र मे 1969–70 से 6 7 तथा 1970–71 मे 7.3 प्रतिशत की जो वृद्धि हमने की थी, वह 1971–72 मे 1.7 प्रतिशत उल्टा

[श्री रामेश्वर प्रसाद यादव]

कम हो गई । इतना ही नहीं, 1972–73 के बारे में आपने जो आर्थिक समीक्षा की है, उसमें इस बात को स्वीकार किया है कि 1972–73 में कृषि उत्पादन की सम्भावनाओं पर मानसून का प्रभाव पड़ा है और वर्तमान संकेतों के अनुसार 1972–73 के कृषि उत्पादन के सूचक अंकों में कमी होना निश्चित सा है । इस बात को आप भी मान कर चलते हैं ।

इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इर्रीगेशन विभाग की भारी भड़कम योजनाओं पर निर्भर न रहें । अपने मंत्रालय को सूखा और भूखा न रहने दें । आज देश की धरती प्यासी है । किसानों को छोटी छोटी योजनाओं के देने से धरती की प्यास बुझ सकती है, उसके द्वारा ही हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, अन्न का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और दुनियां को आप दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से अन्न के मामले में हम अधिकतम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ।

सभापति महोदय, कुछ कानून भी हमारे मार्ग में ऐसे आये हैं, जिनके कारण हमारे कृषि उत्पादन पर गहरा आघात पड़ा है । शुरू शुरू में भूमि सुधार कानूनों का सारे देश में स्वागत किया । जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, गरीबों और भूमिहीन मजदूरों के अन्दर आशा का संचार दिखाई दिया और इस कांग्रेस सरकार ने नारा दिया—'लैण्ड टू दि टिलर्स' । लेकिन आज वह नारा केवल नारा-मात्र ही रह गया है । उसके बाद आपने लैण्ड-सीलिंग की बात उठाई—लेकिन उससे कितनी भूमि किसानों के अन्दर बटी ? आप भूमि की अधिकतम सीमा का जरूर निर्धारण करें—निर्धारण होना चाहिये लेकिन जनसंघ ने मांग की थी कि आमदनी के आधार पर भूमि की सीमा निर्धारित की जाय, आपने हमारे उस सुझाव को ठुकरा दिया है ऐसा मालूम होता है कि सभी जगहों पर एक-से सर्कुलर दे दिये गये—10 से 18 एकड़ तक सीलिंग करो और आज सभी जगह 18 एकड़ का सीलिंग हो रहा है । मैं कृषि मंत्रालय से आग्रह-पूर्वक कहना चाहता हूं—आप थोड़ा सा विचार करें—केरल में रहने वाला काश्तकार जितने कम एकड़ की भूमि की खेती से अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकता है, क्या राजस्थान में उतनी भूमि किसान को दे दी जाय तो वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकता है ? यह टके सेर खाजा, टके सेर भाजी की नीति नहीं चलेगी ।

मैं और मेरी पार्टी चाहती हैं कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाय, लेकिन हम चाहते हैं कि आय के आधार पर उसका निर्धारण किया जाय । हमारे राष्ट्रीय आय का आधे से अधिक भाग कृषि आय पर निर्भर करता है, मैं चाहता हूं कि सारे देश की इकोनोमी 1 और 20 की रेशियो में ले कर चलें —चाहे कृषि उत्पादन क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र हो और उसको 1 और 10 की सीमा में ला कर बांधें । आप दूसरों के लिये इस प्रकार की बात नहीं करते, केवल किसानों के लिये ही इस प्रकार की बातें करते हैं । मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे मिनिस्टरों, बड़े बड़े अफसरों और हमारे राष्ट्रपति की आमदनी का रेशियो क्या है । मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा

रहा हू और न मेरी उनके प्रति कोई दुर्भावना है, लेकिन आप एक ओर विषमता घटाने के लिये लैण्ड सीलिंग की बात करते हैं और दूसरी ओर विषमता पर कोई अकुश नही है । लैण्ड सीलिंग सब चाहते हैं लेकिन उसके लिये एक निश्चित सीमा होनी चाहिये कि 20 साल तक इसमें कोई परिवर्तन नही होगा, यदि कोई परिवर्तन होगा तो 20 साल बाद होगा, जिससे किसान कम से कम आश्वस्त तो हो जाय और अपनी पूजी उस पर लगा सके । लेकिन इस तरह की व्यवस्था आप नही करेंगे । समाजवाद के थोथे नारो से प्रगति के नाम पर विषमता मिटाने के नाम पर बहुत बडी असफलता आपको मिलेगी ।

दूसरी बात मैं कृषि मत्रालय से पूछना चाहता हू—आपकी प्रोक्योरमेट पालिसी क्या है ? आपकी अनाज की वसूली की जो नीति है क्या उसको आपने लक्ष्मण रेखा मे बाध लिया है, क्या उसमे हेर-फेर नही करना चाहते हैं । आपने प्राइस कमीशन बनाया है क्या सत मजिले पर रहने वाले, एयर कण्डीशन मे बैठने वाले आपके अफसरान, आई० सी० एस० आफिसर्स किसानो के दुख दर्द को सुन सकते हैं ? उसमे किसान का प्रतिनिधित्व क्यो नही ? हमारा किसान खलिहान मे खडा होकर धूप के अन्दर जिस प्रकार से दमाही (Thrashing) करता है, मैं समझता हू उस समय हमारे मत्री जी वहा जाय, तो उनको लू लग जायेगी । हमारे एयर कण्डीशन मे रहने वाले अफसरान तो वहा जाने की हिम्मत नही कर सकते—ऐसे लोग हमारी प्रोक्योरमेंट पालिसी का निर्धारण करते हैं, 72—76 रुपए क्विंटल गेहू की कीमत रखते हैं । 1968 के अन्दर जिस पालिसी का निर्धारण किया, वही नीति आज भी चली आ रही है, लेकिन इन पाच वर्षों के अन्दर कृषि के द्वारा उत्पादित होने वाली वस्तुओ, यहां तक कि उद्योगो मे उत्पादित होने वाली वस्तुओ के मूल्यो मे कितना अन्तर आया है—आप इस पर थोडा गम्भीरता से विचार करें । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू कि किसान के साथ उचित न्याय नही हो रहा है । इस बीच मे पानी और बिजली पर कर लगाये गये । इतना ही नही, एक उद्योगपति को अपने उत्पादन को देश के किसी भी भाग मे ले जाने और बेचने की छूट है, यहा तक कि विदेशो मे ले जाकर अधिकतम लाभ कमा सकता है, परन्तु किसान के साथ क्या हो रहा है—आपने जोन बना रखी हैं एक जिले से दूसरे जिले मे भी अपनी उपज को नही ले जा सकता । हम लोग जो गगा और कोसी के दोआब पर रहते हैं, उसको एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते । आपका यह सारे-का-सारा प्रोग्रेसिव कानून केवल किसानो के लिये है ।

आप कृषि उत्पादन को बढाना चाहते है—कृषि क्रियाओ के सचालन मे कितनी अश्वशक्ति की आवश्यकता है । आपकी रिपोर्ट के अनुसार कृषि के विभिन्न क्रिया-कलापो के लिये 12 करोड अश्वशक्ति की आवश्यकता है परन्तु देश मे केवल 4 करोड 50 लाख अश्वशक्ति उपलब्ध है । इसमे दो-तिहाई आठ करोड बैलों द्वारा प्राप्त

[श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव]

होती है, बाकी साढ़े सात करोड़ अश्वशक्ति के लिये आपने क्या कदम उठाये हैं। आपने कहा था कि हम 35 हजार ट्रैक्टर्स मंगायेंगे, 32 हजार का तो नवम्बर तक लदान हो चुका है, ऐसा आपने रिपोर्ट में लिखा है, लेकिन सवाल उठता है कि साढ़े सात करोड़ अश्व-शक्ति की पूर्ति कहां से करेंगे ? क्या छोटे और कम दाम के ट्रैक्टर तैयार करेंगे ?

मैं शेर सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं—उन्होंने पशु-पालन के बारे में कहा है। पशु-पालन के लिये सरकार ने एक योजना को स्वीकार किया और उसके द्वारा छोटे छोटे किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ओर तो पशु-पालन की नीति सरकार ने स्वीकार की है, लेकिन दूसरी ओर जनसंघ ने गत कई वर्ष में मांग की कि गौ-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाया जाय, तो केन्द्रीय सरकार के गले के नीचे वह बात नहीं उतरी—यह दो बातें एक साथ नहीं चल सकतीं—एक तरफ पशु-पालन की बात कही जाय, दूसरी तरफ बूचड़खाने में प्रति दिन गायें कटाई जायं। यह बात समझ में नहीं आती है। देश की एकोनोमी को सुधारने के लिये सीलिंग से सरप्लस लैण्ड को भूमिहीनों में आप कितनी और कब तक बांटेंगे ? बिहार में पहले श्री चन्द्रशेखर सिंह ने कहा कि 20 लाख एकड़ जमीन उपलब्ध होगी और अब कहते हैं कि पांच लाख एकड़ जमीन उपलब्ध होगी। लेकिन पता नहीं उसके बाद 50 हजार एकड़ भी जमीन उपलब्ध होगी या नहीं ? आखिर सीलिंग का फल कौन भोग रहा है ? भोग रहे हैं भोले भाले किसान जिसके घर में कोई मुंशी नहीं है, जिसका परिवार बट चुका है और जिसके घर में 200 मेम्बर हो गये हैं दादा के नाम पर जमीन है। हमारे यहां श्री रघु-वंश नारायण सिंह, जिनके बेटे दिनेश सिंह बिहार में शिक्षा मंत्री हैं उनके पास बिहार में सबसे बड़ी काश्त है, वह सबसे बड़े काश्त-कार हैं लेकिन हैं बड़े समाजवादी, समाज-वादी सरकार के मंत्री हैं। यह समझ में नहीं आता है इसलिये आपकी नीति साफ होनी चाहिये।

थोक व्यापार के बारे में कहकर मैं भाषण समाप्त कर दूंगा। आपने बिड़ला या दूसरे बड़े बड़े उद्योगपतियों के घरानों में चलने वाले जो उद्योग-धंधे हैं उनको लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। थोक व्यापार में किसी का भी एकाधिकार इस देश में नहीं था क्योंकि इस देश में 35 सौ मंडियां हैं और लाखों लोग तिजारत में लगे हुये थे। किसी एक परिवार की उसमें मानोपाली नहीं थी लेकिन अब तो सरकार की मानोपाली हो गई है। गांधी जी की जो सारी की सारी विकेन्द्रीयकरण की योजना थी उसके विरुद्ध सरकार अपने में सभी कुछ केन्द्रित करने जा रही है। नतीजा क्या होगा ? आपने ईंधन भी ले लिया और अब गेहूं भी ले लिया फिर इस देश के 55 करोड़ लोग कहां जायेंगे ? क्या एफ० सी० आई० के बल पर ? एफ० सी० आई० के बारे में पिछले साल लोक सभा में पूरी चर्चा हो चुकी है। मैं उसके भ्रष्टा-चार की एक रिपोर्ट दिल्ली में देता हूं कि डिप्टी मैनेजर जो मरे उनके स्थान पर आपने क्या आदमी दिये। एसोसिएशन में ऐसे तगड़े लोग हैं, ऐसे सक लोग हैं जो

भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हैं। मैं लिवे साहब से कहना चाहता हूं कि कि आप जो यह व्यापार अपने हाथ में लिये हैं उसके स्थान पर क्या आप उस पर अंकुश लगाने के लिये कोई दूसरी विधि नहीं लगा सकते थे? क्या आज एफ० सी० आई० को मार्केट में कम्पीटीशन के तौर पर नहीं ला सकते थे? आप भी रोजगार करते और छोटे छोटे व्यापारियों को भी सौ बोरी तक रखने की छूट देते। कुछ बड़े व्यापारी आपको बहुत खलते हैं या कुछ धनी लोग पाच या दस हजार बोरी रखते थे तो आप सप्लाई विभाग के द्वारा सौ बोरी पर लाकर उनको तिजारत करने देते और साफ साथ एफ० सी० आई० को भी यह काम देते। यदि कभी एफ० सी० आई० ने वर्क टू रूल का नारा दिया और एक हफ्ते तक गोल माल चला तो इस देश के 55 करोड़ लोग भूख से मर मरेंगे। इसलिये आप इस पर पुनः विचार करें। मैं आपसे इस कदम का विरोध नहीं करना चाहता हूं और विवश हो कर मुझे कहना पड़ता है कि आप इस पर पुनः विचार करें। छोटे छोटे दुकानदारों से छीन कर गेहूं व्यापार को एक समाजवादी बढ़ता हुआ कदम बताया जाता है लेकिन आप कितना मुनाफा कमाते हैं? किसान से तो 72 या 76 रुपये में लेते हैं लेकिन स्वयं बेचते हैं फेयर राइस शाप पर 86, 89 या 90 रुपये में।

सभापति महोदय : आप अब समाप्त कीजिये।

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस विषय पर पूर्ण रूप से पुनः विचार करें। आप कम्पीटीशन के रूप में बाजार में आयें।

अब मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं जो अनाज की बर्बादी होती है भंडारण में उसके सम्बन्ध में बतलाना चाहता हूं। 1967 के सर्वे के मुताबिक 93 लाख का नमी और सीलन के कारण नुकसान होता है, 35 लाख चूहे खा जाते हैं।

सभापति महोदय : आप समाप्त कीजिये।

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : 40–50 लाख क्विंटल आप विदेशों से मगा रहे हैं। तो आप भंडारण की अच्छी व्यवस्था करें। इससे बहुत लाभ होगा।

साथ साथ किसान के लिये जो स्माल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स एजेंसियां हैं उनको चुस्त और दुरुस्त करें। मेरा आपसे निवेदन है कि जो देश के बैकवर्ड जिले हैं, जिनको सरकार ने पिछड़ा हुआ घोषित किया है, कम से कम उन क्षेत्रों में ऐसा जरूर करें। स्माल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स के बारे में आपने जो कुछ भी किया है उसके बारे में मुझे कहना है कि साढ़े 70 करोड़ रुपया आपने रखा था लेकिन उसमें से केवल 13 करोड़ ही खर्च किया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप स्माल फार्मर्स एजेंसियां और मार्जिनल फार्मर्स एजेंसियां जो हैं उनको सक्रिय बनायें, सक्षम बनायें ताकि देश के जो छोटे किसान हैं वह उनसे लाभान्वित हो सकें।

श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर

[श्री नरसिंह नारायण पांडे]

मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। हमारे देश का यह बड़ा सौभाग्य है कि हमारा खाद्य मन्त्रालय आज खाद्य मन्त्री के अन्तर्गत है। कृषि में जो उत्पादन बढ़ जाता है तो कृषि के उत्पादन का महत्व होता है। खाद्य मन्त्रालय की गतिविधि बड़ी तेज इस देश में हो गई है। मैं ऐसा समझता हूं कि खाद्य मन्त्रालय और कृषि मन्त्रालय का अलग-अलग अपना स्थान है। कृषि मन्त्री को देश के कृषि के उत्पादन के सम्बन्ध में अपने विचार रखने चाहिए और उसके बाद तत्परता के साथ उसके निराकरण हेतु कोई स्कीम कार्यान्वित करनी चाहिए। यह बात सही है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि यह देश के एक बड़े संकट से गुजर रहा है लेकिन संकट से गुजरने के साथ-साथ हमारे जो मूलभूत साधन हैं उत्पादन के उस क्षेत्र में हमें तरक्की करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए एक आज जो हमारे भूमि सुधार कानून हैं जो सही तरीके से देश के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लाखों करोड़ों जो हमारी गरीब जनता है जिसकी आकांक्षाओं का पालन करने के लिए बनाए गए हैं वह सही रूप से लागू होते हैं या नहीं। जब तक हम मौलिक बातों को नहीं देखेंगे तब तक मैं निश्चित तरीके से कह सकता हूं कि आज जो गरीब झोंपड़ियों में रहते हैं जिनके पास आज अन्न की कमी है, जिनके बच्चे आज अन्न के लिए तरस रहे हैं, जिनके घर में आज चिराग नहीं है उनके लिए हम केवल समाजवादी समाज की रचना का नारा देकर सही तरीके से हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। हमें इसकी तरफ गौर करना पड़ेगा। आज जितने भी भूमि सुधार के कानून बने हैं वह जिलों में जहां के तहां रख दिए गए हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात जानता हूं, अपने प्रदेश की बात जानता हूं कि छोटे किसान पट्टे लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमें बसने के लिए जमीन मिली है, सीलिंग ऐक्ट लागू होने पर जमीन मिली है लेकिन हमें कब्जा नहीं मिल रहा है। कलक्टर से कहा जाता है, मिनिस्टर से कहा जाता है लेकिन किसी तरह से उसका निराकरण नहीं होता। हमें मौलिक तरीके से सोचना पड़ेगा। इस देश में करोड़ों के हितों की रक्षा करने वाली जो हमारी पार्टी है जिसका नारा समाजवादी नारा है उस नारे को अगर हमें सही तरीके से पालन करना है तो आज जो हमारी ब्यूरोक्रैसी का चंगुल है जोकि आज हमारे उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होने देती है उस पर काबू करना होगा। आज भी जिले में जो कलक्टर बैठा है उसको सारी पावर्स दे रखी हैं।

आज उसकी पावर को डीसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। जब तक जिला स्तर पर अधिकारों का डीसेंट्रेलाइजेशन नहीं करते तब तक विकास की गति को जितना तेज करना चाहते हैं, नहीं कर सकेंगे। तो यह मौलिक बात है। आप डीसेन्ट्रेलाइजेशन करें, जिलों में डीसेन्ट्रेलाइजेशन करें, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पोस्ट को वायसराय की पोस्ट न बनाएं। आप जिलों में ऐसी स्थिति पैदा करें जिसमें हम भी ला ऐंड आर्डर के जिम्मेदार हों, पीपुल्स पार्टिसिपेशन जनता का रेप्रेजेन्टेटिव कर सकें। हमसे कहा जाता

है कि पीपुल्स पार्टिसिपेशन करो। लेकिन जिले में हमारी कोई बात नहीं सुनता। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि समाजवादी नीतियां सही तरीके से कार्यान्वित हों तो उसके लिए जरूरी है कि जिला स्तर पर डीसेन्ट्रेलाइजेशन करें, जिला परिषद को पावर दो, ऐग्जीक्यूटिव अथौरिटीज को पावर दो, तभी देश में समाजवादी समाज की रचना कर सकते हैं।

16 hrs.

हमारा देश कृषि प्रधान है। 50 फीसदी आदमी ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहा है। जो 50 फीसदी हमारी नेशनल इनकम को बढ़ा रहा है, जो पचास फीसदी हमारे ऐक्सपोर्ट के साधनों को मुहैया कर रहा है, उसकी हालत क्या है? आज वह किसान कहता है कि कोई ऐसा कमीशन बनाओ जो कि हमारे द्वारा पैदा की गयी चीजो को देखे कि उनकी क्या कीमत होनी चाहिए और वह जिन चीजों का उपयोग करता है एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन मे उन चीजों के क्या दाम होने चाहिए। तो आप पायेंगे कि उसके द्वारा पैदा की गई चीजों के दाम और उसके द्वारा उपयोग में आने वाली चीजो के दाम में बड़ा अन्तर है। फिर कैसे वह प्रोडक्शन बढ़ा सकता है।

यह बात सही है कि सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गयी, एक ऐसा नक्शा बन गया जिसमें हमारे देश का प्रोडक्शन कम हुआ। कुछ प्रदेशों में सूखा पड़ गया और हमें अनाज मंगाना पड़ा। यह देश अजीबो गरीब देश है। यहां कुछ ऐसे वेस्टेड इंटरेस्टस हैं, प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं जो देखती हैं कि कहां सूखा पड़ गया, कब बाढ़ आ जाय और जिस समय बाढ़ और सूखा आ जाता है उस समय चीजों के दाम को बढ़ाते चले जाते हैं। मेरा मतलब कन्ज्यूमर गुड्स से है सरकार को देर नहीं करनी चाहिए। आज सारे उन पदार्थों पर, ऐग्रीकल्चरल गुड्स पर, गेहू के होल-सेल ट्रेड पर जिस तरह आपने कब्जा किया, इसी तरह से जितनी भी कन्ज्यूमर गुड्स हैं उन पर आप को कब्जा करना चाहिए। देर नहीं करनी चाहिए, और इसको ऐम्फेटकली एम्प्लीमेंट करना चाहिए।

आज स्थिति क्या है? होल सेल ट्रेड को आज राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है। मैं उन राजनीतिक लोगों से कहना चाहता हू कि आप देश की अर्थव्यवस्था को जानते हैं, क्या आप की समझ में नहीं आता आज 42 लाख टन अगर शुगर खाने वाले इस देश में हों, और 35 लाख टन का प्रोडक्शन हो तो जाहिर है कि राशनिंग करनी पड़ेगी। इस देश में जब गेहू की पैदावार कम हो रही हो, चावल की पैदावार आबादी की मात्रा में कम हो रही हो, तो इस देश में राशनिंग नहीं होगी तो क्या होगा? और मैं कहना चाहता हू सरकार ने जो निश्चय किया है वह ऐसा निश्चय है कि जिसकी भूरि भूरि प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन हमारे कुछ दोस्त इसको राजनीतिक अखाड़ा बना कर के और चुनाव प्रचार का एक माध्यम बना करके गांवों में जा करके गलत प्रचार कर रहे हैं, और बड़े-बड़े थोक व्यापारियों का प्रचार कर रहे

[श्री नरसिंह नारायण गाडे]

हैं। वह कह रहे हैं कि तुम गल्ला रोक लो, तुम्हें जितने रुपये की जरूरत हो हमसे ले लो। खलिहान में गल्ला आते ही बड़े किसानों से सौदा करना शुरू कर दिया है कि कितने रु० की जरूरत है, कितना गल्ला बेचना चाहते हो, रुपया उनको दे दिया और गल्ला अपने घर में रख लिया। होल सेल ट्रेडर्स यह कर रहे हैं और वह किसानों को रुपया देकर गल्ला उनके यहां होर्ड कर रहे हैं और आपने प्रोग्राम को स्कटिल करना चाहते हैं जिस से आपका प्रोग्राम चल न सके। आप इस बारे में प्रदेश सरकारों को लिखें। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि 31 मार्च तक सारे व्यापारी गोदाम से अपना गल्ला निकाल दें, और अगर उसतारीख तकनहीं निकालेंगे तो उनके खिलाफ़ सरकार कार्यवाही करेगी। मैं जानता हू, 31 मार्च बीत गई, लोगों ने अपना गल्ला नहीं निकाला, लेकिन एक भी होल सेलर अरेस्ट नहीं किया गया। एक को भी जेल नहीं भेजा। मैं जानना हू कि क्यों नहीं भेजा? मैंने एक बड़े अफसर से बात की वह कहता है कि यह तो रोज का तमाशा है जो कानून का बनाया गया है। रोज सरकार के आदेश आया करते हैं। सरकार का होल-सेल ट्रेड को टेक ओवर करने का प्रोग्राम फेल हो जाएगा। और फेल करने के लिए उनका हैंड इन ग्लव्ज है। इस बारे में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं। आपको सोचना चाहिए। आपको प्रदेशों के मुख्य मन्त्रियों को और खाद्य मन्त्रियों को बुलाकर कानफ्रेंस करनी चाहिए कि आखिर इस स्थिति को कैसे सम्भालें। अब कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि इस देश में खाद्यान्न के व्यापार के बारे में मन्त्री जी एलान करें कि जितनी कंज्यूमर गुड्स है सबको नेशनेलाइज करेंगे। आपको स्पष्ट चेतावनी देनी चाहिए कि अगर कोई होल सेल ट्रेडर अपने यहां गल्ला रखता है तो उसको डी० आई० आर में अरेस्ट किया जाएगा। तभी जाकर के आपकी मन्शा पूरी होगी। आज प्रतिक्रियावादी ताकत आपके इस प्रगतिशील कदम का विरोध करने के लिए तैयार हैं और नाना प्रकार की पार्टीयों को मिला करके पोलिटिकल कैपिटल बनाना चाहती है। आपको होशियार होना चाहिए, और इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए।

देश में दूध के उत्पादन की बात कही गई। 280 मिलियन कैटिल इस देश में है और तीन आउन्स डेली हमको दूध मिलता है। इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और सरकार क्या कर रही है कि उन के जो खाने की चीज है वह आप बाहर भेज रहे हैं, और उसके बदले क्या ले रहे हैं? 10 करोड़ रुपए का मिल्क पाउडर मिल रहा है। आपको इस नीति को त्यागना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि देश के अन्दर 3 आउन्स रोज दूध मिले और दूध का उत्पादन बढ़ाया जाए तो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

गरीबों को जमीन कैसे मिले इस पर पर भी विचार करना चाहिए। बहुत सी जमीन एल्केलाइन सोयल है, उस पर आपकी कमेटी की रिपोर्ट आयी है कि उसमें जिप्सम डाले और वह फर्टाइल हो जायगी। इसी तरह जहां एसिडिटी है वहां लाइम डालने के लिए सिफारिश की है जिससे उसे उपजाऊ

बनाया जा सकता है। लेकिन उन सिफारिशों पर कोई अमल नहीं हो रहा है ।

उत्तर प्रदेश में नदियां कहर मचाए हुए है और हर साल 100 करोड़ रुपया बाढ़ में चला जाता है।

आपने बाढ़ के लिए कोई स्कीम बनाई आपने फलड प्रोटक्शन के लिए कोई काम किया? आपने बहुत किया, मैं नही कहता कि कुछ नहीं किया। आपने छितौनी बाध बनाया, नहरें निकाली, लेकिन आज भी जरूरत है राप्ती, घाघरा, कुआनों जैसी नदियो को बाधने की। आज जरूरत है कि एसी नदियों पर बांध हो। जलकन्डो योजना बहुत दिनो से पडी हुई है। उसको लागू करने की जरूरत है। जब तक यह सब चीजें नही होंगी तब तक इस देश में खाद्य-उत्पादन का काम कैसे होगा?

मैं एक चीज का बड़ा विरोधी हूं। आज फर्टिलाइजर के कारखाने खुलते चले जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि कि घर का खाद का कारखाना आप क्यों नहीं मजबूत करते? जो चीज पत्ते से दूसरी चीजों से बनती हैं उनको मजबूत करने के लिए आपने कोई कदम उठाया? कम्पोस्ट को मजबूत करने के लिए आपने कोई कदम उठाया? आप इसके ऊपर भी ध्यान द जिससे हम कम्पोस्ट की खाद को मजबूत कर सकें।

मैं दो मिनट में अपनी आखिरी बात कहना चाहता हूं। शुगर के डेकनेलाइजेशन का सवाल है। चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का मामला हमारे लिए जिन्दगी और मौत की बात हो गई है। चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिए जब हम उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री से मिलते हैं तो वह कहते हैं कि हमने बिल भेज दिया है, वह केन्द्रीय सरकार की झोली में पड़ा हुआ है। जब केन्द्रीय मन्त्री से हम बात करते है तो वह कहते हैं कि रिपोर्ट आ जाने दो, हम तब बात करेंग। एटार्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सब की रिपोर्ट पडी हुई है। कम से कम आज भगवान के लिए यह तो कीजिए कि चीनी मिलों का उद्धार कीजिए पूजीपतियों के पंजे से उनको छुड़ाईये। उनका राष्ट्रीयकरण कीजिए । यह परिस्थिति स्वयं सरकार की कमजोरी की वजह से आई है या क्या है यह तो सरकार के मालिक लोग जान सकते है या मन्त्री जान सकते हैं। अब तक चीनी के मिल मालिक कहते हैं, जिन्होंने मिल को मिक मिल डिक्लेयर किया था, कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं इकट्ठा करके, मिक मिल हमें दे दी जाए, हम चलाएगे। समाजवा के फोरम के लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया, अब उसका भी कंट्राडिक्शन शुरू हो गया है। .मैं कहता हूं कि इसमें कोई समाजवादी फोरम की बात नही है, यह सारी पार्लियामेंट के फोरम को बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को साफ कर देना चाहिए कि जो सिक चीनी मिलले ली गई हैं उनको वापस करने का सवाल नही, चाहे वह करोड़ो रुपया ही क्यों इकट्ठा न कर लें। वह गन्ना किसान के बड़े हमदर्द बन गए हैं, मजदूरों के सबसे बड़े हमदर्द बन गए हैं। लेकिन उनकी हमदर्दी

(श्री नरसिंह नारायण पांडे)

के बारे में किसानो और मजदूरों को मालूम है। हमारी भी हमदर्दी उनके साथ है। इस हमदर्दी की बिना पर मैं कहना चाहता हू कि कभी कभी अखबारो मे मन्त्री महोदय के ऐसे बयान निकलते हैं जिनसे मालूम होता है कि मन्त्री जी भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी सिक मिलो को वापस दे दिया जाए। मैं कहना चाहता हू कि आप ऐसा मत कीजिएगा। चीनी मिलो के बारे मे हमे बडा कटु अनुभव हुआ है। आप चीनी मिलो का राष्ट्रीयकरण कीजिए तो यह किसानो के लिए, मजदूरो के लिए और करोडो पीडित जनता के लिए और मानवता के लिए सबसे बडी देन होगी।

इन शब्दो के साथ मैं इन मागो का समर्थन करता हू।

16 hrs

SHRI M V KRISHNAPPA (Hoskote) Sir, while supporting the Demands for Grants of the Agriculture Ministry I would like to make a few suggestions Out of the ten minutes given to me I would like to devote five minutes for drought and five minutes for wholesale trade on food

In India it is said by people who have long experience in agriculture that taking five years as the cycle in Indian agriculture which is divided as follows out of 5 year cycle one good year, one bad year, one year neither good nor bad and two indifferent years This is a bad year of that circle. It is not uncommon that India will have to face drought quite often

There are repeated droughts in chronically deficit areas about which surveys have been made and reports have been submitted. Yet, there is no earnest attempt to tackle the drought pockets in India in a big way, in a planned way, giving responsibility to a department I am one of those who feel that there should be a separate department for dealing with drought-stricken areas

It is said, one-fifth of India lies in scarcity areas One belt of scarcity starts from Gujarat, passes through Maharashtra and then to Andhra, Karnataka and Telangana and extends upto Ramanathpuram in the south The other belt starts from Gujarat, passes through Rajasthan and parts of eastern U P. districts, like, Deoria, Basti, Gorakhpur and then extends to parts of Bihar As a matter of fact, every district in India has a pocket of scarcity Almost every State has a pocket of scarcity So, one-fifth of India is always scarcity-stricken This is the weakest link in our economy You may have spent crores and crores of rupees and improved agriculture and there may be a green revolution in the valleys and deltas Even though everything is all right in Indian economy, if scarcity starts in these pockets, a scare is created and it has an effect over the prices It is the weakest link in the Indian economy Therefore, it is high time that the Government should take immediate measures and set apart sufficient funds to tackle the situation

There are enough of experiences for us in the world Even in India, in these areas, a coordinated and integrated plan is necessary, as of insurance against famine Then, crop pattern should be changed in these areas Whether there is plenty of rain water in the tank or not, the traditional crop that the farmer grows is paddy in some of these areas Paddy requires four times

water as against maize, jowar or bajra. So, in the same area where the farmer grows traditionally paddy, if he takes to maize, jowar or bajra, he could grow it with the available water and raise a successful crop.

Then, some agro-industries could be developed in these areas. There should be minor irrigation. Preservation of every drop of water is very essential so that failure of rain in one particular year should not make the farmer collapse and he can sustain himself. Some fruits could be grown and processing industries developed in these areas. With a limited amount of water, a lot of horticulture could also be developed. There are certain varieties of fruits, citrus variety and other varieties, which could be developed without much water

In this august House, there was a laughter about poultry-rearing. There was laughter when the Agriculture Minister was talking about poultry. It is such an important thing. In Israel, in one scarcity district, they have developed poultry. They have developed it as a poultry district. There is no or little rain there. But it pays much more than any other district because they have developed poultry there. Poultry is one "tree" that does not require much water or regular rainfall and bears 250 fruits a year. In mythology, there is a story about Kamadenu and Kalpakavriksha. Kamadenu is cow and it gives milk whereas poultry is Kalpakavriksha. No animal that is useful to mankind, either cow or buffalo or sheep or goat, can multiply in such a manner as poultry does. A cow can give you two cows in a year; a buffalo can give you two buffaloes in a year; a sheep can give you two sheep in a year; a goat can give you two goats in a year. But if you take poultry, if there is one hen, it can multiply to 300 in a year. That is why it is like the Kalpakavriksha tree because of its creative capacity or Kalpana—Sakti. Poultry is an important thing. I did not want to mention about it. Since there was laughter about it, since it was taken lightly, I mentioned about it.

Poultry is a very important industry. The Government of India should pay more attention to it. It requires more and more attention. If you want to get protein food, like milk, poultry is the answer. So, in scarcity areas, poultry should be developed to see that the farmer's economy does not collapse if there is failure of rain. There should be a coordinated and integrated plan about it.

Hundreds of crores of rupees are being spent on scarcity relief works. The final figures have not yet come. This year perhaps the Government of India will have to foot a bill to the tune of Rs. 300—400 crores on scarcity relief works

Mysore alone is spending Rs. 50 crores. Maharashtra has spent, I am told, Rs. 60 to 70 crores. Rajasthan has also spent some money. Gujarat is spending Rs. 50 to 60 crores. If all these are totalled, the amount spent this year on scarcity relief would not be less than Rs. 300 to 400 crores. But what type of work has been done? It is all useless and a waste—done temporarily without any plan. Only *kutcha* roads have been constructed. The ringleaders knock away the money, and neither the farmers nor the hard-working labourers are benefited. 'Relief work' means relief to some people and not to the poor people. Therefore, doing these relief workers in a haphazard way should be avoided; there should be an integrated plan. Even if you spend Rs. 300 to 400 crores per year, it does not matter; to develop these pockets, it is very essential.

In Mysore State, things are very bad. In one pocket, in three to four districts, there is continuous famine; nearly 60 lakhs of people come under that. There has been complete failure of rabi and kharif crops and

[Shri M. V. Krishnappa]

people are very much agitated. I request the Food Minister to see that some more foodgrains are sent to that area; otherwise, people will starve. Gulbarga, Bidar, Raichur and Bijapur were growing white jowar, but today because of failure of crop, the people there are starving. There is, therefore, a great need that the Government of India should develop in an integrated and coordinated way the scarcity pockets in India which are the weakest link.

Coming to nationalisation of the wholesale trade, it is said that the Food Ministry has been the graveyard of many reputations....

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): You are a part of it.

SHRI M. V. KRISHNAPPA: I want to give my experience to my successor friend and colleague. I became the Deputy Food Minister when Rafi Ahmed Kidwai was the Food Minister, in 1952 When I entered the Food Department, there was strict and rigorous control, and when I left after ten years, in 1962, we had completely relaxed and people were happy, but that is not the position today. Even after 1962, in Mysore I was in charge of food for five years. With 15 years of experience, I am telling my friend that the wholesale trade take-over by Government is a must because ours is a socialist State. In those days, in 1952, though there was rigorous control, though there was nationalisation of trade, it was not called nationalisation of trade; because of necessity, they had to name it something; under the Defence of India Act they had taken powers to control the entire foodgrains Ours is a socialist State. A number of friends have repeated the importance, why the wholesale trade in foodgrains should be taken over by Government. A great majority of the people of this country are hard-working labourers; most of them are people who spend 80 per cent of their earnings on food. In a country where nearly 80 per cent of the people spend 80 per cent of their income on food, it is very essential that the prices of foodgrains should be kept as low as possible.

When there was control, with my experience in the Food Ministry, I can say, it was hated by every one. Food debate used to be very critical debate; people hated it When we removed it, every one was happy; the grower was happy, the consumer was happy, the trade was happy because there was freedom. but now, in this socialist State, we cannot entrust the whole job to the wholesale merchants. We have tried enough. They generally exploit the farmers in a bumper year and in a scarcity year they exploit the consumers and make huge profits. They want to continue this in spite of ours being a socialist State As I said, this Ministry has been the graveyard of many reputations. It is going to be a very difficult job. When I entered the Ministry 21 years ago, I was hearing less of corruption in the country; but today I hear more of corruption. People do not cooperate now. The wholesale traders will perhaps invest all the Rs. 1,000 or 2,000 crores, which they were investing on foodgrains, on other essential commodities like dhal pulses, oil, etc. and will try to defeat the Government's policy. Most of the Opposition parties are not cooperating with the Government on wholesale trade takeover. With all these difficulties, the Ministry has to see that it is successful. The Food Ministry could raise the reputation of this Government to the Himalayan heights of popularity and they can also take us down to the sea of unpopularity. These two things are possible. So, I wish that they will not take us down to the sea of unpopularity but would take us to the heights of popularity. And, they must be very strict. I am giving you some hints. Having been a Minister for 15 years, I am giving some hints to my friend. Once you said 'controls', it is said

even the gunny bags will start eating. Leave alone others, shortages and deterioration in foodgrains will start. That means that at every stage there is a malpractice, leakage and other corrupt practices and everywhere people indulge in malpractices and leakages occur. Then corruption will increase. They must be strict in dealing with these hoarders and the wholesale merchants, and it should be stricter than it was in the olden days.

Then about prices, the farmers should get remunerative prices. Otherwise, the farmers will start growing other crops. That always happens. If you do not pay the farmer a parity or remunerative price, then he will switch over to chilli-growing in Andhra or jute-growing in Bihar or he would start growing *Chana* in Punjab or groundnuts in Gujarat So, switching over to commercial or cash crops will take place and the Food Mimstiy will very soon be in a soup So, the farmer should be paid a remunerative or parity price. Otherwise, the Food Ministry will very soon come to difficulties

With this little advice to my friend, I once again give a word, not one word of caution, but hundred words of caution, that you must remember that this is an item where Gandhiji said that God appears in the form of food to a poor man. An experienced philosopher once said that the difference between a civilised and an uncivilised man is ten meals. If a civilised man misses two meals, sometimes he will start telling lies for food but if he misses five meals, then he starts telling lies regularly and if he continues to starve and misses ten meals, then he commits a murder. So, the difference between a civilised and an uncivilised man, that philosopher says, is only ten meals. You make a civilised man starve and miss ten meals, then he will become a brute. That is the thing you are handling now. So, do not make these civilised people brutes.

Yesterday, Mr. Vajpayee somewhere has made a statement that food riots will start in the country Food riots not against the Government, food riots will be against those people whom he is supporting—the wholesale traders. People will kill these wholesale traders then they will try to fight against the Government. I may tell Mr. Vajpayee that the riots will be first against the vested interests and then only against the Government.

With these words, I thank you for giving me an opportunity to speak, and I may assure the Food Minister that the next food debate will be as lively as this one.

श्री एस० एस० पूरती (सिंहभूम)

सभापति महोदय, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है । यहां की अधिकाश जनता कृषि पर ही निर्भर करती है और इस देश का वास्तविक विकास भी कृषि के विकास पर ही निर्भर करता है। कृषि के वैज्ञानिक अनुसन्धान सस्थान द्वारा देश मे हरित क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया है । लेकिन जब तक देश के कोने कोने मे इस का प्रचार और प्रसार नही किया जायेगा तब तक कृषि के उत्पादन मे किसी प्रकार की वृद्धि नही होगी और हमें अन्न के लिए दूसरे देशो का मुह ताकना पडेगा । दूसरे देशो से अन्न मंगाने से हमारे देश की क्या हालत हुई है और क्या हालत होगी उस का अन्दाजा अभी हाल की जो घटना घटी है माइलो के आयात के सबध मे उस से लगाया जा सकता है । उस से यह स्पष्ट होता है कि अगर हम अन्न के मामले मे स्वावलम्बी नही है तो दूसरे देश वाले हमें शुद्ध अन्न नही भेजेंगे बल्कि धतूरे के बीज को मिलावट कर के वह हमारे देश में अन्न भेजेंगे जो हमारे लिए विष का काम करेगा । इसलिए हमे चाहिए कि कृषि

[श्री एस०एस० पूरती]

के विकास के लिए पूरा जोर लगाएं और कृषि के विकास के मार्ग में जो भी समस्याएँ हैं उन मौलिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें । हमारी भारत की शस्य श्यामला वसुन्धरा 55 करोड़ लोगों को अन्न देने के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया को भी अन्न देने की सामर्थ्य और क्षमता रखती है । अगर सरकार देश में कृषि की समस्या का निराकरण कर के अन्नोत्पादन में लग जाये ।

आज कृषि उत्पादन के मार्ग में कई समस्याएं हैं । उन समस्याओं में पहली समस्या भूमि वितरण के सम्बंध में है । आज देश में भूमि की असमानता है । किसी के कब्जे में हजारों एकड़ जमीन है तो किसी को खेती के लिए एक इंच भी जमीन नही है । सरकार को यह भारी असमानता दूर करनी पड़ेगी, अन्यथा भूमि के असमानता के साथ साथ आर्थिक असमानता देश मे मौजूद रहेगी सरकार ने भूमि की असमानता को दूर करने के लिए लैंड सीलिंग ऐक्ट भी बनाया । लेकिन लगता है कि वह भी कागज पर ही रहेगा । वह भी सैद्धांतिक ही रहेगा । ऐसे हमारे देश बिहार राज्य में लैंड सीलिंग ऐक्ट को 1962 में ही लागू किया गया था । लेकिन इतने लम्बे समय के पश्चात् भी बिहार राज्य में जो भूमि की असमानता है किसानों के बीच में वह अभी तक मौजूद है । इस से लगता है कि यह लैंड सीलिंग ऐक्ट भूमि की असमानता को सुधारने में सफल नहीं होगा । इस के लिए मेरा अनुरोध है कि जो ऐक्ट आप बनाते हैं उस ऐक्ट को आप सख्ती से अमल में लाएं तभी भूमि मे जो असमानता है उस में सुधार लाया जा सकता है ।

बिहार का दक्षिणी हिस्सा अर्थात् छोटा नागपुर और संथाल परगना पहाड़ों से घिरा हुआ है । प्राकृतिक सुन्दरता वहां है । लेकिन पहाड़ों के निकटवर्ती गांवों में निवास करने वालों का जीवन प्रकृति की सुन्दरता के विपरीत कुरूप सा लगता है । वहां के लोग अन्न के बिना और गरीबी के मारे परेशान हैं । चारो तरफ हाहाकार मच रहा है । वहां उन की आंखों के सामने प्रोटेक्टेड फारेस्ट के अन्दर खेती के लायक जमीन है । लेकिन वह जमीन वैसे ही पडी हुई है । न फारेस्ट डिपार्टमेंट भूमिहीनों को देने का प्रयास कर रहा है और न ही केन्द्रीय सरकार इस संबंध में सही कदम उठा रही है । वहां पर परती पडी हुई जमीन है । उस जमीन को भूमिहीनो के बीच में वितरित किया जाना चाहिए । जंगल के निकट रहने वाले जो वहां के निवासी है वे गरीब है । उन के पास जमीन नही है । अगर वह बेकार पडी हुई जमीन उन के नाम बन्दोबस्त नही होगी तो नतीजा यह होगा कि भूख मे मरता हुआ किसान जगल काटेगा और सैंकड़ो रुपये का माल दस रुपये में बेचेगा । इस तरह से जंगल की बरबादी बहुत जल्दी होगी । किसानों की गरीबी भी दूर नही होगी और असमानता भी दूर नही होगी । इसलिए हमारा अनुरोध है कि जंगलों में खास कर के प्रोटेक्टेड फारेस्ट्स के अन्दर जो बेकार की जमीन पड़ी हुई है वह जमीन भूमिहीन किसानों के बीच में बाट दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

बिहार में जिला स्तर के और प्रखण्ड स्तर के बहुत से सरकारी कृषि फार्म हैं जो बेकार पड़े हुए हैं। असल में इन का लक्ष्य तो होना चाहिए कि उत्तम बीज पैदा करें और किसानों के बीच में वितरण करें, खेती के अच्छे तरीके का प्रदर्शन करें। लेकिन ये कोई भी काम इन फार्मों के द्वारा नहीं होते। बल्कि एक साधारण किसान अपने सीमित साधनों के माध्यम से जितना उत्पादन कर सकता है उतना भी इन फार्मों के द्वारा उत्पादन नहीं हो सकता। इसलिए इस संबंध में भी हमारा अनुरोध है कि जो बेकार पड़े हुए सरकारी कृषि फार्म हैं वह भी भूमि-हीन किसानों के बीच में बांट दिए जायें।

दूसरी समस्या है सिंचाई की। सरकार को और कृषि विभाग को चाहिए कि कृषि के विकास के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए सब से अधिक व्यय सिंचाई पर ही करे। जहां पानी की सुविधा होगी वहां मेहनत करने वाला किसान पत्थर से भी फसल उपजा सकता है। इसलिए पानी के इंतजाम की ओर विशेष ध्यान सरकार का जाना चाहिए। देश में हर जगह नदियां हैं, नाले हैं जो बारिश आने पर ही पानी ले आते हैं। पानी उन में उमड़ पड़ता है और वह पानी बेकार चला जाता है। इतना ही नहीं वह वर्षा का पानी बाढ़ का रूप धारण कर के जान माल को भी खतरे में डालता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जहां नदी, नाले हैं वहां बांध बांधकर और नहरें निकाल कर उस पानी को सिंचाई के काम में ले आए। साथ ही बाढ़ की भयंकरता को भी रोके।

तीसरी बात मैं कृषि ऋण के संबंध में कहना चाहता हूं जो सिर्फ कागजी कार्यवाही तक ही सीमित है। आज देश के किसान अन्नदाता कहे जाते हैं। लेकिन सही रूप में देखा जाय तो ये बिलकुल गरीब हैं। साल भर के खाने के लिए भी अन्न उन्हें मिलता नहीं है। ऐसी हलात में उन्हें उत्तम बीज खरीदने के लिए, हल बैल खरीदने के लिए और खाद खरीदने के लिए समय पर ऋण मिलना चाहिए। सरकार की ओर से जो कृषि ऋण की व्यवस्था है वह अपर्याप्त है और समय पर किसानों को ऋण नहीं मिल पाता। इस के लिए मेरा सरकार से अनु-रोध है कि कृषि ऋण वितरण की जो प्रणाली है वह बिलकुल आसान कर दी जाय और समय पर किसानों को ऋण दिया जाय ताकि वह कृषि विकास के काम में आगे बढ़ सकें।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो गेहूं की कीमत निर्धारित की है वह सही माने में उचित नहीं जचती। हाल में ही पंजाब के दौरे पर हम गए हुए थे जगह जगह किसानों ने बतलाया कि 76 रुपये प्रति क्विंटल अब उत्पादन व्यय के बराबर आ जाता है। उत्पादन में जो व्यय होता है उसी व्यय के बराबर 76 रुपये प्रति क्विंटल है। तो यह देखने की बात है कि जब देश के अन्दर बाजार में दूसरी

[श्री एस० एस० पुरती]

चीजों की कीमत अधिक वृद्धि पर है तो किसान के द्वारा उत्पादन की हुई चीज की कीमत की भी वृद्धि होनी चाहिए और जगह जगह आज किसान माग कर रहे है कि गेहूं की कीमत उचित मिले, गेहू की कीमत सही रूप मे मिले। लेकिन इस ओर सरकार ध्यान नही दे रही है । इस ओर भी सरकार ध्यान दे ।

श्री राम भगत पासवान (रोसेरा) सभापति महोदय, मैं कृषि मन्त्रालय द्वारा प्रस्तुत मागों का समर्थन करने के लिये खडा हुआ हू। हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते इस की आत्मा कृषि में निहित है। कृषि का विकास हमारे हर विकास का आधार-स्तम्भ है। हमारी हरी क्रान्ति तभी सफल होगी जब कृषि में कार्य करने वाले मजदूरो का कृषि पर आधिपत्य होगा। यह ठीक है कि सरकार ने कृषि उत्थान के लिये, खाद्यान्न की वृद्धि के लिये अनेकों उपाय किये है, परन्तु हमारा आर्थिक ढाचा इस प्रकार का रहा है कि इस प्रकार का जो भी लाभ हुआ है वह बडे बडे पूजीपतियो को, भू-स्वामियों को ही मिला है, गरीब और सर्व-साधारण, छोटे तबके के किसान इस लाभ से वचित रहे है। इस प्रकार समाज में आर्थिक समता आने की अपेक्षा आर्थिक विषमता ही फैलती गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भू-स्वामी हैं, जो काश्तकार हैं, उन्हे खेती के अलावा दूसरे व्यापारियों से भी आमदनी है, वे ऊची शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बड़े-बड़े पदों को प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु दूसरी ओर छोटे-छोटे किसानों के बच्चे गरीबी के कारण उचित शिक्षा प्राप्त नही कर सकते, फलत उनके बच्चों के बीच गरीबी की खाई बढती ही जाती है।

विकास के बात से कार्य हुए है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि इस विकास से मजदूरों को क्या मिला ? उनकी मजदूरी आज भी वही है जो पचास साल पहले थी, जो दो सेर अनाज पचास साल पहले मिलता था, वही आज भी मिल रहा है यद्यपि परिवार के सदस्यों की सख्या बढ़ती जा रही है। उनकी मजदूरी को बढाने के लिए आज तक सरकार ने कोई ठोस कदम नही बढाया।

सभापति महोदय, हम देखते है कि कृषि की सबसे बडी त्रुटि आज यह है कि जो खेती करना जानते हैं उनके पास भूमि नही है और जो खेती करना नही जानते, उनके पास हजारो एकड भूमि है। बहुत से ऐसे स्वामी है जो समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हजारो एकड भूमि रखे हुए हैं और इसलिये रखे हुए हैं कि समाज में उन्हे ऊचा समझा जाय। मैं सरकार से आग्रह करता हू कि में दिखला सकता हूं कि सौ एकड़ का एक प्लाट ऐसा पड़ा हुआ है जिस पर पिछले 50 सालों से कभी हल नही चला और अगर कोई गरीब आदमी मागने के लिए जाता है तो देने के लिए तैयार

नहीं, बल्कि उसका खून कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार की विषमता को दूर करने के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

सभापति महोदय, लैंड सीलिंग पास हो गया—बहुत दिनों से ऐसी चर्चा सुन रहा हूं। जब मैं देहातों में जाता हूं तो गरीब लोग मुझ से पूछते हैं कि कब तक जमीन मिलने वाली है, कब तक हम गरीबों की गरीबी दूर होगी ? मैं उसका क्या जवाब दूं ? इसलिए कृषि मन्त्री महोदय से मेरा आग्रह है कि कोई ठोस कदम उठायें इसके लिए कोई निश्चित अवधि मुकर्रर करें कि इतने दिनों के अन्दर जो फाजिल जमीन है, वह गरीबो के बीच बट जायेगी, ताकि उन लोगों को भी सन्तोष हो।

सभापति महोदय, एक शका यह भी है—जब कभी गरीबो को भूमि देने का प्रश्न आता है—पूजीपति और भू-स्वामी बौखला उठते है, यहां तक कि जो लोग पट्टे की जमीन जोतते हैं वह भी उनसे छीन ली जाती है। जब कभी गरीब अपने हक के लिए आवाज उठाता हैं तो कोर्ट में मुकदमा करके उस जमीन को छीन लिया जाता है, यहां तक कि उसे अपने घर की थाली-लोटा को बेचना पड़ जाता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हू कि लैंड सीलिंग से जो फाजिल भूमि निकलेगी, उसका वितरण गरीबों में इस प्रकार से हो कि उसको क्षति न उठानी पड़े। आज हर राज्य के मुख्य मन्त्री को आदेश दें कि सरकार के उच्च-अधिकारियों और पुलिस अफसरों के माध्यम से उन गरीबों को जमीन मिले। अन्यथा पुलिस के इतिहास में यह रिकार्ड है कि जब भी गरीब और अमीर की लड़ाई हुई है पुलिस ने कभी भी गरीबों के पक्ष में फैवरेबिल रिपोर्ट नहीं दी है। इस लिए मेरा आग्रह है कि भूमि-विनरण की जो परिभाषा है, वह साफ-साफ होनी चाहिये तथा बटवारे का असान से आसान तरीका अपनाया जाये ताकि गरीबों को क्षति न उठानी पडे।

सभापति महोदय, अब मैं अपने सूबे बिहार के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। बिहार की भूमि बहुत उपजाऊ है, तीन-चार मील पर नदी बहती है। इन नदियों के उपयोग का प्रयास किया जाय तो यह आशीर्वाद साबित हो सकती हैं, लेकिन दुख है कि इस दिशा में आज तक सरकार ने कोई ठोस कदम नही उठाया, जिसके फलस्वरूप बिहार में कभी अधिक बाढ़ आती है, कभी अधिक सूखा पडता है, इस दुर्भाग्य का सामना वहां को जनता को हर समय करना पड़ता है। किसानो की हालत इस बाढ गौर सूखे के चक्कर में पड़कर दर्दनाक होती जा रही है। इसलिए नदियो से पानी निकालने के लिए सरकार ऐसी व्यवस्था करे, जिससे किसानो को समय पर पानी मिल सके।

मान्यवर, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। सरकार ने खाद्यान्न को तो अपने हाथ में लिया है, अनाज के व्यापार को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन

[श्री राम भक्त पासवान]

अन्न के उपजाने का कार्य अपने हाथ में नहीं लिया। हमारा सरकार से आग्रह है कि हर एक खण्ड में 400 से 500 एकड़ भूमि सरकार एक्वायर करे, जहां सरकार की ओर से वैज्ञानिक ढंग से खेती हो ताकि वहां के स्थानीय मजदूरों को रोजी-रोटी मिले और सरकार को अधिक से अधिक गल्ला प्राप्त होता रहे। इस तरह के फार्म में कुटीर-उद्योगों की स्थापना भी होनी चाहिये। जो कृषि की वस्तुयें हैं उनके द्वारा दूसरा सामान बनाने के कुटीर-उद्योग लगाये जायें।

सभापति महोदय मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं—गरीबों को जमीन दी जायेगी, वह बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में होगी, इसलिए मेरा सुझाव है कि कनैक्टिव फार्मिंग सामूहिक खेती की व्यवस्था होनी चाहिए। समय से उन्हें पानी मिले, खेती के साधन मिले—इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये।

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE (Sangli): I rise not only to support the demands of this Ministry but also to congratulate the Ministers' concerned for their performance during the last few years. I am referring to the drought situation in the country, which was one of the worst in recent history. In some of the areas it was the second or third year in succession. Prompt and effective steps were taken both by the Central as well as the State Governments. They took steps to rush food supplies and to provide drinking water facilities. The emergency agricultural production programme was also undertaken. It was creditable that when faced with such a vast calamity not a single starvation death was allowed to take place in the country and that too without outside help either in the form of concessional imports or gifts of foodgrains or in the shape of funds. The national objective was self-reliance. The nation has fought the natural calamity of such a vast magnitude with its own resources, without any outside help.

I shall now refer to another aspect of the matter. There is a belt which runs through the entire length of our country. People living in that belt look to the skies with uplifted hands and pray for rains. This belt unfortunately runs through the heartland of India. What efforts are being made to change the face of this poverty belt. I know that they will refer to the drought prone area programme. That is being carried on. But I may point out the deficiency in those programmes. To meet the drought situation on a permanent basis and to reduce the severity of drought in areas where drought occurs frequently a programme has been chalked out so that it can be tackled on a permanent basis. That scheme has been launched in 1970 with a provision of Rs. 110 crores. The scheme has to run for four years beginning from 1970-71 and it ends in this year 1973-74. Some selected districts have been chosen on some objective criteria like the incidence of

rain, the pattern of rainfall, the percentage of irrigated area, the frequency of droughts in that area and so on. It has been stated in Annexure VIII of the 'Revised" that there are 54 districts in our country, which have been so selected. I ask whether the purpose for which this particular drought-prone area programme was launched, has been fully achieved. If not, is the Government going to treat such natural calamities as a national responsibility? In order to achieve this objective, is the Government going to include additional areas, which are similarly placed, which are under similar conditions, in the drought-prone area programme?

Six districts of Maharashtra have been selected for inclusion in this particular programme. But there are other areas, which are equally suffering under the same conditions Many districts in Marathwada suffer under similar conditions. There are some adjoining areas in the selected districts also which are similarly situated and which are prone to droughts. Is the Government going to include those areas, not only in Maharashtra but in other States also, in the drought-prone area programme? Secondly, I also want to know whether the Government is going to extend the programme till the end of the Fifth Plan. Results have not been completely achieved.

16.35 hrs.

[DR. SARADISH ROY *in the Chair.*]

No doubt some relief has been given to these areas But, if the programme is to end by the completion of the year 1973-74, then no tangible or concrete results would be achieved Therefore, my suggestion would be to extend this particular programme till the end of the Fifth Plan period. Not only would the extension of timelimit suffice but necessary and requisite funds should also be provided for.

In this connection I may be permitted to read a small portion of the letter that was written to me by Dr. K. L. Rao whom I have asked and also the Agriculture Ministry to include some minor irrigation projects in these drought-prone areas which form part of my District. The particular programme is dealt with by the Agriculture Ministry. And Dr. Rao referred to it. I am quoting him:

> "Further, ten new schemes were sponsored by the Maharashtra Government in August, 1972, which include the three mentioned by you (that means I). "The Ministry of Agriculture have informed the State Government in December, 1972 that it is not possible for them to sanction any more schemes under the programme in question, since the available funds have already been committed."

My submission is that under this programme Rs. 2 crores have been allotted to each District. But, if the need is more and if the demand is genuine, should these considerations be not relaxed? Should not the Finance Ministry be approached to allot more funds to these particular projects in order to achieve concrete and permanent results in those drought-prone areas? There is no other better solution to relieve their distress.

My last suggestion so far as D.P.A.P. programme is concerned is this. Many of my colleagues have spoken regarding the inter-State river water disputes. My suggestion would be that the Agriculture Ministry should take up the matter with the Irrigation and Power Ministry in order to take immediate steps to sanction those irrigation projects. Those irrigation projects which will exclusively benefit the drought-prone areas should be cleared immediately without any condition.

Now I would refer to one more aspect. That is about soil salinity. A serious problem in black soil areas of Maharashtra, Mysore and Andhra Pradesh has been created and more attention should be given to those problems in these three States.

[Shri Annasaheb Gotkhinde]

Regarding taking over of the wholesale trade in foodgrains, my suggestion would be this. The Government now relies on the cooperative sectors so far as distribution machinery is concerned. But, we know and the Government also knows the deficiencies—financial and working deficiencies—of the cooperative sectors. As regards storage and transport facilities, if Government is not going to pay some attention for relieving the difficulties of the cooperative sectors, there will be some trouble. Even today we are witnessing the example of grains allotted to the cooperatives as well as their purchase unions not being lifted purposely simply because funds are not available. They have not even reached the person concerned. These things should be looked into. So far as wholesale takeover of foodgrains trade is concerned, a major decision is taken in the national interest for the transformation of the economy involving the interests of millions of growers and consumers But, I warn the Government that they ought to face the two-pronged attack—the wholesalers who have avowedly declared their intention to non-cooperate with the Government and a section of the Opposition who are warning the Government of food riots They are inciting the people to thwart these important decisions of Government to relieve the difficulties of millions of growers and consumers. But Government should be more careful in dealing with the situation. For example, in Maharashtra these wholesale traders in some districts observed *bandh* on the bazaar day. The intention was that no trade should take place on that particular day and inconvenience should be caused to the common consumer.

17 hrs.

About the credit requirements of agriculture in general, the Minister has given some figures of credit given to the small farmers' development agency. I am quoting two sentences from the Reserve Bank of India's report for the last year:

"The banks are not fully aware of the credit requirements of agriculture." "The growth of advances to agriculture by commercial banks slowed down during the year."

How are we to reconcile the figures given by the Minister and the Reserve Bank's report?

The solution is this: A comprehensive arrangement for long, medium and short term credit is the most important aspect of the whole problem of agricultural development.

Simply because most of the cooperative institutions are facing this difficulty of overdues, the last man who is to get agricultural credit should not suffer. Care should be taken about this Why should not this Government which cares, and rightly so, about the loss of crop in the war-affected areas of Punjab also not care for those States where due to recurring failure of rains consecutively for two to three years the cooperative sector has been brought into trouble? Government should give some special assistance to them to tide over these difficulties. It should be seen that the person in the last rung does not suffer

We are spending crores of rupees on relieving the distress caused by drought. But the Government is not prepared to accept the suggestion of deepening the wells owned by private individuals If that is done, there will be enough production. Even if this expenditure cannot be given as a grant, at least it can be treated as a *taccavi* loan. Government should make a departure and at least in scarcity areas, it should provide funds for developing the wells belonging to private persons.

With these words, I support the Demands.

श्रीमती सहोदरा बाई राव (सागर) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूं और मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहती हूं कि आप ने जो गल्ले का भाव 84 रु० और 76 रु० प्रति क्विंटल रखा है वह ठीक है, लेकिन किसान अगर बैल लेने जाता है तो आजकल एक बैल ढाई हजार रु० का मिलता है, कपड़ा लेने जाओ तो महंगा है। हर एक चीज महंगी है। गल्ला तो आपने सस्ता कर दिया लेकिन किसान तो गल्ले से पैसा कमाता है। किसान की आज बड़ी भारी मरम्मत हो रही है क्योंकि उस पर बैल का कर्जा लगा हुआ है, तकावी का बकाया है, बंधान, खाई का कर्जा लगा हुआ है, ट्रेक्टर का कर्जा लगा हुआ है और लेवी भी देनी है। मैं देहात में गई थी, किसानों ने बड़ी गालियां दी, वे कहते हैं कि बड़े बड़े नेता और छोटे-छोटे नेता कहते हैं कि गल्ले का दाम 84 रु० पर बांध दिया लेकिन यह नहीं उन्होंने देखा कि एक जोड़ी बैल 2,500 रु० में आता है। उनका कहना है कि जब गल्ला सस्ता हो गया तो कपड़ा जो महंगा मिलता है, वह भी सस्ता मिलना चाहिए। तो गल्ले के भाव पर भारत में सारी चीज चलती हैं। जब तक इस दिशा में कदम नहीं उठाएँगे तब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी। गल्ले के भाव के बराबर जब तक व्यापार की चीजें नहीं लायी जाएँगी तब तक देश का विकास नहीं कर सकते।

हमने नारा लगाया था गरीबी हटाएँगे, लेकिन जब मैं देहात में जाती हूं तो किसान लोग कहते हैं कि गरीबी तो दूर रही, जमीन पर सीलिंग लगाने से जो जमीन थोड़ी बहुत निकली भी है, वह भी हमको बांटी नहीं गई। आज किसानों की, खासकर छोटे किसानों की बात मैं कह रही हूं, उनकी हालत यह है कि वे कहते हैं कि सरकार खेती क्यों नहीं ले लेती हाथ में जिससे हम वहीं मजदूरी कर लें। तो जहां जहां जमीनें पड़ी हैं, जिसको गरीबों में बांटना है, जैसे मध्य प्रदेश में है, धौलपुर के पास ग्वालियर में है जंगल की जमीन वन विभाग के पास पड़ी हुई है, उसको अभी तक नहीं बांटा गया है। वैसे तो जमीन कहीं बची नहीं है, लोगों ने कुत्ता के नाम, नाना के नाम, मौसी के नाम, यहां तक कि कुत्तों के नाम बांट दी है जिससे हदबन्दी से बच सकें इसलिए जमीन मिलना मुश्किल है। तो जो कृषि पर निर्भर हैं उसकी तरफ आप देखिए कि कहां सिंचाई नहीं है, कूंआ नहीं है, कहां तालाब बांधना है, कहां नदियां बांधना है, नाले बांधना है। होता यह है जब तक सेशन रहता है आप हमारी बात सुनते हैं, लेकिन देहात की तरफ कोई नहीं जाता, और जब तक आप मौके पर नहीं देखेंगे तब तक उनकी कठिनाइयों का अनुभव नहीं कर सकते और उसके अभाव में कोई काम नहीं कर सकते हैं। हमारे विरोधियों को भी मौका मिल गया, वे कहते हैं कि और दो वोट कांग्रेस को, देखो तुम्हारी जमीन चली गई। जनता में नाना प्रकार के विचार रखते हैं। आज गरीबों को दुकानों से गल्ला नहीं मिलता है जिससे वे भूखों मरने लगते हैं। तो वितरण की व्यवस्था को ठीक कीजिये जिससे हर क्षेत्र में गल्ला मिले।

[श्रीमती सहोदरा बाई राव]

जो आपके कर्मचारी हैं उनको बैठाकर समझाइये कि भ्रष्टाचार न करें क्योंकि देश की हालत को सुधारना है। मैं यह नहीं कहती कि सभी कर्मचारी बेईमान हैं, अच्छे और ईमानदार भी हैं। लेकिन अधिकतर कर्मचारी ऐसे हैं जो 420 करके, दलाल से मिल करके सही काम नहीं होने देते। नतीजा यह होता है कि हम लोग जब अपने क्षेत्रों मे जाते है तो वहां कुछ कार्य नही कर सकते हैं गालियो के मारे।

दूसरी बात यह है कि जैसे आपने बैंक खोले, बैंको का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन उसमें भी बड़ी भारी कमी है। आपको सरकारी मशीनरी के साथ दो, एक, एम० पी० और एम० एल० ए० को भी रखना चाहिए और शहर से बाहर निकल कर 10, 20 मील के फासले पर तम्बू लगाकर किसानों को बुलाकर पैसा दीजिए ताकि किसानों को पूरा पैसा मिल सके। अभी हालत यह है कि जब पटवारी के पास नम्बर लेने के लिए किसान जाता है और कहता है कि हमें पैसा लेने जाना है, तो पटवारी कहता है कि पहले हमे कुछ रिश्वत दो तब नम्बर देंगे, तहसीलदार के पास जाता है तो वह भी कहता है कि 50 रु० से हमारी भेंट पूजा करो। हालत यह है कि जब तक 100-50 रुपया किसान न दे तब तक उसको बैंक से कर्जा नही मिल सकता। ऐसी हालत में यह होता है कि बड़े आदमी तो पैसा ले जाते हैं, लेकिन जो गरीब पैदल चलकर पैसा लेने जाता है उसको पैसा नहीं मिलता वह अगर हजार, दो हजार में से 200 रु० दे दे तो कैसे काम चलेगा।

बैंको की जिम्मेदारी के बारे में हमने अपने क्षेत्र में देखा है। लोग वहां पर बड़े परेशान है। यह हंसने की बात नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि यदि बैंक गरीबों को पैसा देना चाहते हैं तो आप कर्मचारियों को भेजिए और दस मील के एरिये में अपना पाल तानिए। वहां के लोगों को बुलाकर उनके खाते देखिए कि उनके पास कितनी जमीन है। अगर किसी के पास दस एकड़ या पाच एकड़ है तो उसको जमीन मत दीजिए। हरिजन और आदिवासियों को भी जमीन मत दीजिए। यह न सोचिए कि वह नाराज होंगे। आज लोगों के पास चार-चार और छ:-छः एकड़ जमीन है। न तो उसके पास बैल है और न हल है, न साल भर के लिए उनके पास साधन है। अगर उनको जमीन दी जाती है तो जो बगल में बड़े-बड़े किसान है, ब्राहमण और ठाकुर है वह उनसे कहते हैं कि यह जमीन का क्या करोगे, हमसे रुपये लो और जमीन हमको दे दो। वह छोटे छोटे लोग 200 से लेकर 1,000 रु० तक में अपनी जमीनो को बेचकर चले जाते हैं। जब भी आप किसी हरिजन या आदिवासी को जमीन दें तो पहले देख लीजिए कि क्या आप उनको बैल दे सकते है, हल दे सकते है, उनके पास अपने कोई साधन हैं या नही। जब तक साधन न हो तब तक न तो बैल दिए जाएं और न खेत दिए जाएं क्योंकि वहा रोज मुडाफोड़ी होती हैं। बगल वाले बड़े किसान अपने मवेशियों से उनकी फसलें चरा लेते हैं और कभी-कभी कत्ल तक हो जाते हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस वाले भी नहीं सुनते हैं। हवलदार से कहो तो जब तक रुपया

न दो तब तक वह रिपोर्ट नहीं लिखेगा। थानेदार ऊपर से गाली देता है, कोई सुनने वाला नहीं है आदिवासियों की बात।

ऐसी हालत में देश का काम कैसे चलेगा? जब तक आप कड़े कदम नहीं उठाएंगे, नजर नहीं रखेंगे, कृषि मन्त्रालय वाले दौरा नहीं करेंगे तब तक किसानों की समस्या हल नहीं होगी, तब तक किसानों की परेशानी बनी रहेगी। एम० एल० ए० और एम० पी० वहां लोगों की सेवा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में वहां दूसरी पार्टियों के लोगों को मौका मिल जाता है। वह कहते हैं कि जो हमने कहा था कि कांग्रेस को वोट मत दो, उसको वोट देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब लेवी भी देनी पड़ रही है।

मैं कहना चाहती हूं कि आपने गेहूं के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया बड़ा अच्छा किया। आप 84 रुपये के हिसाब से लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो ऊपर की चीजें महंगी हैं रोजमर्रा की, बाजार की, देहात की, शहर की, आने जाने वालों की, खाने पीने की, जब तक आप उनका एक निश्चित भाव नहीं रखेंगे, तब तक देश में खेती की उन्नति बड़ी मुश्किल है। इस वक्त किसान भी आप से नाराज है। उसको कैसे मनाया जाये? जब हम गांवों में जाते हैं तो पांव पड़ते हैं, ब्राह्मण और ठाकुरों को नमस्कार करते हैं। वह कहते हैं कि आखिर यह कैसा राज्य है, कल से खाने को नहीं मिला, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस वाले सुनने वाले नहीं, मिनिस्टर सुनने वाले नहीं...

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : हम सुन रहे हैं।

श्रीमती सहोदरा बाई राय : कोई नहीं सुनता। वहां जाकर आप देखिये तब आप को पता चलेगा।

मैं फिर कहना चाहती हूं कि जो खेत पड़े हैं भूमिहीन लोगों के लिये, जब तक पहले उनको ट्रैक्टर्स से जुतवा न लें, तब तक आदिवासियों को मत दें, भूमि हीनों को मत दें। उनको देने से पहले देखिये कि उनके पास साधन हैं या नहीं। जब तक साधन नहीं होंगे, तब तक वह खेती नहीं कर सकेंगे। फिर आप जमीन कहां देते हैं? जहां पर पत्थर होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होती है, जहां हल नहीं चल सकते। जब ऐसी जगहों पर आप उनको जमीन देते है तब बड़े बड़े लोग रुपयों के बल पर उनसे ले लेते हैं। ऐसी हालत में वे खेती कैसे करें? उनके लिये खेती करना बड़ा मुश्किल हो गया है।

वैसे तो खेती में काफी उन्नति हुई है। हमारे मध्य प्रदेश में अच्छा गल्ला हुआ है। तीन चार प्रदेशों में सूखा पड़ा हुआ है। अगर उनके मवशियो के लिये परेशानी होती है भूसा वगैरह की तो यह मध्य प्रदेश से ले जाते है। वहां काफी गल्ला है, जहां सूखा पड़ा भी वहां राहत कार्य खोले जा रहे हैं। मुझे कोई बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, लेकिन कृषि मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरा कहना है कि जैसे ही सेशन खत्म हो जाये, कुछ दिनों के लिये वह पूरे प्रदेश का दौरा करें और वहां जाकर स्थिति

[श्रीमती सहोदरा बाई राय]

को देखें किसानों को समझायें। वहां पर सारी चीजों की व्यवस्था कराई जाये। स्टाक बनाया जाये। जहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं है वहां पर स्टाक होना चाहिये। फिर वहां बोरे मैदान में पड़े रहते हैं हर एक जगह पर। वहां पर गल्ला रखने की व्यवस्था की जाये। जहां पर किसानों को रुपया नहीं मिल रहा है वहां पर बड़ी परेशानी है, बहुत जल्दी लूट मार होने वाली हैं, यह मुझे दिखलाई पड़ रहा है। देहातों में जाते हैं तो लोग कहते है कि मौसी जी, गल्ला नहीं है, गेहूं नही है, पानी नही है, ट्यूब वैल नही हैं। कुंए नहीं हैं, हरिजनों में भी मतभेद है, ब्राह्मण ठाकुरों से भी उनकी लड़ाई होती है। मैं कहना चाहती हूं कि वहा कुंऐं अलग मे न खुदवाये जायें हरिजनों और ब्राह्मणों के लिये। एक हो कुंआ हो जिसमें से हरिजन भी पानी भरे और ब्राह्मण तथा ठाकुर भी भरें। वहा पर छात्रावास भी अलग अलग न हों। जो छात्रावास अलग अलग लोगो के लिये चल रहे हैं उनको बन्द करवाइये। ऐसे छात्रावास खुलवाइये जिनमें हरिजन और ब्राह्मण सभी के लड़के रहें। अगर ऐसा नहीं होगा तो छुआ छूत बनी रहेगी। जब तक सब लडके एक साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक उनमें भेद बना रहेगा। हम पुराने लोग तो मर जायेंगे छुआछूत वाले, लेकिन नयी पीढ़ी वाले जब तक एक साथ नहीं बैठेंगे तब तक काम नही चलेगा। हजारों सालों से मतभेद चले आ रहे है उनको आपको मिटाना चाहिये।

कृषि मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वह खाली गल्ले पर ही नजर न रखें। हमारे यहां बैठकर वह कमेटी करें, मेम्बरों की मीटिंग करें, वहां प्रधान मंत्री को बुलायें और सारी ऊपर की चीज बतलाये। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक विकास का काम हो पाना कठिन है। रोज लड़ाई झगड़े, होंगे, हड़ताल होंगी। रोज बजाजें बजा करेंगे, कभी जनसंघ आयेगा, कभी स्वतन्त्र पार्टी आयेगी (व्यवधान) .. मैं तो कहना चाहती हूं कि जब हम सही कदम उठायेंगे तो जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी क्या कर सकेगी। जब हमारा ढांचा ढीला नही होगा, गवर्नमेंट ढीली नही होगी तब जनसंघ वाले और स्वतन्त्र पार्टी वाले कुछ नहीं कर सकेंगे।

इसलिये कृषि मंत्रालय सही कदम उठाये, सिंचाई आदि की व्यवस्था करे, बाध हैं, नदियां हैं, नहरें हैं, तालाब हैं, उनकी ठीक व्यवस्था की जाये तभी हमारा काम चल सकता है। हो सकता है कि इसमें दो, चार, दस करोड़ रुपया लग जायें, लेकिन अगले साल वह आ जायगे।

मैं कृषि मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हू और मंत्रालय को बधाई देती हूं कि वह ढीलेपन को दूर कर रहा है।

SHRI BHALJIBHAI PARMAR (Dohad): I would like to speak on the Demands for Grants, but the time available is very limited and, therefore, I will speak on the main subject. I would like to speak on the food problem which the country is facing today. We know that, in most parts of the country, there are drought conditions and famine conditions. In Gujarat, Maharashtra, Rajasthan and other parts of the country, there is acute shortage of foodgrains and grass. People are not getting enough food. In Gujarat

every individual gets two to five kilos monthly which are not sufficient to meet their needs. They are forced to purchase grains from the open market where the rates are very high. They cannot afford to purchase foodgrains from the open market.

The next point is that the daily wages they get from relief works are very limited. They are getting a daily wage of 60 Paise to Rs. 2. That is not sufficient to purchase their daily needs. So, Government should look into this problem very seriously. Government may also think of giving some subsidy on foodgrains so that people can stand on their legs and survive because the conditions are very hard.

Government have been talking of green revolution and white revolution. But, really speaking, we have had no such revolution till now because revolution must be of a permanent nature. Looking to the past Four Five-Year Plan, we see that the expenditure inucrred on agriculture is not adequate. They have not developed forests. When there are no forests, naturally there are no rains. I have seen from the report of the Commission on agriculture that up-till now, in all these 25 years, we have spent only Rs. 210.24 crores on forestry. This is very little. Unless there is development of forests, there can be no development of agriculture. We cannot have regular rains unless we have rich forests and this is the greatest draw-back which we have not till now rectified. So, I request the hon. Minister to look to these problems very seriously.

I have seen that unless we have rich and developed forests in the country, there is no likelihood of regular rains every year and hence agriculture is being affected seriously. Looking to the amount of funds allocated and spent during all the plan periods for development of agriculture and forestry, it does not exceed more than 14.7 per cent and 0.6 per cent respectively in any of the Five Year Plan's total outlay already provided.

Now, we see that India has about 75 million hectares of land under forests which comes to about 22.7 per cent of the total land area. The cultivated area is about 50 per cent of the total geographical area of India. Although the forest area is a little less than half of the cultivated area, the contribution of forestry sector to the gross domestic product is very small and is not commensurate with its potential. The contribution of forestry (forestry and logging) sector to the Gross Domestic Product in 1969-70 was a mere 1.6 per cent while agricultural sector contributed about 46 per cent during the same period. While agriculture and other ancillary activities in 1961 provided employment to 70 per cent of the rural working force, forestry and logging accounted for only 0.2 per cent. The revenue from India's forests so far has also been very negligible. The national average gross revenue per hectare from India's productive forests under the present system of working is only Rs. 21.50.

Then, I come to another aspect. Because of the inadequacy in the development of forestry, we have not enough fodder for our cattle. The cattle die away in these hard days of famine and drought conditions prevalent in the country. For instance, in famine and drought-affected areas of Gujarat, Mysore, Rajasthan and Maharashtra cattle die away because of non-availability of grass. The Government seems to be a silent spectator. The Government should hasten to the rescue of the poor farmers of the country and supply grass and save the valuable cattle wealth of the country. The Government must make a determination to meet this challenge and see that the white revolution is guaranteed by saving the milch cattle. The farmer should be encouraged and enthused to grow more grass on his field and near about rivers with the help of oil engine pumps. The drought-prone area schemes under forestry development must be implemented vigorously so that we can eradicate famine and drought conditions from the country.

I have found in the District of Panch Mahals in Gujarat that this scheme is

[Shri Baljibhai Parmar]

working very nicely. I hope that this forestry development would be extended to other parts of the country also so that we can have a green revolution in the country.

Now, connected with agriculture is the question of water resources. The river Narmada project is pending since long. This matter is pending for a very long time and memorandum after memorandum has been submitted to the Prime Minister. Yesterday also I reminded the Irrigation Minister, Dr. K. L. Rao, but there is no satisfactory reply coming forth. I hope you may kindly do something in the matter and request the Prime Minister so that she may take an immediate decision and give her award because this is a very long-pending problem. We know that without Narmada, there is no scope for development of agriculture in Gujarat. It is a national problem and it will help in solving the food problem of the country. I hope you will kindly look into this matter very seriously.

Now, I come to the soil conservation programme which is carried on in the country. I would like to suggest that this programme which is carried on under drought and famine conditions must be continued on subsidy basis and the farmers should not be forced to pay any dues so that farmers can get incentives. I hope that all these amounts which will be granted by the Centre will be converted as subsidy. I have learnt from the Minister that about Rs. 115 crores will be given to Gujarat and that amount may be treated as subsidy so that the people can be really helped.

Now I come to the food problem. It is very sad that we have not enough buffer stocks of foodstuffs to meet the challenge on the food front. Now we are going to purchase foodgrains to the tune of Rs. 1.50 crores. We are purchasing millions of tonnes of foodstuffs and thereby being indebted to other countries also. Our four five-year plans though implemented are not implemented wholeheartedly and hence there is food shortage and other problems facing the country. These problems can be solved if my earlier suggestions of Forestry Development, supply of electricity, supply of fertilizers at moderate rates to farmers and construction of river dams wherever possible are taken up.

The day to day requirements of the people of the country in the form of foodstuffs are not met. I have found in Gujarat that maize is not at all supplied. Kindly look into this matter and give sufficient stock of maize to the people The poor people are forced to pay the prices in the open market which is beyond their reach There should be proper supply of these coarse grains.

With regard to house sites for rural landless labourers I would like to suggest that the recommendations of the National Commission on Agriculture should be taken up. I have gone through the report of the Commission on Agriculture They have suggested a very good scheme and it is in the interest of agricultural labourers. This scheme may be taken up and implemented seriously. The poor people, the scheduled caste people and adivasis can get the benefit out of this. They have recommended 22.5 crores for provision for house sites for harijans and adivasis. This will really help them and I think they should be encouraged to carry on their business and they can in this way get houses on permanent basis. Government may also make suitable legislation in this connection so that they can have this site on permanent basis and they can also be inherited. A separate Rural Housing Board in each site may be started to supervise the implementation of the programmes and the laying down of general guiding principles.

In the end I would like to suggest that the estimated expenditure amounting to Rs. 76,74,088 thousands should be spent judiciously in order to solve the serious food problem of the country. I expect that the hon. Food Minister Shri F A Ahmed and his colleagues will strive hard to meet the challenges wholeheartedly considering every man, woman and child of this country as their big family members They may try to see God and serve God through these unfortunate half-clad, half-starved millions of people of this vast country

श्री सी० डी० गौतम (बालाघाट) सभापति महोदय, मै प्रस्तुत मागो का समर्थन करना हू । हमारा ध्येय गरीबी और बेरोजगारी हटाना है । हमारे देश मे 100 म 75 आदमी देहात मे रहते है और उन मे 75 मे से 65 गरीब है । 10 प्रतिशत ऐसे होगे जो कि ठीक अवस्था मे है । तो अगर हमारे देहात के लोगो की उन्नति होगी तभी गरीबी और बेरोजगारी हटने वाली है । आज 18 एकड की सीलिंग हो गई है । एक आदमी के अगर पाच लडके है तो तीन तीन चार चार एकड उन के हिस्से मे आने वाला है । उन्हे उस मे अपना गुजारा आगे करना होगा । ठीक है सीलिंग हुई । बहुत अच्छी बात हुई और होनी भी चाहिए । परन्तु जो परिस्थिति सामने आई है वह मैं बताता हू । जब तक कि हम खेती का उत्पादन नही बढाएगे तब तक कोई समस्या हल होने वाली नही है । आज हमारा उत्पादन क्या है ? मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का रहने वाला हू । एक एकड मे 5 क्विंटल धान होता है ज्यादा से ज्यादा मामली तौर से और दो या तीन क्विंटल गेहू होता है । तो यह दो या तीन क्विंटल गेहू जो होता है या पाच क्विंटल धान होता है उस से क्या उन्नति होने वाली है और उस से क्या गरीबी हटने वाली है ? इसलिए जब तक हमारे पास सिचाई के साधन नही होगे, जब तक अच्छा बीज नही मिलेगा बिजली नही मिलेगी और अच्छा उर्वरक नही मिलेगा तब तक कोई उन्नति होने वाली नही है और गरीबी रहने वाली है । सूखा कोई 1971 या 72 म ही पडा हो ऐसी बात नही है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद बीच बीच मे सूखा पडता रहा है । परन्तु हमारी सरकार ने जो टापप्रायरिटी कृषि को देनी चाहिए वह नही दी । अभी तक उन्होने यह महसूस नही किया कि जो यह 100 म 75 देहात के लोग है उन की उन्नति अगर करे तो हम बेकारी भी हटा सकेंगे और गरीबी भी हटा सकेंगे । इस बात को उन्होने महसूस नही किया और इसीलिए टाप प्रायरिटी खेती को उन्होने अभी तक नही दिया । नहीं तो जहा जहा तालाब है उन तालाबो के पानी को खेती के इस्तेमाल मे लाने की योजना सरकार तैयार कर सकती थी । आज भी कई तालाब पडे हुए है जिन की कि दुरुस्ती नही हुई है । आज कई जगह ऊपर से पानी बहता है पहाडो से जिस को कि रोका नही गया है जिस का कि बडा अच्छा इस्तेमाल खेती के लिए हो सकता था और उस मे फसल बहुत बढिया हो सकती थी । लेकिन उस की भी कोई योजना नही है । सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कहते है तो वह कहते है कि यह स्टेट का काम है और स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास फण्ड नही है । इसलिए हम यह सुधार

[श्री सी० डी० गौतम]

नहीं कर सकते । सेंट्रल गवर्नमेंट करती जरूर है, बहुत कुछ उन्नति के काम वह कर रही है, लेकिन मेरा यह कहना है कि टाप प्रायरिटी कृषि को जब तक नहीं देंगे तब तक कोई उन्नति होने वाली नहीं है पूरा मुल्क यह बसा हुआ है देहातों में । इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि दूसरे विभागों को भले ही आप उतनी प्रमुखता न दें, टाप प्रायरिटी न दें, लेकिन ऐग्रीकल्चर को जरूर टाप प्रायरिटी दें ताकि आज जो यह भयंकर समय देखने को मिल रहा है वह दूर हो । हालांकि लोग मरे नहीं हैं, सरकार व्यवस्था कर रही है, लोगों को काम दे रही है, परन्तु स्थिति भयंकर है । पांच पांच मील पर उन्हें काम करने के लिए जाना पड़ता है जो काम आप ने उन के लिए खोल रखे हैं । तो वह उन्हें करना पड़ेगा क्योंकि उन को तो जीना है, अपना पेट भरना है । इसलिए यह टाप प्रायरिटी कृषि को देना बहुत जरूरी है । उस के लिए तालाब खोदने चाहिए, बड़े बड़े बांध बनाए जाने चाहिएं । जो बांध आज बने हुए हैं वह बहुत ही अपर्याप्त है । इस साल तो वर्षा की कमी से बहुत से बांध भी नहीं भरे हैं और इसलिए उन से सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाया । तो यह स्थिति हमारे यहां किसानों की है ।

अब हम ने अभी 76 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का भाव कायम किया है । बाजार में इस के पहले 120 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का भाव था और कहीं कहीं उस से भी ज्यादा था । तो 76 रुपये में किसानों को पूरा पड़ने वाला नहीं है क्योंकि आज खेती पर जो खर्चा होता है वह बहुत ज्यादा होता है । फिर अगर 76 रुपये के भाव से सरकार गेहूं खरीदती है तो उस के मुकाबिले में दूसरी चीजें भी सस्ती हो जायें तब तो ठीक है, उस को पूरा पड़ जावेगा । लेकिन वह स्थिति नहीं है । आज किसान को फर्टिलाइजर लेना पड़ता है, और बहुत सी चीजें उसे खरीदनी पड़ती हैं । आज चीनी का भाव बाजार में 3 रुपये 80 पैसे प्रति किलो है । ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा महंगी हैं । दूसरे जो अपनी कैश क्राप बोते हैं जैसे मूंगफली है, सेब के बागान हैं, आम के बाग हैं, केले हैं इन को तो मनमाना पैसा मिलता है । परन्तु धान और गेहूं का उत्पादन करने वाले जो हैं या ज्वार वगैरह जो भी अनाज पैदा करने वाले हैं उन को बहुत कम पैसा मिलता है । तो थोड़ा सा तुलनात्मक दृष्टि से भी सरकार देखने की कृपा करे और इस ओर ख्याल कर के एक तो सब चीजों के भाव घटाये और या फिर गेहूं का भाव थोड़ा बहुत ऊंचा करे । क्योंकि 76 से 80 रुपये तक जो भाव है उस से पूरा पड़ने वाला नहीं है । हमारे किसान लोग इस से बहुत ही असन्तुष्ट हैं । तो इस पर सरकार ख्याल करे ।

ऋण वगैरह की व्यवस्था के बारे में जो हमारे भाइयों ने बात कही वह बिलकुल सही है । पूरे देश में यह हालत है किसानों को जल्दी ऋण मिलता नहीं है । जो बड़े लोग हैं उन को मिल जाता है । बड़े लोग भी अब छंट गए हैं । 18 एकड़ की सीलिंग के बाद कोई बड़ा रहने वाला नहीं है । हां, जैसा हमारे भाइयों ने

बताया कि किसी ने रिश्तेदारो के नाम अपने कुत्ते के नाम पर या किसी और के नाम जमीन लिख दी है तो वह कुछ रखेंगे, बाकी और बड़े लोग ज्यादा रहे नही हैं। इसलिए खेती की उन्नति के लिए जिन बातों की जरूरत है उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।

अब सीलिंग से जो जमीन निकलेगी मैं अपने गाव की बताता हू कि जो जमीन निकलेगी उस मे से लैण्डलैस जो लोग है मुश्किल से दो चार को दो चार एकड जमीन मिलेगी अगर मिली तो। दो चार एकड मे वह करेगा भी क्या ? एक तो हजार रुपये की बैलो की जोडी वह खरीद नही सकता है न बीज खरीद सकता है न कोई और कोई साधन उस के पास है जिस से खती कर सके। इसलिए बेहतर तो यह होगा कि सरकार उस को साधन उपलब्ध करावे और नही तो फिर ऐसी जो जमीन है उस पर सहकारी खेती कराए और कुछ लोगो को सहकारी खेती के लिए दे दे तो उस मे उन का कुछ भला होगा। सब मिल कर सहकारी खेती करेगे। इसलिये सीलिंग के बाद मे गावो के अन्दर सौ पचास एकड जो भी जमीन उपलब्ध होती है उस जमीन पर सहकारी खेती या सामुदायिक खेती कराई जाय तो कुछ लाभ हो सकेगा और उस मे सरकार जितनी मदद कर सकती है उतनी मदद सरकार को करनी चाहिए।

ऋण के बारे मे जो बात और सदस्यो ने बतायी वह हमारे यहा भी है। सरकार को खास तौर से उस चीज को देखना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरा जिला बालाघाट है मेरे यहा ज्यादातर धान की फसल होती है और बड़े धान के साथ हम लोग उतेरा डालते हैं, अर्थात् उडद, अलसी, लखारी डालते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर के उपयोग की वजह से जमीन इतनी कडी हो जाती है कि उतेरा की रबी की जो फसल होती है, वह ठीक तरह से नही होती। पहले जितनी होती थी उस की आधी भी नही होती। धान ठीक होता है, परन्तु उतेरा ठीक नही होती है। दूसरे हमारे यहा जो पहले फाइन क्वालिटी का चावल पैदा होता था, जैसे चिन्नौर, हीरा-नखी, तुलसी-अमृत, जिस मे बहुत बढिया फलेवर होता था, अब फर्टिलाइजर के उपयोग की वजह से वह फलेवर उड गया है और जो फाइन ग्रेन था वह मोटा हो गया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हू कि वे इस तरफ ध्यान दें और जो उन के अनुसन्धान करने वाले लोग है उन से इस के बारे मे जानकारी प्राप्त करे।

*SHRI A M CHELLACHAMI (Tenkasi) Hon Mr Chairman Sir I rise to say a few words in support of the Demands for Grants relating to the Ministry of Agriculture

Sir, at the outset I would like to quote two Kurals' from the immortal Tamil classic Tirukkural written by the great piet saint Tiruvalluvar. The name of Tiruvalluvar is well-known to all the hon Members o the House I feel it is only appropriate that I should make a reference to Tirukkural which has devoted a chapter on the importance of agriculture in the country

Sir, in one Kural the poet Tiruvalluvar says

SUZHANTRUM AIR PINNATHU ULAGAM UZHANTHUM UZHAVE THALAI ATHANAL

It means Sir that through whatever walks of life the world wanders, it abides in plough therefore with all its hardships, farming is the best anyhow

*The original speech was delivered in Tamil

[Shri A. M. Chellachami]

In another Kural, the poet says:

UZHUVAR ULAGATHARUKKU ANI ATHATRATHU APHUVA-RAI ELLAM ZORUTHU.

This stanza means that the farmers are the lynch-pin of the *ratha* of world's men because they sustain those who do not plough but would stray often.

Sir, the great poet of Tamil, Subramania Bharatiar has stated in a song that the world bows its head to those engaged in agriculture and industry. I refer to these to show how for ages agriculture has been treated with utmost importance in the economic development of a nation. It is needless for me to say that agriculture is really the backbone of our economy We have formulated 5-year plans and have executed 4 such plans We all know that the objectives of planning have been four-fold, namely, (1) economic development (2) to improve gainful employment (3) to improve the living standards of our people and (4) to improve the employment climate in our country. On this basis we formulated the agricultural schemes with a view to achieve green revolution in the country It was our earnest hope that by implementing the agricultural programmes the small farmers would greatly benefit The then Minister for Agriculture, Shri C. Subramaniam formulated a number of meaningful schemes for increasing agricultural production. These schemes went on well for some time but later got into difficulties. The result was, contrary to our expectations, the small farmers did not derive the intended benefits. It is the richer sections of the farming community which exploited these programmes and they grew richer. The small farmers could not take any real advantage under these schemes, Sir, in our country we have "Free for all irrigation system":

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरैना) : सभापति महोदय, इतना अच्छा भाषण चल रहा है, परन्तु सदन में गण-पूर्ति नहीं है ।

MR. CHAIRMAN: Let the bell be rung—Now there is Quorum.

SHRI A. M. CHELLACHEMI: Sir, I was submitting that in our country because of the free for all irrigation system, we find the interests of the small farmers and petty land holders have been grossly neglected. The needs and requirements of these people have not been adequately met. This has been pointed by the Deputy Chairman of Agricultural Commission and presently member of Planning Commission Shri V. Sivaraman in a statement on 27th December 1972. Therefore, Sir, I would appeal to the Government that this matter should be looked into.

Sir, there are as many as five lakh villages in our country and the agricultural labourers from the main bulk of the rural population. Out of these villages in one lakh ten thousand villages no arrangements exist for the supply of pure drinking water In the same manner there is no hospital for 80 per cent of the villagers and the agricultural labour are not covered under any health scheme on all India basis I earnestly appeal to the hon. Minister that these minimum facilities become available to the countless number of agricultural labourers living in the villages.

Sir, I understand that under the scheme of distribution of land to the landless agricultural labourer one lakh acres of land were distributed in West Bengal but as a result of this distribution it appears that nearly 68,000 cases were filed in courts in the State. We have land ceiling laws in operation in our country. Under these Acts, according to statement of the hon. Minister, 10 lakh hectares of

land were acquired as surplus land and 5 lakh hectares were distributed. I would like to know to how many cases of litigation this distribution of land has led.

Sir, according to a report of the National Sample Survey it seems that so far as a result of implementation of agricultural programmes, 15,35,000 persons holding more than 30 acres have only derived large scale benefits and that people possessing 5 acres and less, whose number is about 5.25 crores, have not got even marginal benefits.

Sir, after many years of research in the field of agriculture many new modern methods of farming have been suggested by our agricultural scientists. According to Shri M. S. Swaminathan the Director of ICAR and eminent Agricultural scientist who was given a State Award, if the small farmers were to derive any benefit out of this research then changes in the administrative set up would become very necessary. I wonder in which century one reasonably can hope that these changes would really take place. Sir, it is our painful experience that, the major part of the benefits out of the 5-year plans has gone to the people living in the urban areas. It is always the agricultural labour who suffer immensely as a result of gross neglect of their interests by the State and Central Governments and it is they who are worst hit by the natural calamities like floods and drought. We the politicians call upon these poor agricultural labourer time and again to work hard and increase the production of foodgrains. But, what concern do we show for their welfare? Do we honestly believe that the rich landlords would make increased production possible? We know that it is only the hard working small farmers who can make India prosperous. I would like to say it is not at all desirable to paly politics with these millions of agricultural labourer and small farmers.

Sir, we expected that with he nationalisation of the commercial banks, the small farmers would get easy loan facilities. But, what is the picture we see? These poor small farmers are refused loans by these banks on flimsy grounds when they apply for the purchase of oil engines, pump-sets and cattle. Even if some loans are granted, they go the farmers living near about the urban centres. Several conditions such as that the village should be within a distance of a mile from the office of the bank are imposed which virtually mean that no loans would be given to these farmers. I appeal to the hon. Minister that the situation should be remedied quickly. Sir, the small farmers have not also not benefitted in the least from the Land Development Banks and the Central Cooperative Banks. These Banks only serve the interests of rich and resourceful landlords. In Tamilnadu a number of land development banks are operating under the Central Cooperative Bank. I was myself a Director of one such Bank I know Sir, that political considerations largely dictate the policies of grant of loans to farmers. Mearly because I was in favour of grant of loans, the Tamilnadu Government fearing that my party will become popular among them saw to it that I was removed from the directorship of the Bank. Thus politics dominate the working of these banks This, of course, is not a solidary instance, if I catalogue the misdeeds of the State Government you will all be greatly shocked

The Central Cooperative Bank is supposed to help the farmers to obtain loans for the purchase of fertilisers etc But Sir, only the rich and resourceful farmers get loans from these banks. Even if they default in repayment for three years no action is taken against them. But if the small farmer takes, by chance, the loan he is greatly harassed if he does not repay within a year. Even his property is sought to be attached. Here also discrimination on political considerations prevails.

[Shri A. M. Chellachami]

Sir, coming to irrigation I greatly welcome the proposal to link up Ganges with Caubery, but Sir, so far as Tamil Nadu is concerned it is only Trichy and Tanjore districts which will enjoy the fruits of this scheme, while Madurai, Ramanathapuram, Thirunelveli and Kanyakumari districts will derive no benefits. Therefore, Sir, in order to cover these districts also I would suggest that along with Cauveri, Ganges should be linked up Tambaravarni river also. If that is not possible, atleast dams should be constructed on the rivers, Vadamalaiaru Keeriyaru Kodaimalaiyaru and Thalaiyanai which originates from Western ghats so that these districts get assured irrigation. Sir, rural unemployment has become a serious problem. In Kerala it is 13.3 per cent, in Tamilnadu 7.4 per cent, in Bihar 5.8 per cent and so on. Some immediate effects will have to be taken to solve this problem of rural unemployment.

Sir, before I conclude I would once again appeal to the hon Minister to see that small farmers derive benefits from cooperative banks and nationalised banks, Ganges is linked with Tambravani and also the dam projects on the rivers I earlier referred to are taken up.

With these words I conclude.

SHRI A K M ISHAQUE (Basirhat) Sir, I rise to support the Demands for Grants of this Ministry. I take this opportunity to congratulate the Government on taking over the wholesale trade in foodgrains. If the Government succeed in this venture, they will earn the blessings of the country. We have in this a chance of terminating the perpetual exploitation of the peasants by the non-peasantry. So long we have seen that the small farmers, the marginal farmers and below-marginal farmers have to make distress sales of their produce immediately after the new arrivals. The non-peasants who have the money and the hoarding capacity, purchase the new arrivals at very low prices and hoard them.

18 hrs.

The farmers produce the foodgrains working in the sun and rains and in the mud, but they do not get the fruits of their labour. The non-peasant sophisticated people take overdrafts from banks, buy the foodgrains at low prices, hoard them and sell them later at high prices. So, we see in this takeover of wholesale trade in foodgrains a chance of totally eradicating this perpetual exploitation of the peasants by the non-peasants. Therefore, we would like to see this objective standard as to whether the Government is able to terminate this perpetual exploitation of peasants by the non-peasants. If the Government can ensure a uniform price for foodgrains throughout the year, then and then only we can claim that the policy has been a successful one If they can do that, the Government will earn the blessings of the people in the country. As you know, of the total workers in the country, 43 per cent alone are cultivators.

MR CHAIRMAN: He will continue his speech tomorrow.

18 01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 18, 1973/Chaitra 28, 1895 (Saka).

MGIPND—L—313 LS—11-4-73—1010.